



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24]
No. 24]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 13, 1992/ ज्येष्ठ 23, 1914
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 13, 1992/JYAISTHA 23, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांख्यिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government
of India (other than the Ministry of Defence)

योजना मंत्रालय
(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1992

का.आ.1480—सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953
(1953 का 32) के खंड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय
के दिनांक 18 फरवरी, 1960 के एस.ओ. 462 में भारत
सरकार की अधिसूचना में संदर्भित मामलों से संबंधित
सांख्यिकी संग्रहण के प्रयोजन के लिये क्षेत्र संकार्य प्रभाग,
सांख्यिकी विभाग के निदेशक को "सांख्यिकी प्राधिकारी"
के रूप में नियुक्त करती है तथा निदेश देती है कि उक्त
अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "संयुक्त निदेशक क्षेत्र संकार्य
प्रभाग सांख्यिकी विभाग" शब्दों के लिये "निदेशक,

क्षेत्र संकार्य प्रभाग, सांख्यिकी विभाग" प्रतिस्थापित
किया जायेगा।

[संख्या एम-15011/1/91-प्रशा.-III]

जी.डी. शर्मा, अवसर सचिव

पाद टिप्पणी:—मूल अधिसूचना 18-2-1960 के एस.ओ.
संख्या 462 के माध्यम से प्रकाशित की
गई थी तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा
संशोधन किया गया :

1. एस.ओ. 4249 दिनांक 13-10-1969
2. एस.ओ. 4471 दिनांक 6-12-1968
3. एस.ओ. 1325 दिनांक 26-3-1969
4. एस.ओ. 752 दिनांक 2-2-1971
5. एस.ओ. 1009 दिनांक 17-4-1972
6. एस.ओ. 2335 दिनांक 12-5-1983
7. एस.ओ. 4736 दिनांक 16-12-1983
8. एस.ओ. 2153 दिनांक 18-7-1991

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 22nd May, 1992

S.O. 1480.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Collection of Statistics Act, 1953 (32 of 1953) the Central Government hereby appoints the Director, Field Operations Division, Department of Statistics to be the 'Statistics authority' for the purpose of collecting Statistics relating to the matters referred to in the notification of the Government of India in the Cabinet Secretariat, No. S.O. 462, dated the 18th February, 1960 and directs that the following amendment shall be made in the said notification, namely :—

In the said notification, for the words "Joint Director, Field Operations Division, Department of Statistics", the words "Director, Field Operations Division, Department of Statistics" shall be substituted.

[No. M-15011/1/91-Admn. II]

G. D. SHARMA, Under Secy.

Foot-Notes : The principal Notification was published vide S.O. No. 462, dated 18-2-1960 and subsequently amended by :—

1. S.O. 4249 dated 13-10-1969
2. S.O. 4471 dated 6-12-1968
3. S.O. 1325 dated 26-3-1969
4. S.O. 752 dated 2-2-1971
5. S.O. 1009 dated 17-4-1972
6. S.O. 2335 dated 12-5-1983
7. S.O. 4736 dated 16-12-1983
8. S.O. 2153 dated 18-7-1991

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 1992

सा.का.नि. 1481—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 की धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति एतद्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा, (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) प्रथम संशोधन नियमावली, 1992 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 के शीर्षक "भारी शास्तियाँ" के अन्तर्गत धारा (V) के लिये निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी :—

"(V) धारा (iii-क) में तथा उपर्युक्त के सिवाए, किसी विशेष निर्धारित अवधि के लिये समय-वेतन को

किसी निचले स्तर तक घटाना और साथ ही ये दिशा-निर्देश देना कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसे वेतनमान में स्तरावनत किये जाने की अवधि के दौरान वेतन-वृद्धि अर्जित करेगा अथवा नहीं और यह कि क्या ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर उनके वेतन की भावी वेतन वृद्धि के विलम्बन पर उक्त समय वेतनमान की स्तरावनति का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं।"

[संख्या 11012/4/86-स्था. (क)]

एम.एस. बाली, उप सचिव

टिप्पणी:— प्रधान नियम/आदेश, भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 तथा उपखण्ड (2) में दिनांक 20-11-65 की अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्था. (क) में प्रकाशित किये गये तथा तदनन्तर निम्नलिखित संख्या और तारीखों को संशोधित किये गये :

- | | |
|------|---------------------------|
| 1966 | का.आ. 1149 दिनांक 13-4-66 |
| | का.आ. 1596 तारीख 4-6-66 |
| | का.आ. 2007 तारीख 9-7-66 |
| | का.आ. 2648 तारीख 2-9-66 |
| | का.आ. 2854 तारीख 1-10-66 |
| 1967 | का.आ. 1282 तारीख 15-4-76 |
| | का.आ. 1457 तारीख 29-4-67 |
| | का.आ. 3253 तारीख 16-9-67 |
| | का.आ. 3530 तारीख 7-10-67 |
| | का.आ. 4151 तारीख 25-11-67 |
| 1968 | का.आ. 821 तारीख 9-3-68 |
| | का.आ. 1441 तारीख 27-4-68 |
| | का.आ. 1870 तारीख 1-6-68 |
| | का.आ. 3423 तारीख 28-9-68 |
| 1969 | का.आ. 5008 तारीख 27-12-69 |
| 1970 | का.आ. 397 तारीख 7-2-70 |
| 1971 | का.आ. 3521 तारीख 25-9-71 |
| | का.आ. 249 तारीख 1-1-72 |
| 1972 | का.आ. 990 तारीख 22-4-72 |
| | का.आ. 1600 तारीख 1-7-72 |
| | का.आ. 2789 तारीख 14-10-72 |
| 1973 | का.आ. 929 तारीख 31-3-73 |
| 1974 | का.आ. 1648 तारीख 6-7-74 |
| 1976 | का.आ. 2742 तारीख 31-7-76 |
| | का.आ. 4664 तारीख 11-12-76 |
| 1977 | का.आ. 3062 तारीख 8-10-77 |
| | का.आ. 3573 तारीख 26-11-77 |
| | का.आ. 3574 तारीख 26-11-77 |
| | का.आ. 3671 तारीख 3-12-77 |

- 1978 का.आ. 2464 तारीख 2-9-78
का.आ. 2465 तारीख 2-9-78
- 1979 का.आ. 920 तारीख 17-2-79
- 1980 का.आ. 1769 तारीख 5-7-80
- 1981 का.आ. 264 तारीख 24-1-81
का.आ. 2126 तारीख 8-8-81
का.आ. 2203 तारीख 22-8-81
का.आ. 2512 तारीख 3-10-81

- 1982 का.आ. 168 तारीख 23-1-82
- 1985 अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था. (क)
तारीख 5-7-85
अधिसूचना सं. 11012/5/85-स्था. (क)
तारीख 29-7-85
अधिसूचना सं. 11012/6/85-स्था. (क)
तारीख 6-8-85
अधिसूचना सं. 11012/12/85-स्था. (क)
तारीख 6-12-85
अधिसूचना सं. 11012/8/85-स्था. (क)
तारीख 11-12-85
अधिसूचना सं. 11012/24/85-स्था. (क)
तारीख 26-11-86
- 1987 का.आ. 830 तारीख 28-3-87
का.आ. 831 तारीख 28-3-87
का.आ. 1591 तारीख 27-6-87
का.आ. 1825 तारीख 18-7-87
- 1988 का.आ. 3060 तारीख 15-10-88
का.आ. 3061 तारीख 15-10-88
- 1989 का.आ. 2207 तारीख 16-9-89
- 1990 अधिसूचना सं. 11012/13/89-स्था. (क)
तारीख 30-3-90
का.आ. 2208 तारीख 25-8-90

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 26th May, 1992

S.O. 1481.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) First Amendment Rules, 1992.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, under the heading

"Major Penalties" for clause (V), the following clause shall be substituted, namely :—

"(V) Save as provided for in clause (iii) a), reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government servant will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay."

[No. 11012/4/86-Estt.(A)]

M. S. BALI, Dy. Secy.

Note:

Principal rules/order published vide Notification No. 7/2/63-Estt. (A) dated 20-11-1965.

Subsequently amended by Notification published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub Section (ii) under the following number and date :—

	S. O. No.	Date
1966	1149	13-4-66
	1596	4-6-66
	2007	9-7-66
	2648	2-9-66
	2854	1-10-66
1967	1282	15-4-67
	1457	29-4-67
	3253	16-9-67
	3530	7-10-67
	4151	25-11-67
1968	821	9-3-68
	1441	27-4-68
	1870	1-6-68
	3423	22-9-68
1969	5808	27-12-69
1970	397	7-2-90
1971	35217	25-9-71
	249	1-1-72
1972	990	22-4-72
	1600	1-7-72
	2789	14-10-72
1973	929	31-3-73
1974	1648	6-7-74
1976	2742	31-7-76
	4664	6-7-74
1977	3062	8-10-77
	3573	26-11-77
	3574	26-11-77
	3671	3-12-77
1978	2664	2-9-78
	2465	2-9-78
1979	920	17-2-90
1980	1769	5-7-88
1981	264	24-1-81
	2126	8-8-81
	2203	22-8-81
	2512	3-10-81
	168	23-1-82

- 1985 Notification No. 11012/15/84-Estt.(A) dt. 5-7-1985
Notification No. 11012/5/85-Estt. (A. dt. 29-7-1985
Notification No. 11012/6/85-Estt.(A) dt. 6-8-1985
Notification No. 11012/12/85-Estt.(A) dt. 11-12-1985
Notification No. 11012/24/85-Estt.(A. dt. 26-11-1986

1987	S.O. 830	dated 28-3-1987
	S.O. 831	dated 28-3-1987
	S.O. 1591	dated 27-6-1987
	S.O. 1825	dated 18-7-1987
1988	S.O. 3060	dated 15-10-1988
	S.O. 3061	dated 16-10-1988
1989	S.O. 2207	dated 16-9-1989
Notification No. 11012/13/89-Estt.(A) Dt. 30-3-1990		
1990	S.O. 2208	dated 25-9-1990

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 1992

का.आ. 1482—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/324/89-सी.शु.-8 दिनांक 18-05-1989 को यह निदेश जारी था कि श्री एम. राजेन्द्र ने सपुत्र श्री माधवन नायर, पुथनि परामबिल हाउस, तालावडी, पो. -तिरुवला, केरल को निरुद्ध कर लिया जाये और केन्द्रीय कारागार तिरुवेन्द्रम में अभिरक्षा में रखा जाये ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिये हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, तिरुवेन्द्रम के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/324/89-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1482.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/324/89 CUS. VIII dated 18-05-1989 under the said sub-section directing that Shri M. Rajendran,

S/o Madhavan Nair, Puthenparambil House, Thalavady P.O., Thiruvalla, Kerala State be detained and kept in custody in the Central Prison, Trivandrum with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Trivandrum within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/324/89-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 1992

का.आ. 1483.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/94/91-सी.शु.-8 दिनांक 7-2-91 को यह निदेश जारी था कि श्री गुलाम हुसैन कासम मोरीया, छा छा मुहल्ला, पो. रैंडर, जिला सूरत, गुजरात को निरुद्ध कर लिया जाये और केन्द्रीय कारागार साबरमती में अभिरक्षा में रखा जाये ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो केन्द्रीय विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिये हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अप ने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/94/91-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1483.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/94/91- CUS.VIII dated 7-2-1991 under the said sub-section directing that Shri Gulam Hussain Cassam Moreea, Chha-Chha Mohalla, P.O. Rander, Distt. Surat, Gujarat be detained and kept in custody in the Central Prison, Sabarmati with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Ahmedabad within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/94/91-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 1992

का.आ. 1484-भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/199/91-सी. शु.-8 दिनांक 30-4-1991 को यह निदेश जारी किया था कि श्री ऊधवरास थाडाराम, फ्लैट नं. 605, ड्रीमलैंड अपार्टमेंट, गोल्मैदान पुलिस चौकी के सामने, उल्हासनगर, थाणी, को निरुद्ध कर लिया जाये और केन्द्रीय कारागार बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाये ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिये हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/199/91-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1484.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/199/91-CUS.VIII dated 30-4-1991 under the said sub-section directing that Shri Udhav Thadaram Baharani, Flat No. 605, Dreamland Apartment, Opp. Golmaldan Police Chowki, Ulhasanagar, District-Thane (Maharashtra) be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Maharashtra, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/199/91-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 1992

का.आ. 1485-भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/355/88-सी. शु.-8 दिनांक 16-9-88 को यह निदेश जारी किया था कि श्री एम. खाजा मोहदीन पुत्र श्री मोहदीन, 5, मनी कट्टी स्ट्रीट, कीलायुर इलायांगडी, पसुमपोन मुथुरामलिंगम, तमिलनाडु, को निरुद्ध कर लिया जाये और केन्द्रीय कारागार मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाये ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिये हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मुथुरामलिंगम के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/355/88-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1485.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/355/88-CUS.VIII dated 16-9-1988 under the said sub-section that Shri M. Khaja Maideen, S/o. Maideen, 5, Mani Katti Street, Keelayur Ilayangadi, Pasumpon Muthuramalingam Distt., Tamil Nadu be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person

to appear before the Director General of Police, P. Muthu-ramalingam d.t. within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/355/88-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 1992

का.आ. 1486.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से मशकत किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/20/92-सी.शु.-8 दिनांक 14-1-1992 को यह निर्देश जारी किया था कि श्री मिट्ठालाल हारकचंद जैन उर्फ मिट्ठालाल जैन, सी.-1, आशीश, दूसरा तल, दरवाजा नं. 454, नेपियन सी रोड, बम्बई-400036 को निरुद्ध कर लिया जाये, और केन्द्रीय कारागार बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाये ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने में रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिये हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके।

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मुम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/20/92-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1486.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued under F. No. 673/20/92-CUS.VIII dated 14-1-1992 under the said sub-section that Shri Mithalal Harakchand Jain @ Mithalal Jain, C-1, Ashish, 2nd Floor, Door No. 454 Napeansea Road, Bombay-400 036 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/20/92-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 1992

का.आ. 1487.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से मशकत किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/18/92-सी.शु.-3 तारीख 14-1-92 यह निर्देश देते हुए जारी किया था कि श्री मुकेश कुमार मीना उर्फ चार्ल्स पैट्रिक, चौथा तल, माडोना बिल्डिंग, सेंट जोसेफ रोड, बान्द्रा (प.), बम्बई को निरुद्ध कर दिया जाये और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाये ताकि सामान की तस्करी करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक पुलिस आयुक्त बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/18/92-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1487.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673/18/92-CUS.VIII dated 14-1-1992 under the said sub-section directing that Shri Mukesh Kumar Meena @ Charles Partrick 4th floor Madonna Bldg., St. Joseph Road, Bandra (West), Bombay be decided and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/18/92-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का.आ. 1488.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधि-

नियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप में सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/1/91-सी. शु.-8 तारीख 14-1-91 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री सुरिन्दर पाल सिंह पुत्र श्री सरदार हरनाम सिंह, उ-1/284, पश्चिम विहार, नई दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाये और केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में अभिरक्षा में रखा जाये ताकि सामान की तस्करी करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिसमें उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/1/91-सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1488.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued under F. No. 673/1/91-CUS.VIII dated 14-1-1991 under the said sub-section directing that Shri Surinder Pal Singh, S/o. Sardar Harnam Singh, A-1/284, Paschim Vihar, New Delhi be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from abetting the smuggling of goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/1/91-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का. आ. 1489.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप में सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/88/92/सी. शु.-8 तारीख 25-3-92 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि

श्री धिराज हुसैन, पुत्र रसगीर अब्दुल रहीमान, न्यू हाउस, उदुपीतालुक, माउथ कनारा जिला, कर्नाटक को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बंगलूर में अभिरक्षा में जाए ताकि उसे तस्करी का माल लाने में जाने अथवा उसे छिपाने अथवा उसे रखने के कार्य में निवृत्त रहने के अथवा तस्करी के माल का धंधा करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिसमें उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बंगलूर के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/88/92—सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1489.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/88/92-CUS.VIII dated 25-3-92 under the said sub-section directing that Shri Dhiraj Hussian, S/o. Late Abdul Rehman, New House, Uchila, Udupi Taluk, South Kanara Dist. Karnataka be detained and kept in custody in the Central Prison, Bangalore with a view to preventing him from dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasonable believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bangalore within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/88/92-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का. आ. 1490.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप में सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/372/89/सी. शु.-8 तारीख 20-6-89 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री सरवन सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र श्री धारा सिंह, नं.-13, रेस कोर्स रोड, अमृतसर, पंजाब को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, अमृतसर में अभिरक्षा में जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने में जाने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; आयुक्त, अमृतसर के समक्ष हाजिर हो।

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त अमृतसर के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/372/89-सी. शु.-8]

रूप चंद, अवसर सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1490.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued under F. No. 673/372/89-CUS.VIII dated 20-6-89 under the said sub-section directing that Shri Sarwan Singh @ Bittoo (Aged 23 yrs), S/o. Sh. Dhara Singh, R/o. 13, Race Course Road, Amritsar, Punjab be detained and kept in custody in the Central Jail, Amritsar with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Amritsar within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/372/89-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का. आ. 1491.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/36/91-सी. शु.-8 तारीख 11-1-91 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री जोगेन्द्र सिंह, पुत्र श्री भगवान सिंह, (1) बाली गैराज, 58/5-बी., वी. टी. रोड, चिरिया मोड, कलकत्ता, (2) ग्राम वाराना, पो. ओ. लालपुर, पी. एस. सीरहाली, अमृतसर पंजाब को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेन्सी जेल, कलकत्ता में अभिरक्षा में जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने ले जाने तथा छिपाने के कार्य में लिप्त होने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त अमृतसर के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/36/91-सी. शु.-8]

रूप चंद, अवसर सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1491.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued under F. No. 673/36/91-CUS.VIII dated 11-1-91 under the said sub-section directing that Shri Joginder Singh (Aged 18 yrs.), S/o Sh. Bhagwan Singh, (i) Bali Garrage, 58/5-8, B. T. Rd., Chiria More, Calcutta (ii) Vill. Varana, P. O. Lalpur, P. S. Srihali, Amritsar, Punjab be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting and concealing smuggled goods,

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/36/91-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का. आ. 1492.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और सरकारी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आदेश फा. सं. 673/308/91-सी. शु.-8 दिनांक 24-9-90 को यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री मेथू चन्द्र डे पुत्र श्री बेनोद चन्द्र डे, ग्राम—जिन्जिरा, केरालीगंज, ढाका, बांग्लादेश को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हों।

[फा. सं. 673/308/91-सी. शु.-8]

रूप चंद, अवसर सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1492.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673/308/90-CUS.VIII dated 24-9-90 under the said sub-section directing that Shri Methu Chandra Dey, S/o. Benod Chandra Dey, Vill. Zinzira, Keraniganj, Dhaka, Bangladesh be detained and kept in custody in the Central Prison, Calcutta with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/308/90-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का. आ. 1493.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/286/91—सी. शु.-8 दिनांक 25-6-91 को यह निदेश जारी किया गया था कि श्री अब्दुल जलील अब्दुल हमीद खान, 161, सी. 9, पिरिन्सीन भवन, पहला तल, 169, ईब्राहिम रहमतुल्ला रोड, बम्बई-400 003 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हों।

[फा. सं. 673/268/91-सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1493.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/286/91-CUS. VIII dated 25-6-1991 under the said sub-section that Shri Abdul Jalil Abdul Hamid

1370 GI/92—2

Khan, 161, C-29, Princess Building, 1st Floor, 169, Ibrahim Rahimtullah Road, Bombay 400003, be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/286/91-CUS.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का.आ. 1494.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/287/91-सी. शु.-8 दिनांक 25-6-91 को यह निदेश जारी था कि श्री अब्दुल गनी अब्दुल हमीद खान, 161, सी-29, प्रिन्सेस बिल्डिंग, पहला तल, इब्राहिम रहमतुल्ला रोड, बम्बई-400 003 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हों।

[फा. सं. 673/287/91-सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1494.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/287/91-CUS.VIII dated 25-6-1991 under the said sub-section directing that Shri Abdul Gani Abdul Hamid Khan, 161, C-29, Princess Building, 1st floor, Ibrahim Rahimtullah Road, Bombay-400003 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/287/91-CUS.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का.ग्रा. 1495:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1973 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/162/90-सी.शु.-8 दिनांक 22-6-90 को यह निदेश जारी था कि श्री के. सदाकथुला पुत्र स्वर्गीय श्री सैयद मोहम्मद, मलिक मोहम्मद, लिब्बा हाउस, तिरुविदामकोड पो. कन्याकुमारी, जिला, तमिलनाडु को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/162/90-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवसर सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1495.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/162/90-CUS. VIII dated 22-6-1990 under the said sub-section directing that Shri K. Sadakathulla, S/o Late Sh. Syed Mohd, Malik Mohd. Lebba House, Thruthancode P.O., Kanyakumari distt., Tamil Nadu, be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/162/90-CUS.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का.ग्रा. 1496:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/678/89-सीमा शुल्क 8 दिनांक 23-11-89 को यह निदेश जारी था कि श्री मोहम्मद मीरा लीबिया, (1) 32, पहला फेज, टी.पी. कोली स्ट्रीट, ट्रिप्लीकोन, मद्रास-5 (2) 105, नॉर्थ स्ट्रीट, किलाकारी, रामनाड जिला, तमिलनाडु को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हाजिर हों।

[फा.सं. 673/678/89-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवसर सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1496.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/678/89-CUS. VIII dated 23-11-1989 under the said sub-section that Shri Mohammed Meera Lebbai, (i) 32, 1st Lane, T.P. Koil Street, Triplicane, Madras-5, (ii) 105, North Street, Kilakarai, Ramnad Distt., T.N. be detained and kept in custody in the Central Jail, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/678/89-CUS.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का.ग्रा. 1497:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा

(1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/288/91-सी. शु.-8 दिनांक 25-6-92 को यह निदेश जारी था कि श्री अब्दुल आरिफ अब्दुल हामिद खान, 161, प्रिन्सिपल भवन, तीसरा तल, ईब्राहिम रहिमतुल्ला रोड, बम्बई-400003 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अथ केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हों।

[फा.सं. 673/288/91-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1497.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/288/91-CUS. VIII dated 25-6-1992 under the said sub-section that Shri Abdul Arif Abdul Hamid Khan, 161, Princess Building, 3rd Floor, Ibrahim Rahimtulla Road, Bombay-400003, be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/288/91-CUS.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

बैंकिंग प्रभाग

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.प्रा. 1498:—बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों पर घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबन्ध, हुसन जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., हुसन (कनटिक राज्य)

पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से 30 जून, 1994 तक लागू हों होंगे।

[संख्या एफ 6-2/92-ए.सी.]

पी.के. तेजयान, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1498.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section 1 of Section 11 of the said Act shall not apply to the Hassan District Cooperative Central Bank Ltd., Hassan (Karnataka State) from the date of publication of this Notification in the Official Gazette to 30 June 1994.

[F. No. 6(2)/92-AC]

P. K. TEJYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 1992

का.प्रा. 1499:—भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री रशीद जिलानी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक को भारतीय निर्यात आयात बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में मनोनीत करती है।

[संख्या एफ-7/4/92-बी ओ-1]

एम.एस. सीतारामन, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1499.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (e) of sub-section (1) of section 6 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government hereby nominates Shri Rashid Jilani, Chairman and Managing Director, Punjab National Bank, New Delhi, as a Director of the Board of Directors of the Export-Import Bank of India.

[F. No. 7/4/92-BO.1]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 1992

का.प्रा. 1500:—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में "मगध विश्वविद्यालय शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

डा. एम.जी.प्रार. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, मद्रास

1. बैचलर ऑफ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी एम.बी.बी.एस.

2. डिप्लोमा इन प्राथोटेटिक्स एण्ड गायनिकालोजी	डी.जी. प्रो.	36. डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ	डी. पी. एच.
3. डिप्लोमा इन प्राथोटेटिक्स	डी. प्रार्थी.	37. डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग)	एम.डी. (प्र.वि. स्त्री रोग)
4. डिप्लोमा इन विनिरिलोजी	डी.डी.	38. डिप्लोमा इन फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहबिलिटेशन	डी.पी.एम. एंड आर.
5. डिप्लोमा इन ड्र.मेटोनाजी	डी.डी.	39. डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन	डी.एच.ई.
6. डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी.सी.एच.	40. डाक्टर आफ मेडिसिन (चिकित्सा चिकित्सा)	एम.डी. (चि.चि.)
7. डिप्लोमा इन आफस्वेमोलोजी	डी.प्रो.	टिप्पण. ये प्रस्ताव केवल तब मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान प्रस्ताव होंगी जब निम्नलिखित तारीख को या उसके पश्चात अनुदत्त की जाती हैं :	
8. डिप्लोमा इन ग्रनैस्पीसियोलोजी	डी.ए.	एम.बी.डी.एस. डिग्री	मार्च, 1992 से
9. डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी ऑप्टी	डी.एम.आर.टी.	स्नातकोत्तर डिग्री	मार्च, 1990 से
10. डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलोजी डाइग्नोसिस	डी.एम.आर.डी.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	मार्च, 1989 से
11. डिप्लोमा इन क्लिनिकल पथोलोजी	डी.पी.पी.	[सं. बी-11013/58/88-एम ई (यू.जी.)]	
12. डिप्लोमा इन सायकनोजीकल मेडिसिन	डी.पी.एम.	आर. विजयाकुमारी, डेस्क ऑफिसर	
13. डिप्लोमा इन आर्टोरोलिनजोलोजी	डी.एल.आर.	MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE	
14. डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	एम.डी. (सामान्य आयुर्विज्ञान)	(Department of Health)	
15. डिप्लोमा इन टुबरकुलोसिस चेस्ट डिसेजिज	डी.टी.सी.डी.	New Delhi, the 20th May, 1992	
16. डाक्टर ऑफ मेडिसिन (रति रोग)	एम.डी (रति रोग)	S.O. 1500.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:—	
17. डाक्टर आफ मेडिसिन (सब रोग)	एम.डी संवेचना)	In the First Schedule to the said Act, after the heading "Magadh University" and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted, namely:—	
18. डाक्टर आफ आयुर्विज्ञान (बाल चिकित्सा)	एम.डी. (बाल वि.)	DR. M.G.R. MEDICAL UNIVERSITY, MADRAS	
19. डाक्टर आफ आयुर्विज्ञान (चिकित्सा विज्ञान)	एम.डी. (चि.वि.)	1. Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. M.B.B.S.	
20. मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	एम.एस (सामान्य शल्य विज्ञान)	2. Diploma in Obstetrics and Gynaecology D.G.O.	
21. मास्टर आफ सर्जरी (का. ना. क.)	एम.एस० (का. ना. क.)	3. Diploma in Orthopaedics D. Orth.	
22. मास्टर आफ सर्जरी (अस्थि विज्ञान)	एम.एस. (अ.वि.)	4. Diploma in Venerology D.V.	
23. डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषजगुण विज्ञान)	एम.डी. (भे.वि.)	5. Diploma in Dermatology D.D.	
24. डाक्टर आफ मेडिसिन (तंत्रिका विज्ञान)	डी.एम. (तंत्र.वि.)	6. Diploma in Child Health D.CH.	
25. डाक्टर आफ मेडिसिन (हृदय रोग विज्ञान)	डी.एम. (हृ.वि.)	7. Diploma in Ophthalmology D.O.	
26. मास्टर आफ सर्जरी (बाल शल्य चिकित्सा)	एम.सी.एच. (बा.श.चि.)	8. Diploma in Anaesthesiology D.A.	
27. मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य चिकित्सा)	एम.सी.एच. (प्ला.श.चि.)	9. Diploma in Medical Radiology Therapy D.M.R.T.	
28. मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका शल्य चिकित्सा)	एम.सी.एच. (तंत्र.श.चि.)	10. Diploma in Medical Radiology Diagnosis D.M.R.D.	
29. मास्टर आफ सर्जरी (जरीर रचना विज्ञान)	एम.सी.एच. (श.र.वि.)	11. Diploma in Clinical Pathology D.C.P.	
30. मास्टर आफ सर्जरी (जैनिटो-प्रसूति-सर्जरी)	एम.सी.एच. (जैनिटो-प्रसूति-सर्जरी)	12. Diploma in Psychological Medicine D.P.M.	
31. मास्टर आफ सर्जरी (शारीरिक सर्जरी)	एम.सी.एच. (शारीरिक सर्जरी)	13. Diploma in Oto Rhino-Laryngology D.L.O.	
32. डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा रोग)	एम.डी. (त्वचा रोग)	14. Doctor of Medicine (General Medicine) M.D. (Gen. Med.)	
33. मास्टर आफ मेडिसिन (ज्वर-मायन)	एम.डी. (ज.र.)	15. Diploma in Tuberculosis & Chest Diseases D.T.C.D.	
34. मास्टर आफ मेडिसिन (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)	एम.डी. (सा. और नि.आ.)	16. Doctor of Medicine (Venerology) M.D. (Ven.)	
35. मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका शल्य चिकित्सा)	एम.एस. (तंत्र.श.चि.)	17. Doctor of Medicine (Anaesthesiology) M.D. (Anaes.)	
		18. Doctor of Medicine (Paediatrics) M.D. (Paed)	
		19. Doctor of Medicine (Radiology) M.D. (Radio)	
		20. Master of Surgery (General Surgery) M.S. (Gen. Sur.)	

21. Master of Surgery (ENT)	M.S. (ENT)
22. Master of Surgery (Ortho.)	M.S. (Ortho)
23. Doctor of Medicine (Pharm)	M.D. (Pharm)
24. Doctor of Medicine (Neurology)	D.M. (Neuro)
25. Doctor of Medicine (Cardiology)	D.M. (Card.)
26. Master of Surgery (Paediatric Surgery)	M.Ch. (Paed. Surg.)
27. Master of Surgery (Plastic Surgery)	M.Ch. (Plas. Surg.)
28. Master of Surgery (Anatomy)	M.S. (Anatomy)
29. Master of Surgery (Neuro-surgery)	M.Ch. (Neuro. Surg.)
30. Master of Surgery (Genito-Urinary-surgery).	M.Ch. (Genito-Urinary sug.)
31. Master of surgery (Thoracic surg.)	M.Ch. (Thoracic Surg.)
32. Doctor of Medicine (Derm.)	M.D. (Derm.)
33. Doctor of Medicine (Biochemistry)	M.D. (Biochemistry)
34. Doctor of Medicine (Social & Preventive Medicine)	M.D. (SPM)
35. Master of Surgery (Neuro-Surgery)	M.S. (Neuro-Surg.)
36. Diploma in Public Health	D.P.H.
37. Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynaecology)	M.D. (Obst. Gynae)
38. Diploma in Physical Medicine & Rehabilitation	D.P.M. & R.
39. Diploma in Health Education	D.H.E.
40. Doctor of Medicine (Radio-Therapy)	M.D. (Radio-Therapy)

NOTE:—These qualifications shall be recognised medical qualifications only when granted on the following dates:

M.B.B.S. Degree from March, 1992

Postgraduate Degrees from March 1990.

Postgraduate Diplomas from March 1989.

R. VIJAYA KUMAR, Desk Officer
[No. V. 11015/58/88-ME(UG)]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

क्र.भा. 1501 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना क्र.भा.सं. 3151 तारीख 28-12-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अन. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी.एन.बी.यू. से जी.जी.एस.-II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य : गुजरात जिला : भाखच तालुका : वागदा

गांव	खलाक नं.	हेक्टेयर आर.	सेटीयर
केशवान	25	0	08 60
	23	0	20 80
	21	0	26 00
	37	0	08 80
	40	0	20 00
काटे ट्रेक		0	02 60
	60	0	07 60
	58	0	13 20
	57	0	22 60
	1076	0	16 80
	54	0	11 20
	53	0	13 00
	52	0	19 40
	51	0	00 58
	46	0	29 02
	47	0	05 60

[सं. 12016/91/91-प्रो.एन.जी.डी.-IV]

एम. माटिन, हेक्क अधिकारी

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1501.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3151 dated 28-12-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the

right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNB to GGS. II

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Keshwan	25	0	08	60
	23	0	20	80
	21	0	26	00
	37	0	08	80
	40	0	20	00
	Cart track	0	02	60
	60	0	07	60
	58	0	13	20
	57	0	22	60
	1076	0	16	80
	54	0	11	20
	53	?	13	00
	52	0	19	40
	51	0	00	58
	46	0	29	02
	47	0	05	60

[No. O-12016/91/91-ONG D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

मई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.आ.सं. 1502—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 3163/5 तारीख 28-12-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का पाईपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट देखी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्णय लेती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

बी-21-22 से जंक्शन बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात

जिला : भरुच

तालुका : जंबुसर

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	मार.	सेंटीयर
कहानवा	कार्ट ट्रैक	0	01	80
	55	0	17	68
	56	0	05	72
	54/ए/बी	0	04	16
	53	0	08	45
	52	0	08	32
	51	0	11	18
	37	0	00	18
	34	0	12	74

[सं ओ० 12016/105/91/ओएनजीसी IV]

एम० मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1502.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3165 dated 28-12-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from D-21—22 to Junction Point

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
Kahanwa	Cart track	0	01	80
	55	0	17	68
	56	0	05	72
	54/A/B	0	04	16
	53	0	08	45
	52	0	08	32
	51	0	11	18
	37	0	00	18
	34	0	12	74

[No. O-12016/105/91-ONG D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.प्रा. 1503.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा.सं. 3152 तारीख 28-12-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राण्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और प्रागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

बहेज-3 से बहेज जी.सी.एस. तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात

जिला : मद्रास

तालुका : वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हैक्टेयर	आर.	सेंटीयर
कोलीयाद	213	0	01	00
	228	0	24	00
	214	0	14	40
	227	0	26	20
	229	0	27	80
	178/बी	0	01	20
	178/ए	0	30	60
	190	0	24	00
	189/बी	0	02	80
	191	0	19	20
	187	0	19	20
	183/बी	0	13	20

[सं ओ 0-12016/92/91-ओ.एन जी.डी.-4]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1503.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3152 dated 28-12-1992 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Dahej-3 to Dahej GGS.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec- tare	Arc -	Con- tiare
Koliad	213	0	01	00
	228	0	24	00
	214	0	14	40
	227	0	26	20
	229	0	27	80
	178/B	0	01	20
	178/A	0	30	60
	190	0	24	00
	189/B	0	02	80
	191	0	19	20
	187	0	19	20
	183/B	0	13	20

[No. O-12016/92/91-ONG D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली 25 मई, 1992

का.प्रा. 1503.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा.सं. 3153 तारीख 28-12-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राण्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और प्रागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस धाराओं में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी एन.बी.यू. से जी.जी.एम.-II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात

जिला : भरुच

तालुका : वाग्रा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	अर.	सेंटीयर
पालडी	241	0	29	58
	242	0	00	38
	244	0	25	04
	246	0	35	00
	249	0	11	40
	254	0	30	80
	256	0	28	70
	257	0	00	70
	274	0	10	64

[सं. ओ-12016/93/91-ओ.एन.जी.डी.-4]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1504.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3153 dated 28-12-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNPU to GGS. II.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cent-tiare
Paldi	241	0	29	58
	242	0	00	38
	244	0	25	04
	246	0	35	00

249	0	11	40
254	0	30	80
256	0	28	70
257	0	00	70
274	0	10	64

[No. O-12016/93/91-ONGD-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.प्रा. 1505.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संजालय की अधिसूचना का.प्रा.सं. 3153 तारीख 28-12-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और प्राप्ते, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा प्रजित किया जाता है।

और प्राप्ते उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस धाराओं में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन. उल्फू ए. जे (19) से लनवा ई पी एम.-I तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात

जिला : महेसना

तालुका : चपासमा

गांव	खेती नं.	हे.	अर.	सेंटीयर
लनवा	514/पी	0	05	40
	514/पी	0	05	88
	514/पी	0	03	60
	513/3	0	10	08
	512	0	07	80
	510	0	35	64
	432	0	05	28
	431	0	04	68
	430	0	04	44
	436	0	03	84

[सं. ओ-12016/104/91-ओ.एन.जी.डी.-IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1505.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3164 dated 28-12-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances,

SCHEDULE

Pipeline from LWAJ (19) to LANWA EPS.I.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chanasma

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Tanwa	514/P	0	05	40
	514/P	0	05	88
	514/P	0	03	60
	513/3	0	10	08
	512	0	07	80
	510	0	35	64
	432	0	05	28
	431	0	04	68
	430	0	04	44
	436	0	03	84

[No. O-12016/104/91-ONG D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.आ. 1506.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 3144 तारीख 24-11-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का प्रस्ताव आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का क्रिश्चय किया है।

1370 GI/92—3.

अतः, आतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्-द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ई.पी.एस. से अक्तेबर मी.टी.एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाणा	तालुका : चानासा		
गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	घार.	सेंटी
मेसली	36/ए	0	32	80
	36/बी	0	24	80
	38/ए	0	28	20
	49	0	34	00
	48/ए	0	26	85
	4	0	37	07
	47	0	04	40
	5	0	15	20
	6	0	14	05
	7	0	08	15
	8	0	06	20
	9	0	07	70
	10	0	05	00
	11	0	10	40
	13	0	17	35
	19	0	36	55
	18	0	13	80
	16	0	46	10

[सं. -ओ11027/113/90-ओ एन जी बी-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1506.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3144 dated 24-11-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from E.P.S. to Ankloshwar CTF.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec- tare	Arc	Cent- tiare
Bhensali	36/A	0	32	80
	36/B	0	24	80
	38/A	0	28	20
	49	0	34	00
	48/A	0	26	85
	4	0	37	07
	47	0	04	40
	5	0	15	20
	6	0	14	05
	7	0	08	15
	8	0	06	20
	9	0	07	70
	10	0	05	00
	11	0	10	40
	13	0	17	35
	19	0	36	55
	18	0	13	80
	16	0	46	10

[No. O-11027/113/90-ONG D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. प्रा. सं. 1507.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 489 तारीख 16-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राण्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और प्रागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेष्टि करती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

चोकारी टी बिन्दु से जिष्को तक पार्श्व लाईन बिछाने के लिए (नया)

राज्य:—गुजरात

ज़िला:—वडोदा

ता. पावरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेन्टी.
1	2	3	4	5
मृजपुर	1264	0	10	33
	1265	0	11	28
	1259	0	07	61
	1258	0	07	43
	1257	0	11	20
	1256	0	21	91
	1284	0	17	18
	1286	0	00	35
	1289	0	19	28
	1290	0	02	00
	कार्ट ट्रैक	0	00	65
	1240	0	08	60
	1239	0	12	93
	1234	0	11	13
	1235	0	10	33
	1221	0	15	18
	1222	0	12	93
	1215	0	07	78
	1214	0	07	28
	1211	0	03	55
	1213	0	03	93
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	1159	0	09	71
	1160	0	06	23
	1158	0	07	93
	1164	0	22	28
	1165	0	10	82
	कार्ट ट्रैक	0	01	52
	982	0	18	07
	983	0	00	76
	975	0	21	08
	976	0	03	30
	977	0	17	65
	970	0	00	35
	कार्ट ट्रैक	0	00	65
	843	0	01	54
	844	0	19	93
	845	0	04	00
	848	0	12	28
	849	0	16	68
	850	0	05	30
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	953	0	08	68
	952	0	10	68
	951	0	05	40
	950	0	04	75
	948	0	05	26
	947	0	01	03

1	2	3	4	5
	864	0	26	04
	886	0	22	80
	678	0	16	00
	677	0	11	80
	672	0	01	50
	675	5	08	85
	671	0	08	60
	670	0	07	60
	655	0	01	40
	663	0	13	60
	658	0	00	35
	659	0	17	40
	494	0	02	70
	493	0	18	00
	कार्ट ट्रैक	0	0 2	
	483/बी	0	04	25
	486	0	02	50
	484	0	12	00
	485	0	07	75
	471	0	23	00
	469	0	01	25
	कार्ट ट्रैक	0	03	00
	400	0	04	00
	438	0	04	00
	437	0	08	69
	436	0	04	00
	435	0	04	00
	434	0	05	20
	415	0	18	50
	414	0	04	50
	410	0	10	00
	413	0	05	00
	412	0	11	00
	408	0	09	00
	348	0	00	70
	349	0	10	20
	357	0	13	00
	359	0	08	00
	340	0	20	00

[सं. ओ—11027/199/90/ओ. एन. जी. डी. III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 150.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 489 dated 16-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of

user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Chokari T. Point to GIPCO (Revised)

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padara

Village	Block No.	Hec-tare	Arc	Cent-tiare
1	2	3	4	5
Mujpur	1264	0	10	33
	1265	0	11	28
	1259	0	07	61
	1258	0	07	43
	1257	0	11	20
	1256	0	21	91
	1284	0	17	18
	1286	0	00	35
	1289	0	19	28
	1290	0	02	00
	Cart track	0	00	65
	1240	0	08	60
	1239	0	12	93
	1234	0	11	13
	1235	0	10	33
	1221	0	15	18
	1222	0	12	93
	1215	0	08	78
	1214	0	07	28
	1211	0	03	55
	1213	0	03	93
	Cart track	0	01	00
	1159	0	09	71
	1160	0	06	23
	1158	0	07	93
	1164		22	28
	1165	0	01	82
	Cart track	0	01	52
	982	0	18	07
	983	0	00	76
	975	0	21	08
	976	0	03	30
	977	0	17	65
	970	0	00	35
	Cart track	0	00	65
	843	0	01	54
	844	0	19	93
	845	0	04	00
	848	0	12	28
	849	0	16	68
	850	0	05	30
	Cart track	0	01	00
	953	0	08	68
	952	0	10	68
	951	0	05	40

1	2	3	4	5
MUJPUR	950	0	04	75
	948	0	05	26
	947	0	01	03
	864	0	26	04
	866	0	22	80
	678	0	16	00
	677	0	11	80
	672	0	01	50
	675	0	08	85
	674	0	08	60
	670	0	07	60
	655	0	01	40
	663	0	13	60
	658	0	00	35
	659	0	17	40
	494	0	02	70
	493	0	18	00
	Cart track	0	02	00
	483/B	0	04	25
	486	0	02	50
	484	0	12	00
	485	0	07	75
	471	0	23	00
	469	0	01	25
	Cart track	0	03	00
	400	0	04	00
	438	0	04	00
	437	0	08	69
	436	0	04	00
	435	0	04	00
	434	0	05	20
	415	0	18	50
	414	0	04	50
	410	0	10	00
	413	0	05	00
	412	0	11	00
	408	0	09	00
	348	0	00	70
	349	0	10	20
	357	0	13	00
	359	0	08	00
	340	0	20	00

[No. O-11027/199/90-ONGD.III]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. भा. 1508.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 982 तारीख 6-4-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना अग्रण घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और अग्रे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और अग्रे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा या

अनुसूची

जी. एन. सी. पी. से. जी. एन. ए. न्यूनतम पार्श्व लाईन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात	जिला—भरुच	तालुका—जंबुसर		
गाव	ब्लॉक नं.	है.	अर.	सेन्टी
कलक	789	0	06	89
	766/प/बी	0	34	32
	768	0	03	25
	769	0	05	20
	770	0	02	08
	फाट ट्रेक	0	02	86
	721/प	0	72	80

[सं. ओ-11027/60/90—ओ. एन. जी. सी. III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1508.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 982 dated 6-4-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNCP to GNAQ

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hec-tare	Ac-re	Centi-are
Kalak	789	0	06	89
	766/A/B	0	34	32

1	2	3	4	5
	768	0	03	25
	769	0	05	20
	770	0	02	08
	Cart track	0	02	86
	721/A	0	72	80

[No. O-11027/60/90-ONG D-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. प्रा. सं. 1509.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 428 तारीख 9-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख की तिथि होगी।

अनुसूची

जी एन सी जी से जी जी एस II तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात		ज़िला—भरुच		तालुका—वाग्रा	
गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर	
पालडी	190	0	11	18	
	195	0	07	80	
	194	0	05	20	
	200	0	08	45	
	199	0	03	25	
	201	0	24	18	
	209	0	13	65	
	208	0	10	66	
	212	0	07	80	
	213	0	18	46	
	214	0	27	04	
	216/ए	0	08	45	
	279	0	20	80	
	284	0	11	70	
	277/ए	0	17	36	
	277/बी	0	02	80	

[सं. ओ.—11027/197/90—ओ. एन. जी. डी.—III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1509.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 428 dated 9-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNGC to GGS. II

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra.

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent.
Paldi	190	0	11	18
	195	0	07	80
	194	0	05	20
	200	0	08	45
	199	0	03	25
	201	0	24	18
	209	0	13	65
	208	0	10	66
	212	0	07	80
	213	0	18	46
	214	0	27	04
	216/A	0	08	45
	279	0	20	80
	284	0	11	70
	277/A	0	17	36
	277/B	0	02	80

[No. O-11027/197/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. प्रा. सं. 1510.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 983 तारीख 6-4-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और प्राप्ते, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने नात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अथ, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा न शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और प्राप्ते उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के पश्चात् की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

पी. एस. से अंकलेश्वर पी. टी. एफ. तक पाइपलाइन बिछाने के लिए ।

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—अंकलेश्वर

ब्लॉक नं.	हे.	घा.	सेन्टी.
वा 169	0	02	20
171	0	27	53
172	0	11	90
कार्ट ट्रैक	0	04	20
214	0	23	95
216	0	06	50
213	0	19	20
217	0	28	80
233	0	20	70
232/ए/बी	0	45	75
228	0	23	75
229	0	03	80
कार्ट ट्रैक	0	05	40
10/पी	0	17	15
17	0	16	95
20	0	35	68

[नं. ओ.-11027/117/90-ओ. एन. जी. बी.-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी ।

New Delhi, the 25th May, 1992

O. 1510.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 983 dated 6-4-91 under sub-section (1) of Section 3 of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

and whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

and further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from E.P.S. to Ankleshwar CTF.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent.
Telwa	169	0	02	20
	171	0	27	53
	172	0	11	90
	Cart track	0	04	20
	214	0	25	95
	216	0	06	50
	213	0	19	20
	217	0	28	80
	233	0	20	70
	232/A/B	0	45	75
	228	0	23	75
	229	0	03	80
	Cart track	0	05	40
	10/P	0	17	15
	17	0	16	95
	20	0	35	68

[No. O-11027/117/90 ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. प्रा. स. 1511.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 984 तारीख 6-4-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और प्राप्ते, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अथ, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और प्राप्ते उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक

नैस प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जे. एन. ए. पी. से जे. एन. एम. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य:—गुजरात जिला: मेहसाणा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	घर.	सेन्टीयर
सिद्धोसना	107	0	09	60
	104	0	11	88
	105	0	00	48
	103	0	02	64
	100	0	08	64
	99	0	05	40

[सं. ओ.-11027/145/90-ओ. एन. जी. सी.-III]

एम. माटिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1511.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 984 dated 6-4-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from JNAP to JNM

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent.
Sidosana	107	0	09	60
	104	0	11	88
	105	0	00	48
	103	0	02	64
	100	0	08	64
	99	0	05	40

[No. O-11027/145/90-ONGD-III]

M. MATIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. प्रा. सं. 1512.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 494 तारीख 16-2-91 द्वारा राष्ट्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ;

अनुसूची

घोकारी टी विन्दु से जिप्को तक पार्श्व लाईन बिछाने के लिए (नया)।

राज्य:—गुजरात जिला:—बड़ौदा तह.---पावन

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	घर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
एकलवारा	622	0	14	90
	621	0	08	40
	525	0	02	70
	591	0	05	84
	592	0	20	30
	590	0	15	00
कार्टे ट्रेक		0	01	69
	551	0	09	00
	552	0	16	36
	553	0	19	48
कार्टे ट्रेक		0	03	26
	467	0	08	88
	466	0	06	00
	465	0	06	80
	468	0	05	00
	464	0	24	11
	558	0	06	02
	462	0	12	01
	461	0	03	81
कार्टे ट्रेक		0	04	55
	242	0	17	48
	243	0	19	78

1	2	3	4	5
	233	0	01	14
	234	0	14	95
	कोटार	0	03	08
	87	0	21	81
	88	0	13	40
	92	0	10	00
	91	0	12	32
	105	0	34	80
	104	0	26	33
	122	0	24	85
	123	0	10	84
	कार्ट ट्रैक	0	01	18
	124	0	04	26
	कार्ट ट्रैक	0	03	17
	125	0	10	80

[सं. ओ.--11027/198/90--ओ. एन. जी. बी.-IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1512.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 494 dated 16-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Chokari 'T' Point to GIPCO

State : Gujarat: District Vadodara Taluka - Padra.

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent
1	2	3	4	5
Akalbara	622	0	14	90
	621	0	08	40
	625	0	02	70
	591	0	05	84
	592	0	20	30
	590	0	15	00

1	2	3	4	5
	Cart track	0	01	69
	551	0	09	00
	552	0	16	36
	553	0	19	48
	Cart track	0	03	27
	467	0	08	88
	466	0	06	00
	465	0	06	80
	468	0	05	00
	464	0	24	11
	558	0	06	02
	462	0	12	01
	461	0	03	81
	Cart track	0	04	55
	242	0	17	48
	243	0	19	78
	233	0	01	14
	234	0	14	95
	Kotari	0	03	08
	87	0	21	81
	88	0	13	40
	92	0	10	00
	91	0	12	32
	105	0	34	80
	104	0	26	33
	122	0	24	85
	123	0	10	84
	Cart track	0	01	18
	124	0	04	26
	Cart track	0	03	17
	125	0	10	80

[No. O-11027/198/90-ONGD.III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.प्रा.सं. 1513:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा.सं. 981 तारीख 6-4-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था।

यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और ध्याते, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम का धारा 6 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ता.सं-1 से जी.एन.ए.सू तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य--गुजरात जिला--बड़वा तालुका--जंबुसर

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेटी.
कपुरीया	215	0	11	55
	217	0	55	10
	216	0	12.	64
	213	0	04	59
	212	0	09	93
	185	0	00	80
	184	0	02	75
	183	0	00	75
	182/2	0	02	75
	128	0	01	45

[सं. ओ-11027/46/90--ओ एन जो डी-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1513.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 981 dated 6-4-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from NADA-1 to GNAQ.

State : Gujarat Distt. Bharuach Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent
1	2	3	4	5
Kapuria	215	0	11	65
	217	0	05	10
	216	0	12	64
	213	0	04	59
	212	0	09	93
	185	0	00	84

0	2	3	4	5
	184	0	02	75
	183	0	00	75
	182/2	0	02	75
	128	0	01	45

[No. O-11027/46/90-ONGD, III]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली 25 मई, 1992

का.प्रा. 1514:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन को भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा.सं. 974 तारीख 6-4-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सशम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निर्देश होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सर्वा बाधाओं से मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

गंधार से धुवाण तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य--गुजरात जिला--खंडा तालुका--बोरसद

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सेटी.
देहवाण	1076	0	24	00

[सं. ओ. 11027/82/88-ओ एन जी डी-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1514.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 974 dated 6-4-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Gandhar to Dhuvaran

State : Gujarat Distt : Kheda Taluka : Borsad

Village	Survey No.	Hect	Are	Cent.
Dewan	1076	0	24	00

[No. O-11027/82/88-ONGD.III]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.प्रा.सं.1515:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा.सं. 975 तारीख 6-4-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा का उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से सभी बाधाओं से मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी.एन.बी.एफ.से. जी.एन.ए. क्यू तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला भद्रक तालुका : जंबूसर

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	घर.	सेंटीघर
कलक	565	0	00	12
	653	0	00	10

1	2	3	4	5
	652	0	06	50
	655	0	24	14
	592	0	21	80
	665	0	12	87
	654	0	09	75
	664	0	07	80

[सं.ओ.-11027/84/89-ओ एन जी इ-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1515.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 975 dated 6-4-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM GHRF to GNAQ

State : Gujarat Distt : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent.
Kalak	565	0	00	12
	653	0	00	10
	652	0	06	50
	655	0	24	14
	592	0	21	80
	665	0	12	87
	654	0	09	75
	664	0	07	80

[No. O-11027/84/189-ONGD.-III]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.प्रा.: 1516—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा.सं. 985 तारीख 6-4-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार पाइपलाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अथ, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्-द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

इ.पी.एस. से अंकलेश्वर सीटीएफ तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : --गुजरात जिला और तालुका : --भरुच

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेंटी.
नावेथा	243	0	17	65
	260	0	18	20
	261	0	00	25
	258	0	10	15
	257	0	14	35
	264	0	13	85
	265	0	03	50
गाडापार		0	08	20

[सं. ओ-11027/146/90-ओ एन जी डी-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1516.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 985 dated 6-4-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from E.P.S. to Ankleshwar CTF.

State : Gujarat Distt : Taluka : Bharuach

Village	Block No.	Hect	Are	Cent.
NAVETHA	243	0	17	65
	260	0	18	20
	261	0	00	25
	258	0	10	15
	257	0	14	35
	264	0	13	85
	265	0	03	50
Cart track		0	08	20

[No. O-11027/146/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.भा. 1517 :--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.भा.सं. 968 तारीख 6-4-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अथ, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्-द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन के इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ओ एन जी एन से ईपीएस तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : --गुजरात जिला : --भरुच तालुका : --वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेंटीयर
गधार	322/ग/बी	0	83	20

[सं. ओ-11027/152/90-ओ एन जी डी-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1517.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 968 dated 6-4-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNGN to E.P.S.

State : Gujarat Distt : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent
Gandhar	322/A/B	0	83	20

[No. O-11027/152/90-ONGD-III]

M. MARTIN Desk Officer.

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.भा.सं. 1518 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज वाहपलाहन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधन की अधिसूचना का.भा.सं. 427 तारीख 9-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को वाहपलाहनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार वाहपलाहन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जो एन.जी.बी. से जोएन.डी.ए. तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर	सेन्टी.
पावडी	357	0	03	38
	358	0	14	56
	359	0	07	28
	345	0	17	68
	348	0	06	50
	331	0	03	25
	338	0	04	16
	337	0	31	20
	406	0	93	43

[सं. ओ-11027/193/90-ओ एन जी डा-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1518.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 427 dated 9-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNGB to GNDF.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra.

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent.
Paldi	357	0	03	38
	358	0	14	56
	359	0	07	28
	345	0	17	68
	348	0	06	50
	331	0	03	25
	338	0	04	16
	337	0	31	20
	406	0	93	43

[No. O-11027/193/-90-ONGD-II]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. प्रा. 1519.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 1 के अर्थात् भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 423 तारीख 9-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्थात् सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अथ, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी एन. डी.डी. से जी एन. डी.डी. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : भरुच	तालुका : वाग्रा			
गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेटीयर	
गंधार	322/ए/बी/	1	29	97	

[सं O-11027/189/90/ऑ एन जी डी-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1519.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 423 dated 9-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNDD to GNDC

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra.

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent.
Gandhar	322/A/B	1	29	97

[No. O-11027/189/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. प्रा. 1520.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्थात् भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 781 तारीख 27-2-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्थात् सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अथ, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

नवागाम सी.टी.एफ. से कोयला रिफाइनरी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात जिला :—खेड़ा तालुका :—मातार

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
हरीयाला	683/1/पी	0	10	40
	683/पी	0	01	37
	688/1	0	00	25
	648	0	24	40
	644	0	21	00
	641/2	0	40	40
	640/2	0	07	40

[सं. O-11027/11/90-ओ एन जी सी-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1520.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 781 dated 27-2-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from NAVAGAM CTF to KOYALI REFINERY
State: Gujarat District : Kheda Taluka : MATAR

Village	Block No.	Hect	Are	Cent.
Hariyala	683/1/P	0	10	40
	683/1/P	0	01	37
	688/1	0	00	25
	648	0	24	40
	644	0	21	00
	641/2	0	40	40
	640/2	0	07	40

[No. O-11027/11/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

का आ 1521.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ सं. 789 तारीख 27-2-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सधम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते केन्द्रीय सरकार सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजह से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

टी पी रजासण से रामोन जी जी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दमसोई

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेंटीआर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बीनानीया	140	0	07	00
	139	0	26	00
	138	0	15	00
	136	0	07	60
	137	0	17	60
बी. पी.		0	02	40
	108	0	37	20
	109	0	00	36
	118	0	37	40
	102	0	58	20

[सं. O-11027/3/90-ओ एन जी सी-III]

एम. मार्टिन डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1521.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 789 dated 27-2-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central

Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from T.P. Ranasan to Ranol GGS.

State: Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent.
Bilaiya	140	0	07	00
	139	0	26	00
	138	0	15	00
	136	0	07	60
	137	0	17	60
	V.P.	0	02	40
	108	0	37	20
	109	0	00	36
	118	0	37	40
	102	0	58	20

[No. O-11027/3/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. भा. 1522.--यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 776 तारीख 31-3-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था।

और यत्: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत्: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के प्रश्नात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-

द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, शोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

गंधार से छुहारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : खेडा तालुका : खंभात

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेटी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छुहारण	440	0	14	40
	439	0	05	52
	438	0	00	48
	437/1	0	14	14
	437/2	0	08	25
	436	0	23	70
	435/1	0	18	60
	435/2	0	12	00
	434/1-ए	0	09	24
	434/1-बी	0	13	50
	434/2	0	03	64
	424	0	10	20
	425/1	0	15	00
	622/3	0	17	40
	622/2	0	15	60
	622/1	0	15	60
काटे ट्रेक		0	04	50
	407/2	0	11	40
	407/1	0	12	00
	406	0	11	90
	404/1	0	00	32
काटे ट्रेक		0	09	00
	376/3	0	00	12
	376/2	0	10	44
	376/1बी	0	18	00
	376/1ए	0	16	20
	377	0	15	60
	378	0	24	60
	380	0	01	00
	379/1	0	07	50
	379/2	0	22	20
	273	0	04	68
	276	0	09	00
	366	0	09	00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	274	0	23	40
	काटे ट्रैक	0	01	50
	240	0	20	10
	248	0	14	40
	249	0	11	70
	250	0	21	30
	216	0	06	00
	254/1	0	47	40
	251/2	0	22	20
	210	0	07	50
	209	0	16	50

[सं. O-11027/5/90 एम. एन. जी. सी. -III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1522.—Whereas by notification of the Government India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 776 dated 31-3-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (i) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Gnahdar to Bhuwaran

State : Gujarat District: Kheda Taluka : Khambhat

Village	Survey No.	Hect.	Are	Cent.
1	2	3	4	5
Dhuwaran	440	0	14	40
	439	0	05	52
	438	0	00	48
	437/1	0	14	14
	437/2	0	08	25
	436	0	23	70
	435/1	0	18	60
	435/2	0	12	00
	434/1-A	0	09	24

1	2	3	4	5
	434/1-B	0	13	50
	434/2	0	03	64
	424	0	10	20
	425/1A	0	15	00
	622/3	0	17	40
	622/2	0	15	60
	622/1	0	15	60
	Cart track	0	01	50
	407/2	0	11	40
	407/1	0	11	00
	406	0	11	90
	404/1	0	00	37
	Cart track	0	09	00
	376/3	0	00	12
	376/2	0	10	44
	376/1-B	0	18	00
	376/1-A	0	16	20
	377	0	15	60
	378	0	24	60
	380	0	01	00
	379/1	0	07	50
	379/2	0	22	20
	273	0	04	68
	276	0	09	00
	366	0	09	00
	274	0	23	40
	Cart track	0	01	50
	240	0	20	10
	248	0	14	40
	249	0	11	70
	250	0	21	30
	216	0	06	00
	254/1	0	47	40
	251/2	0	22	20
	210	0	07	50
	290	0	16	50

[N]. O-11027/5/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. प्रा. 1523.—यतः पेट्रोलियम और द्रव्यजन खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 786 तारीख 27-2-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः महम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और प्राप्ते यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियाँ में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार से निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सर्वा वाध्याओं से मुक्त रूप में वायणा के प्रकाशन की दस तारीख को निहित होगी।

अनुसूची

के. एन. के. फेज II के लिए पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात	जिला—खेडा	तालुका—नडीयाद			
गांव	ब्लॉक नं.	हे.	घ.र.	से.	
आखडोल	646	0	27	50	
	647	0	02	50	
	648	0	10	00	
	672	0	10	00	
	670	0	04	00	
	671	0	07	00	
	669	0	00	15	
	718	0	11	00	
	717	0	00	10	
	719	0	08	40	
	725	0	12	40	
	711	0	00	15	
	761	0	09	00	
	763	0	18	00	
	764	0	06	00	
	806	0	15	00	
	839	0	17	20	
	877	0	05	80	
	876	0	12	60	
	875	0	08	30	
	460पी	0	02	40	

[सं. ओ.—11027/6/90—ओ एन जी डी—III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1523.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 786 dated 27-2-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intended to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline for K N K Phase II

State: Gujarat Dist : Kheda Taluka : Nadiad

Village	Block No.	Hect.	Are	Centiare
Akhdol	646	0	27	50
	647	0	02	50
	648	0	10	00
	672	0	10	00
	670	0	04	00
	671	0	07	00
	669	0	00	15
	718	0	11	00
	717	0	00	10
	719	0	08	40
	725	0	12	40
	711	0	00	15
	761	0	09	00
	763	0	18	00
	764	0	06	00
	806	0	15	00
	839	0	17	20
	877	0	05	80
	876	0	12	60
	875	0	08	30
	460/P	0	02	40

[No. O-11027/6/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.आ. 1524.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 787 तारीख 27-2-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आने उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रामोल जीजीएस से एईसी वीओल तक पाईपलाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात; जिला : अहमदाबाद; तालुका : दसकोई

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	घार	सेन्टी-घार
पींसोल	567	0	11	20
	566	0	53	00
	565/1	0	08	80
	563	0	17	60
	553	0	09	60
	554	0	11	00
	556	0	05	20
	555	0	08	00

[सं. ओ-11027/7/90-ओ एन जी डी-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1524.—Whereas by notification of the Government India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 787 dated 27-2-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from RAMOL GGS to AEC Vinzol

State : Gujarat Distt Ahmedabad Taluka : Dasecroi

Village	Survey N.	Hect.	Are	Cent
Vinzol	567	0	11	20
	566	0	53	00
	565/1	0	08	80
	562	0	17	60

1	2	3	4	5
	553	0	09	60
	554	0	11	00
	556	0	05	20
	555	0	08	00

[No. O-11027/7/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.आ. 1525.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 780 तारीख 27-2-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मन्त्रम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एवद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रामोल जी जी एस से एईसी वीओल तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात;	जिला : अहमदाबाद;	तालुका : दसकोई		
गांव	ब्ल.क. नं.	हेक्टर	घार	सेन्टीघार
हाथीजण	634	0	01	00
	648	0	00	42
	649	0	10	80
	624	0	07	20
	623	0	12	80
	621	0	10	60
	620	0	10	20
	614	0	16	80
	615	0	10	40
	616	0	15	80
	580	0	00	51
	519	0	01	65
	520	0	13	60
	521	0	16	60
	523	0	23	50
	0	03	00	

[सं. ओ-11027/10/90-ओएनजीडी-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1525.—Whereas by notification of the Government India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 780 dated 27-2-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances,

SCHEDULE

Pipeline from Ramol GGS to AEC Vinzol

State : Gujarat District Ahmedabad Taluka : Daskroi

Village	Block No.	Hect.	Are	Centiare
Hathijan	634	0	01	00
	648	0	00	42
	649	0	10	80
	624	0	07	20
	623	0	12	80
	621	0	10	60
	620	0	10	20
	614	0	16	80
	615	0	10	40
	616	0	15	80
	580	0	00	51
	519	0	01	65
	520	0	13	60
	521	0	16	60
	523	0	23	50
	Cart track	0	03	00

[No. O-11027/10/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.प्रा. 1526.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा. सं. 582 तारीख 2-2-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाना है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

बलोल जी.जी.एस.टी से लनका जी.जी.एस-3 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए—

राज्य : गुजरात; जिला : महेसाणा; तालुका : चाणासमा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर आर	सेन्टी- आर
मुलथानिया	43	0	00
	42/2	0	10
	42/1	0	14
	40/3	0	00
			21

[सं. ओ. 11027/21/90(ओएमजीसी-III)]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1526.—Whereas by notification of the Government India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 582 dated 2-2-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Balol GGS I to Lanva GGS III

State : Gujarat Distt : Mehsana Taluka : Chanasma

Village	Survey No.	Hect.	Are	Cent
Multhaniya	43	0	00	45
	42/2	0	10	80
	42/1	0	14	10
	40/3		00	21

[No. O-11027/21/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली 25 मई, 1992

का.सं. 1527—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.सं. 850 तारीख 7-4-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और भागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

सी पी एफ से ड.पी.एस तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात; जिला : मेहसा; तालुका : बागरा

गांव	ब्लोक नं.	हेक्टर	आर.	सेन्टी.
1	2	3	4	5
चाँचवेल	931	0	03	20
	932	0	50	77
	933	0	44	27
	930	0	23	35
	929	0	09	60
	928	0	10	80
	754	0	20	16
	743	0	46	08

1	2	3	4	5
	753	0	82	46
	744	0	61	44
	752	0	22	00
	679	0	40	00
	678	0	04	00
	680	0	70	50
	676/ए/बी	0	80	50
	684	0	04	59
	683	0	68	00
	687	0	52	00
	631	0	31	32
	636	0	01	68
	688	0	00	30
	634	0	62	72
	635	0	34	47
	633	0	01	08
	632	0	00	81
	640	0	65	25
	641	0	64	00
	517	0	25	00
	516	0	32	00
	515	0	65	00
	511	0	49	50
	463	0	42	00
	461/ए/बी	0	32	00
	472	0	19	50
	473	0	08	37
	474	0	93	40
	काँड ट्रेक	0	07	44
	405	1	18	57
	406	0	12	80
	396	0	91	25
	398	0	01	15
	397	0	03	60
	391	0	51	42
	1324	0	23	04
	1327	0	41	60
	1326	0	39	06
	1325	0	63	50
	390	0	27	50
	389	0	10	24
	282	10	55	06
	284	4	90	00

[स. ओ-11027/33/90/ओ एनजीडी-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1527.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 850 dated 7-4-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from C.P.F. to E.P.S.

State : Gujarat Distt: Bharuch Taluka Vagra

Village	Block No	Hect.	Are	Cent
1	2	3	4	5
Chanchwel	931	0	03	20
	932	0	50	77
	933	0	44	27
	930	0	23	35
	929	0	09	60
	928	0	10	80
	754	0	20	16
	743	0	46	08
	753	0	82	46
	744	0	61	44
	752	0	22	00
	679	0	40	00
	678	0	04	00
	680	0	70	50
	676/A/B	0	80	50
	684	0	04	59
	683	0	68	00
	687	0	52	00
	631	0	31	32
	636	0	01	68
	688	0	00	30
	634	0	62	72
	635	0	34	47
	633	0	01	08
	632	0	00	81
	640	0	65	25
	641	0	64	00
	517	0	25	00
	516	0	32	00
	515	0	65	00
	511	0	49	50
	463	0	42	00
	461/A/B	0	32	00
	472	0	19	50
	473	0	08	37
	474	0	93	40
Cart track		0	08	44
405		0	18	75
406		0	12	80
396		0	91	25

1	2	3	4	5
	398	0	01	15
	397	0	03	60
	391	0	51	42
	1324	0	23	04
	1327	0	41	50
	1326	0	39	60
	1325	0	63	06
	390	0	27	50
	389	0	10	24
	282	0	55	06
	284	0	90	00

[No. O-11027/33/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.आ. 1529.—यह: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधिन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 3737 तारीख 24-11-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उन अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों के बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यह: मन्त्र प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और प्राये, यह केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और प्राये उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ए केन्द्रीय सरकार, निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजह से और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एल० डब्ल्यू० एफ० एक्स से लंबा पी० एम० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात जिला: मेहसाणा, तालुका: वाणसमा

सुनसर	5 62	0	10	56
-------	------	---	----	----

[सं. ओ-11027/127/90-ओ एन ग्रीडी-III]

एम० मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1528.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3137 dated 24-11-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from LWFX to LZNWA EPS. II
State : Gujarat Distt : Mehsana Taluka : Chanasma

Village	Survey No	Hct	Are	Cent.
Sunasar	562	0	10	56

[No. O-11027/127/90 ONGD IV]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली 25 मई, 1992

का.प्र. 1529.—यत्. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 425 तारीख 9-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का आशय घोषित कर दिया था।

और यत् सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत्, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को महित होया।

अनुसूची

जी. एन. सी. जी. से जी. जी. एस. II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसना	तालुका : चानासा			
गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेंटी.	
केशवान	337	0	07	02	
	कार्ट ट्रैक	0	03	25	
	167	0	07	28	
	168	0	09	62	
	165	0	08	32	
	177	0	08	58	
	178	0	19	24	
	179	0	00	28	
	180	0	17	16	
	181	0	06	50	
	182	0	18	46	
	188	0	00	06	
	189	0	18	72	
	192	0	07	80	
	110	0	07	54	
	109	0	05	98	
	108	0	14	56	

[सं. ओ-11027/191/90-ओएनजीसी-II]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1529.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 425 dated 9-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline :

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNCG to GGS. II

State : Gujarat Distt : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hect	Are	Cent
Keshwan	337	0	07	02
	Cart track	0	03	25
	167	0	07	28

	2	2	4	5
168	0	09	62	
165	0	08	32	
177	0	08	58	
178	0	19	24	
179	0	00	28	
180	0	17	16	
181	0	06	50	
182	0	18	46	
188	0	00	06	
189	0	18	72	
192	0	07	80	
110	0	07	54	
109	0	05	98	
108	0	14	56	

[No. O-11027/191/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली 25 मई, 1992

का. प्रा. 1530.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा.सं. 851 तारीख 9-3-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उन अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए सज्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोग के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

आर आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय गैल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस भावना को निहित होगा।

अनुसूची

के. एन.के. फेस II की पाईप लाइन बिछाने के लिए
राज्य: गुजरात जिला: खेड़ा तालुका: पेटलाद

गाँव	ब्लॉक नं.	हेक्टर	आर	सेंटीयर
संजया	312	0	06	90
	कार्ट ट्रैक	0	00	80
	297	0	09	10
	कार्ट ट्रैक	0	01	40
	302	0	01	25
	300	0	15	75

	1	2	3	4	5
		307	0	07	33
		308	0	08	50
		306	0	01	17
		315	0	06	40
		314	0	06	60
		313	0	05	20
		311	0	06	80

[सं. 11027/26/90-आ एन जो ई-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1530.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 851 dated 9-3-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline for KNK Phase II

State: Gujarat Dist: Kheda Taluka - Petlad

Village	Block No	Hect	Arc	Cent.
Sanjaya	312	0	06	90
	Cart track	0	00	80
	297	0	09	10
	Cart track	0	01	40
	302	0	01	25
	300	0	15	75
	307	0	07	33
	308	0	08	50
	306	0	01	17
	315	0	06	40
	314	0	06	60
	313	0	05	20
	311	0	06	80

[No. O-11027/26/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.प्र. 153।—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बंटाव्य को अधिसूचना का.प्र. 3064 तारीख 17-11-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों के बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राण्य घोषित कर दिया था।

और यतः मजमूदा प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन.ए. द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एन.ए. द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे, इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में स्थित होने की वजह से तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाश—की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

चोकरी टी बिंदु से उदेंग तक पाइप लाईन बिछाने के लिए (नदा)

राज्य गुजरात

जिला और तालुका : वडोदा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेंटी
1	2	3	4	5
अपाड	285	0	14	80
	286	0	17	20
	287	0	03	00
	290	0	12	00
	291	0	00	50
	292	0	25	00
	293	0	09	00
काट्टे ट्रैक	0	01	20	
	296	0	12	80
	295	0	24	15
	254	0	02	50
	298/बं	0	18	80
	304	0	10	00
	306	0	00	70
काट्टे ट्रैक	0	00	70	
	305	0	10	00
	307/ए	0	41	00
काट्टे ट्रैक	0	01	00	
	309	0	19	09
काट्टे ट्रैक	0	01	40	
	191	0	20	20

1	2	3	4	5
	190	0	17	16
	189	0	08	16
	156	0	02	25
	188	0	25	15
	186	0	03	65
	185	0	18	30
	166	0	13	70
	165	0	11	00
	164	0	01	20
	129	0	10	38
	127	0	27	79
	125/ए	0	20	20
	122	0	29	50
	121	0	06	90

(सं. ओ-11027/142/90-ओ एन जो रो III)

एम. मार्टिन, डी.ए. अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1531.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3064 dated 17-11-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Chokari 'T' Point to Undera

State : Gujarat Distt : & Taluka : Vadodara

Village	Block No.	Hect	Are	Cent
1	2	3	4	5
Ampad	285	0	14	80
	286	0	17	20
	287	0	03	00
	290	0	12	00
	291	0	00	50
	292	0	25	00
	293	0	09	00
	Cart track	0	01	20
	296	0	12	80
	295	0	24	15
	254	0	02	50

1	2	3	4	5
AMPAD—Contd.	298/B	0	18	80
	304	0	10	00
	306	0	00	70
	C.T.	0	00	70
	305	0	10	00
	307/A	0	41	00
	Cart trach	0	01	00
	309	0	19	09
	Cart trach	0	01	40
	191	0	20	20
	190	0	17	16
	189	0	08	16
	156	0	02	25
	188	0	25	14
	186	0	03	15
	185	0	18	30
	166	0	13	70
	165	0	11	00
	164	0	01	20
	129	0	10	38
	127	0	27	79
	21 25/A	0	29	20
	122	0	29	50
	121	0	06	90

No. O-11027/142/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.आ. 1532.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना क.अ.सं. 3065 तारीख 17-11-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अप आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची				
एल डब्ल्यू एच. न्यू से लानवा ई.पी एस-II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।				
राज्य : गुजरात जिला : मेहेसाणा ताल्लुका : चणिसमा				
गांव	सर्वे नं.	हे.	अर.	सेंटी.
सुणसर	549	0	02	28
	557	0	06	12
	556/पी	0	02	76
	556/पी	0	03	36
	555	0	01	08
	559	0	00	72
	553/3	0	08	88
	553/2	0	04	56
	553/पी	0	04	56

[सं. ऑ-11027/127/90-ओ एन जी डी III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1532.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3065 dated 17-11-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from LWHQ to Lanwa EPS-II				
State : Gujarat Distt : Mehsana Taluka : Chanasma				
Village	Survey No.	Hect	Are	Centiare
Sunasar	549	0	02	28
	557	0	06	12
	556/P	0	02	76
	556/P	0	03	36
	555	0	01	08
	559	0	00	72
	553/3	0	08	88
	553/2	0	04	56
	553/P	0	04	56

[No. O-11027/127/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. अ. 1533—यतः पेट्रोलियम और खनिज के पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जेंट अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आयोग मंत्रालय के अधिसूचना का. अ. सं. 790 तारीख 27-2-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निश्चय करती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी।

अनुसूची

सी. टी. एल. मुलोल से जी. जी. एस. 11 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - गांधीनगर तालुका - कलोला

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	घार.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
अदालज	529	0	22	60
	530	0	02	00
	532	0	16	60
	531	0	13	00
	534	0	09	00
	538/पी	0	04	00
	537	0	24	00
	538/पी	0	17	20
	542	0	41	38
	644	0	08	62
	545	0	06	00
	546	0	11	30
	515	0	00	10
	548	0	30	20
	552	0	07	70
	552	0	20	30
	काट ट्रैक	0	01	20
	555/पी	0	33	20
	555/पी	0	01	00
	557	0	13	20

1	2	3	4	5
	558	0	00	10
	571	0	01	56
	569	0	16	00
	576/पी	0	18	52
	577/पी	0	00	63
	वी पी	0	06	60
	577/पी	0	12	80
	काट ट्रैक	0	02	80

[सं. ओ - 11027/4/90-ओ एन जी डी - III]

एम. माटिन, डैपक अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1533.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 790 dated 27-2-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GTF Kalol to GGS XI.

State : Gujarat Distt: Gandhinagar Taluka : Kalol

Village	Block No	Hect	Area	Centiare
Adalaj	529	0	22	60
	530	0	02	00
	532	0	16	60
	531	0	13	00
	534	0	09	00
	538/P	0	04	00
	537	0	24	00
	538/P	0	17	20
	542	0	41	38
	344	0	08	62
	545	0	06	00
	546	0	11	30
	515	0	00	10
	548	0	30	20
	552	0	07	70
	553	0	30	30
	Cart track	0	01	20

1	2	3	4
	555/P	0	33 20
	555/P	0	01 00
	557	0	15 20
	558	0	00 10
	571	0	01 56
	569	0	16 00
	576/P	0	18 52
	577/P	0	00 63
	V.P.	0	06 60
	577/P	0	12 80
	Cart track	0	02 80

[No.O-11027/4/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. मा. 1534 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. मा. सं. 590 तारीख 2-2-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था।

और यतः गृहम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजह से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख की तिथि होगी।

अनुसूची

जी. जा. एस XI से टेप आफ बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला व तालुका - गान्धिनगर

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	घर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
तारपुर	117	0	07	60
कार्देट ट्रेक		0	13	42
	118	0	06	00
	119	0	27	40
	123	0	26	80
	122	0	33	60

1	2	3	4	5
	124	0	18	22
	85	0	02	20
	84	0	20	40
	77	0	05	13
	80	0	10	50
	82	0	04	70
	81	0	18	00
	75	0	16	80
	76	0	10	60

[सं. ओ - 11027/19/90 - ओ एनजीसी-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1534.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 590 dated 2-2-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GGS XI to Tape off point Chandkheda
State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Block No.	Hect	Are	Cent
Tarapur	117	0	07	60
	Cart track	0	13	42
	118	0	06	00
	119	0	27	40
	123	0	26	80
	122	0	24	00
	124	0	18	22
	85	0	02	20
	84	0	20	40
	77	0	05	13
	80	0	10	50
	82	0	04	70
	81	0	18	00
	75	0	16	80
	76	0	10	60

[No. O-11027/19/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. भा. 1535.--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि से उपयोग का अधिकार का अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 2631 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करनेका विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. एच. बी. से के. जी. जी. एस. तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - खेडा तालुका - खम्बहत

गांव	सं. नं.	हे.	आर.	सेन्टी.
1	2	3	4	5
धुवरान	252/1	0	07	58
	252/3	0	15	15
	606	0	00	55
	603	0	01	94
	254/1, 2	0	07	75

[सं. जो - 11027/66/90 - ओ. एन. जी. डी. - [I]]

एम. मार्टिन, बैक: अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

1535.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2631 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from DHV to KGGS

State : Gujarat District:-Kheda Taluka : Khambhat

Village	Survey No.	Hect	Are	Ce
Dhuvaran	252/1	0	07	58
	252/3	0	15	15
	606	0	00	55
	603	0	01	94
	254/1&2	0	07	75

[No.O-11027/66/90-ONJD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. भा. 1536.--यतः पेट्रोलियम और खनिज की पाइपलाइन भूमि से उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 3058 तारीख 17-11-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उ. अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित हो की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एल डब्ल्यू. ई एफ से लनवा ईपीएस-1 तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - महेसाणा तालुका - चानसमा

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर	सेन्टी
1	2	3	4	5
दानोदरदा	506	0	01	92
	509	0	06	12
	508	0	07	32
	514/पी	0	2	88
	513	0	04	32
	517/पी	0	06	00
	517/1	0	08	52
	522/1	0	04	44
	519	0	00	60
	521	0	13	44

[सं. ओ-11027/128/90-ओएनजीडी III]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1536.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3058 dated 17-11-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from LWFF to LANWA EPS-I

State : Gujarat Distt: Mehsana Taluka : Chanasma

Village	Survey No.	Hect.	Are	Cent.
Danodarda	506	0	01	92
	509	0	06	12
	508	0	07	32
	514/P	0	02	88

1	2	3	4	5
	513	0	04	32
	517/P	0	06	00
	517/1	0	08	52
	522/1	0	04	44
	519	0	00	60
	521	0	13	44

[No. O-11027/128/90-ONGD-III]

M. Martin, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. आ. 1537:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार ने प्रस्तावित और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3060 तारीख 17-11-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार उस अधिसूचना से सम्बन्धित अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) अन्तर्गत सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सम्बन्धित अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सम्बन्धित अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार ने निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एल डब्ल्यू. ई एफ से लनवा ईपीएस तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : महेसाणा तालुका : चानसमा

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर	सेन्टी
1	2	3	4	5
दानोदरदा	544	0	01	32
	555/1	0	12	60
	555/2	0	03	72
	556/2	0	03	84
	556/	0	04	08
	564/पी	0	06	12
	564/पी	0	05	76
	565	0	15	84

[सं. ओ-11027/131/90-ओएनजीडी-III]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1537.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3060 dated 17-11-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from LWEU to LAWNA EPS-1

State : Gujarat District: Mehsana Taluka : Chanasma

Village	Survey No.	Hect.	Are.	Cent
Danodarda	554	0	01	32
	555/1	0	12	60
	552/2	0	03	72
	556/2	0	03	84
	556/1	0	04	08
	564/P	0	06	12
	564/P	0	05	76
	565	0	15	84

[No. O-11027/131/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. प्रा. 1538.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सलाह की अधिसूचना का. प्रा. सं. 3059 तारीख 17-1-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों के बिछाने के लिए अर्जित करना अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय गैर और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं में मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

बी.ओ.ए.डी.ने बकराजी ई.पी.एस.तक पाइप लाईन बिछाने के लिए
राज्य - गुजरात जिला - मेहसाणा तालुका - चानास्मा

गाँव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सेन्टी.
1	2	3	4	5
इन्द्रप	184/1	0	68	40
	196	0	01	44
	197	0	05	28

[नं. ओ - 11027/129/90 - ओ एन जी डी - III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1538.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3059 dated 17-11-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from BCAD to BECHARAJI EPS

State : Gujarat. Distt. : Mehsana Taluka : Chanasma

Village	Survey No.	Hect.	Are.	Cent.
Indrap	184/1	0	68	40
	196	0	01	44
	197	0	05	28

[No. O-11027/129/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. आ. 1539.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3136 तारीख 24-11-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी एन ई जड से ई. पी. एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।
राज्य - गुजरात जिला - भरुच तालुका - वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
गंधार	321	0	27	01
	322/ए/बी	1	08	81

[सं. ओ - 11027/119/90 - ओ एन जी डी - III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1539.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3136 dated 24-11-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Gov-

ernment hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNEZ to E.P.S.

State : Gujarat	Distt: Bharuch	Taluka : Vagra
Village	Block No.	Hect. Are Cen
Gandhar	321	0 27 01
	322/A/B	1 08 81

[No. O-11027/119/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. आ. 1540.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ सं. 3138 तारीख 24-11-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी.एन.ई.आई. से ई.पी.एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।
राज्य - गुजरात जिला - भरुच तालुका - वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
गंधार	377	0	06	24
	382	0	16	64
	383	0	08	84
	386	0	03	12
	385	0	14	69
	389	0	20	80
	321	0	15	60
	322 ए	2	00	72

[सं. ओ-11027/79/90-ओ एन जी डी-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1540.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3138 dated 24-11-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNEI to E.P.S.

State : Gujarat District: Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hect.	Are.	Cent.
Gandhar	377	0	06	24
	382	0	16	64
	383	0	08	84
	386	0	03	12
	385	0	14	69
	389	0	20	80
	321	0	15	60
	322/A	2	00	72

[F.No. O-11027/79/90-ONGD-III]

M MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.आ.सं 1541.—यह पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2614 तारीख 17-9-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उन अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यह : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यह केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, यह अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती

है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए अर्जित करने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जा रहा है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय गैस और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

पावरा-9 में पेट्रोलियम पाइपलाइन तक पाटन ताड़न बिछाने के लिए

राज्य — गुजरात जिला और तालुका — वडोदरा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
गोकल्पपुरा	171/1	0	10	40
	171/2	0	02	00
	168	0	17	39
	169	0	00	68
	167	0	00	24
	कार्ट ट्रैक	0	00	52

(सं. पी-11027/96/90-ओ एन जी सी-III)

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1541.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 9614 dated 17-9-90 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Mines Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Padra-9 to EPS Padra

State : Gujarat District & Taluka : Vadodara

Village	Block No.	Hect.	Are.	Cent.
Gohalpur	171/1	0	10	40
	171/2	0	02	00
	168	0	17	39
	169	0	00	68
	167	0	00	24
	Cart track	0	00	52

[No. O-11027/96/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer,

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.आ.सं. 1542 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 3142 तारीख 24-11-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा की प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एल. डब्ल्यू. ई. एस. और एल. डब्ल्यू. ई. वार्ड. से लक्शा ई. पी. एस.-I तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाना तालुका—चानासमा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर.	सेंटर
दानोदराडा	288	0	04	56
	286	0	00	48
	285	0	07	20
	284	0	06	24
	283	0	04	56
	283	0	00	60

[सं. ओ-11027/136/90-ओ एन जी डी-III]

एम. मार्टिन, ईस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1542.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3142 dated 24-11-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

1370 GI/92—7

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from LWEX & LWEY to LANWA EPS-I

State : Gujarat Distt : Mehsana Taluka : Chanasma

Village	Survey No.	Hect.	Are	Cent
Danodarada	288	0	04	56
	286	0	00	48
	285	0	07	20
	284	0	06	24
	283	0	04	55
	283	0	00	60

[No. O-11027/136/90-ONGD-II]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली 25 मई, 1992

अधिसूचना

का.आ.सं. 1543 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 426 तारीख 02-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा की प्रकाशन की इस तारीख निहित होगा।

अनुसूची

सुलेर 'टी', पोन्ट से जी.जी.एम. II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—वाग्रा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
पायडी	261/ए	0	06	21
	272	0	10	40
	55	0	05	20
	269	0	05	20

[सं. ओ-11027/192/90-ओ एन जी डी-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1543.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 426 dated 9-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Muller 'T' Point to GGS II

State: Gujarat Distt: Bharuch Taluka : Vagra.

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent.
Paldi	261/A	0	06	21
	272	0	10	40
	55	0	05	20
	269	0	05	20

[No. O-11027/192/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.प्र.सं. 1544 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्र.सं. 2612 तारीख

6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन.ए. द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एन.ए. द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी.एन.ए.एफ. से एन.जी.-4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—अमांथ

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
अमीपुर	32	0	04	55
	31	0	03	90
	30	0	03	25
	357	0	07	15
	366	0	05	20
	367	0	01	30
	346	0	23	40
	264	0	05	20
	269	0	07	80

[सं. ओ-11027/98/90-ओ एन जी डी-III]

सं. त्रिवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1544.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2612 dated 6-10-90 under sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNAF to MG-I

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent.
Valipur	32	0	04	55
	31	0	03	90
	30	0	03	25
	357	0	07	15
	366	0	05	00
	367	0	01	30
	346	0	23	40
	264	0	05	20
	269	0	07	80

[No. O-11027/98/90-ONGD-III]

K. VIVEKANANDA, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. भा. 1525:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाहपलाहन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.भा.सं. 2922 तारीख 1-11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाहपलाहनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाहपलाहन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वश वेदी है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

इ पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पार्श्व लाईन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला व तालुका—भरुच

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेटीयर
1	2	3	4	5
कासव	92/ए-बी	0	27	30
	93	0	15	28
	91	0	15	10
	95	0	07	40
	88	0	07	17
	87	0	13	68
	102/ए/बी/सी/डी	0	11	60
	84	0	28	00
	78	0	00	35
	82	0	25	10
	81	0	17	00
	113	0	35	80
	71	0	26	00
	128	0	16	90
	127	0	29	63
	131	0	02	16
	132	0	12	35
	56	0	19	90
	कार्ट ट्रेक	0	08	50
	55	0	19	70
	11	0	23	80
	13	0	23	10
	15	0	29	48
	14	0	01	44
	20	0	07	80
	22	0	08	80
	21/ए-बी	0	09	02
	23	0	23	25
	26	0	21	60
	27	0	05	50
	कार्ट ट्रेक	0	05	85
	498/ए-बी	0	10	60
	495	0	01	10
	520	0	11	20
	496	0	24	00
	491	0	00	20
	490	0	04	30
	489	0	32	00
	कार्ट ट्रेक	0	06	80

[सं. ओ-11027/126/89-ओ एन जी डी-III]

कै. विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1545.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2922 dated 1-11-89 under sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From EPS Gandhar to GNFC

State : Gujarat District & Taluka : Bharuach

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent.
1	2	3	4	6
KASAD	92/A-B	0	27	30
	93	0	15	28
	91	0	15	10
	95	0	07	40
	88	0	07	17
	87	0	13	68
	102/A/B/C/D	0	11	60
	84	0	28	00
	78	0	00	35
	82	0	25	10
	81	0	17	00
	113		35	80
	71	0	26	00
	128	0	16	90
	127	0	29	95
	131	0	02	16
	132	0	12	35
	56	0	19	90
	Cart track	0	08	50
	55	0	19	70
	11	0	23	80
	13	0	23	10
	15	0	29	48
	14	0	01	44
	20	0	07	80
	22	0	08	80
	21/A-B	0	09	02
	23	0	23	25
	26	0	21	60
	27	0	05	50

1	2	3	4	5
	Cart track	0	05	85
	498/A-B	0	10	60
	495	0	11	10
	520	0	11	20
	496	0	24	00
	491	0	00	20
	490	0	04	30
	489	0	32	00
	Cart track	0	06	80

[No. O-11027/126/89-ONGD-II]

K. VIVEKANAND, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.आ. 1546—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 2921 तारीख 1-11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था।

और यतः सभ्य प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

इ.पी.एस. गंधार से जी.एन.एफ.सी. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हुबटेयर	घार	सेन्टी.
1	2	3	4	5
साचण	252	0	10	00
	255/बी	0	07	50
	255/ए	0	13	20
	256	0	18	00
	257	0	00	16
	287/बी	0	07	20
	287/ए	0	10	42
	260	0	21	30
	288	0	06	14

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	266/ए	0	20	30		256	0	18	00
	266/बी	0	03	20		257	0	00	16
	268	0	09	45		287/B	0	07	20
	267	0	16	40		287/A	0	10	42
	270	0	37	62		260	0	21	30
	कार्ट ट्रैक	0	08	00		288	0	06	14
	243/ए	0	25	30		266/A	0	20	30
	242/ए	0	29	40		266/B	0	03	20
	कार्ट ट्रैक	0	05	00		268	0	09	45
	218	0	26	00		267	0	16	40
	219	0	14	70		270	0	37	62
	222	0	00	16		Cart track	0	08	00
	111	0	09	00		243/A	0	25	30
	70	0	08	75		242/A	0	29	40
	311	0	13	70		Cart track	0	05	00
	221/ए	0	05	15		218	0	26	00
	225	0	18	00		219	0	14	70
	226	0	15	00		222	0	00	16
						111	0	09	00
						70	0	08	75
						311	0	13	70
						221/A	0	05	15
						225	0	18	00
						226	0	15	00

[सं. O-11027/125/89-ओ एन जी डी-III]

के. विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1546.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2921 dated 1-11-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from EPS Gandhar To CNFC.

State : Gujarat District: Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hect	Are	Cent.
1	2	3	4	5
Sachan	252	0	10	00
	255/B	0	07	50
	255/A	0	13	20

[No. O-11027/125/89-ONGD III]

K. VIJEKANAND, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.आ. 1547 - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संवर्धन की अधिसूचना का.आ.सं. 2927 तारीख 1-11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार से उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की 3 स तारीख का तिथि होगा।

अनुसूची

इ पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : वरुच तालुका : वागरा

गाँव	ब्लॉक नं.	हे.	अर.	सेन्टी.
1	2	3	4	5
अरगामा	219	0	28	40
	225	0	00	48
	226	0	08	20
	234	0	10	90
	227	0	03	70
	228	0	20	00
	233	0	42	90
	237	0	19	95
	240	0	28	08
	241	0	00	38
	239	0	09	30
	242	0	12	00
	207	0	01	68
	243	0	10	65
	244	0	07	48
	246	0	12	80
	248	0	10	60
	249	0	11	00
	252	0	07	40
	253	0	04	28
	254	0	16	70
	257	0	14	70
	258	0	07	40
कार्ट ट्रैक	0	13	60	
58	0	03	85	
57	0	06	80	
कार्ट ट्रैक	0	03	40	
2	0	41	00	
3	0	08	00	
4	0	09	20	
5	0	06	92	
7	0	04	80	
8	0	01	57	
9	0	17	50	

सं-[O 11027/131/89-ओ.एन.जी.सी-III]

के. विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1547.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2927 dated 1-11-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from EPS Gandhar to GNFC

State : Gujarat Distret : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hect.	Ac.	Cent.
1	2	3	4	5
Argama	219	0	28	40
	225	0	00	48
	226	0	08	20
	234	0	10	90
	227	0	03	70
	228	0	20	00
	233	0	42	90
	237	0	19	95
	240	0	28	08
	241	0	00	38
	239	0	09	30
	242	0	12	00
	207	0	01	68
	243	0	10	65
	244	0	07	48
	246	0	12	80
	248	0	10	60
	249	0	11	00
	252	0	07	40
	253	0	04	28
	254	0	16	70
	257	0	14	70
	258	0	07	40
Cart track		0	13	60
58		0	03	85
57		0	06	80
Cart track		0	03	40
2		0	41	00
3		0	08	00
4		0	09	20
5		0	06	92
7		0	04	80
8		0	01	57
9		0	17	50

[N. O-11027/131/89-ONGD III]

K. VIVEKANANDA, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.प्रा.सं. 1548:- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1862 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा.सं. 2924 तारीख

1-11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाह्यलाहनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाह्यलाहन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

इ पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पाह्य लाइन बिछाने के लिए।
राज्य : गुजरात जिला : तालुका : भरुच

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेन्टी.
मंदेशाल	104	0	02	62
	108	0	04	20
	109	0	06	20
110/ए/बी/सी/डी/ई	0	05	44	
111	0	65	74	
112	0	06	12	
113	0	07	14	

[सं. O-11027/128/89-जी एन जी सी-III]

के. विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1548.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2924 dated 1-11-89 under sub section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government:

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC.

State : Gujarat	District & Taluka : Bharuch			
Village	Block No.	Hect- are	Are	Centi- arc
1	2	3	4	5
NANDEWAR	104	0	02	62
	108	0	04	20
	109	0	06	20
	110/A/B/C/D/E	0	05	44
	111	0	05	74
	112	0	06	12
	113	0	07	14

[No. O-11027/128/89-ONGDIII]

Sd/-

K. VIVEKANAND, Desk Officer

तृई विल्ली, 25 मई, 1992

का. आ. 1549:- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाह्यलाहन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2924 तारीख 1-11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाह्यलाहनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाह्यलाहन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

इ पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पाह्य लाइन बिछाने के लिए।
राज्य : गुजरात जिला : तालुका : भरुच

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेन्टी.
रहाडपोर	56	0	16	95
	54/पी	0	10	20

1	2	3	4	5
	48	0	08	48
	47	0	08	25
	44/पी/2/1	0	40	10
	46	0	02	05
	45	0	11	10
	28	0	10	20
	29/1/2	0	00	40
	27	0	08	95

[सं. O-11027/127/89-ओ एन जी डी III]

के. वियेकानन्द, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1549.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2923 dated 1-11-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC

State : Gujarat District & Taluka : Bharuch

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
RAHADPUR	56	0	46	95
	54/P	0	10	20
	48	0	08	48
	47	0	08	25
	44/P/2/1	0	40	10
	46	0	02	05
	45	0	11	10
	28	0	10	20
	29/1/2	0	00	40
	27	0	08	95

[No. O-11027/127/89-ONGD-III]

K. VIVEKANAND, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. प्रा. 1550 :- यत. पेट्रोलियम और गैस पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा.सं. 2958 तारीख 6-11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार के पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, शोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

इ पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।
राज्य : गुजरात जिला : तालुका : भरुच

गांव	इलाक में हे.	आर.	सेन्टी.
उमराज	447	0	18
	418 पाट	0	24
	449	0	09
	462	0	12
	463	0	00
	461 पाट	0	66
	476	0	30
	482/1/2	0	15
	479	0	12
	480 पाट	0	29

[सं.ओ. 11027/135/89-ओ एन जी डी III]

के. वियेकानन्द, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1550.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2958 dated 6-11-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC.

State : Gujarat

District & Taluka : Bharuch

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
UMRAJ	447	0	18	30
	448 Part	0	24	40
	449	0	09	30
	462	0	12	70
	463	0	00	72
	461 Part	0	66	35
	476	0	30	50
	482/1/2	0	15	10
	479	0	12	20
	480 Part	0	29	90

[No. O-11027/135/89-ONGD-III]

K. VIVEKANAND, Desk Officer.

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.भा. 1551.--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.भा.सं. 854 तारीख 7-4-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में

1370 G1/92-8

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तैल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में, सभी भाषाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची,

एन.के.जी.जी.एस-II से एन.के.सी.टी.एफ. तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : महेसाना तालुका : कडी

गांव	सर्वे. नं.	हे.	आर.	सेंटीयर
चासासन	114/2	0	09	12
	114/3	0	08	52
	86/1	0	01	20
	86/2	0	11	40
	86/3	0	05	64
	88	0	14	40
	87	0	03	60
	काटे ट्रेक	0	00	84
	92	0	09	84
	95	0	04	20

[सं. 11027/30/80-ओ.एन.जी.सी.-III]

के. विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1551.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 854 dated 7-4-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted the report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

(Department of Petroleum and Natural Gas)

PIPELINE FROM N-K GGS II TO NK CTF

New Delhi, the 1st June, 1992

State : Gujarat District :- Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
CHALASAN	114/2	0	09	12
	114/3	0	08	52
	86/1	0	01	20
	86/2	0	11	40
	86/3	0	05	64
	88	0	14	40
	87	0	03	60
	Cart Track	0	00	84
	92	0	09	84
	95	0	04	20

[No. O—11027/30/90—ONGD-III]

K. VIVEKANAND, Desk Officer

(प्राकृतिक गैस विभाग)

नई दिल्ली, 1 जून, 1992

का.प्रा. 1552.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला रायगढ़ में मौजे बोरीस, तहसील अलीबाग से मौजे सालाब तहसील मुरुड जंजिरा तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिये पाईप लाईन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110 066 द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अथ अतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिकार अजित करने का अपना आशय घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि को नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. प्रभु निवास, दूसरा मजला, अलीबाग, तहसील अलीबाग को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि यह चाहता है कि उक्त सुनुवाई व्यक्तिगत स्वरूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र जिला : रायगढ़ तहसील : अलीबाग

गाँव का नाम	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र हे.	आर	सेंटीयर
देवघर	--	--	314 भाग	--	09	50
	--	--	305 भाग	--	02	30

[सं. O-14016/63/90-जी.पी.]

सी. एल. बाशल, उप सचिव

S.O. 1552.—Whereas it appears to the Central Govt. that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, From Boris, Tahasil-Alibag, District-Raigad to Village-Salav, Tahasil-Murud Janjira, District-Raigad in the State of Maharashtra pipe line should be laid through the Agency of Gas Authority of India Ltd. 16 Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, Ring Road, New Delhi-110066.

And whereas, it appears to the Central Govt. that for the purpose of laying such pipe lines, it is necessary to acquire the Right of User in the lands described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipe lines (Acquisition of Right of user in the lands) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Govt. hereby declares its intention to acquire the Right of User in the lands referred in the schedule;

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the pipe lines through the said lands may prefer any objection within 21 days from date of the Notification to the Competent Authority, Tahasil-Salav Natural Gas pipe line, Prabhu Niwas, 2nd Floor, At. Post. Tahasil-Alibag, District-Raigad Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal Practitioner.

SCHEDULE

State : Maharashtra District :- Raigad Thasil : Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Gat No.	Area		
				H	Are	C. Are
1	2	3	4	5	6	7
Deoghar	—	—	314 Part	—	09	50
	—	—	305 Part	—	02	30

[No. O-14016/63/90-G.P.]

C. L. BASHAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 1 जून, 1992

का.प्रा. 1553.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला रायगढ़ में मौजे बोरीस, तहसील अलीबाग से मौजे सालाब, तहसील मुरुड जंजिरा तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिये पाईप लाईन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110 066 द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अथ पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिकार अजित करने का अपना आशय घोषित किया है।

बघर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड प्रभु निवास, दूसरा मजला, अलिबाग, तहसील-अलिबाग को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत स्वरूप में हो या किसी विधि व्यवहारी के मार्फत।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र		तहसील : अलीबाग		जिला : रायगड	
गांव का नाम	सर्वे नं.	हिस्सा नंबर	गट नम्बर	क्षेत्र	
				हे.	आर. सेंटीयर
खानाव	65	8 भाग	--	--	03 00
	96	3 भाग	--	--	00 60
	03	1 भाग	--	--	05 50

[सं० ओ-14016/63/90-जी.पी.]

सी. एल. बशाल, उप सचिव

New Delhi, the 1st June, 1992

S.O. 1553.—Whereas it appears to the Central Govt. that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, From Boris, Tahasil-Alibag, District-Raigad to Village-Salav, Tahasil-Murud Janjira, District-Raigad in the State of Maharashtra pipe line should be laid through the Agency of Gas Authority of India Ltd. 16 Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, Ring Road, New Delhi-110066.

And whereas, it appears to the Central Govt. that for the purpose of laying such pipe lines, it is necessary to acquire the Right of User in the lands described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipe lines (Acquisition of Right of user in the lands) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Govt. hereby declares its intention to acquire the Right of User in the lands referred in the schedule;

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the pipe lines through the said lands may prefer any objection within 21 days from the date of the Notification to the Competent Authority Tahasil-Salav Natural Gas pipeline, Prabhu Niwas, 2nd Floor, Alibag At Post Tahasil-Alibag, District Raigad, Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal Practitioner.

SCHEDULE

State : Maharashtra District : Raigad Tahasil : Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Gat No.	Area		
				H.	Ac.	C. Are
1	2	3	4	5	6	7
Khanav	68	8 Part	--	--	03	00
	96	3 Part	--	--	00	60
	03	1 Part	--	--	05	50

[No. O-14016/63/90-G.P.]

C. L. BASHAL. Dy. Secy.

नई दिल्ली, 1 जून, 1992

का.भा. 1554.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला रायगढ़ में मौजे बोरीस, तहसील अलिबाग से मौजे सालाव, तहसील मुरुद जंजिरा तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिये पाईप लाईन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. नई दिल्ली-110066 द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों का बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्प्राबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिकार अर्जित करने का अपना आणव्य घोषित किया है।

बघर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. प्रभु निवास, दूसरा मजला, अलिबाग, तहसील अलिबाग को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत स्वरूप से हो या किसी विधि व्यवहारी के मार्फत।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र		जिला : रायगड		तहसील : अर्लावाग	
गांव का नाम	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र	
				हेक्टर	घार, सेंटीयर
सहाण	—	—	386 भाग	—	— 57

[सं. ओ-14016/63/90-जी.पी.]

सी. एल. बशाल, उप सचिव

New Delhi, the 1st June, 1992

S.O. 1554.—Whereas it appears to the Central Govt. that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, From Boris, Tahasil-Alibag, District-Raigad to Village-Salav, Tahasil-Murud Janjira, District-Raigad in the State of Maharashtra pipeline should be laid through the Agency of Gas Authority of India Ltd. 16 Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, Ring Road, New Delhi-110066.

And whereas, it appears to the Central Govt. that for the purpose of laying such pipe lines, it is necessary to acquire the Right of User in the lands described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipeline (Acquisition of Right of user in the lands) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Govt. hereby declares its intention to acquire the Right of User in the lands referred in the schedule;

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the pipe lines through the said lands may prefer any objection within 21 days from the date of the Notification to the Competent Authority, Tahasil-Salav Natural Gas pipeline, Prabhu Niwas, 2nd Floor, At. Post Tahasil-Alibag, District-Raigad Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal Practitioner.

SCHEDULE

State : Maharashtra District : Raigad Tahasil : Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Gat No.	Area		
				H	Are	C. Are
1	2	3	4	5	6	7
Sahan	—	—	386 Part	—	—	57

[No. O-14016/63/90-G.P.]
C. L. BASHAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 1 जून, 1992

का.आ. 1555—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला रायगढ़ से मौजे बोरीस, तहसील-अलिबाग से मौजे सालाव, तहसील-मुहुड जजिरा तथा नैसर्गिक गैस परिवहन के लिये पाईप लाईन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110066 द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाठ अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः जब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना आग्रह घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आशेष, सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. प्रभु निवास, दूसरा मजला, अलिबाग, तहसील अलिबाग को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत स्वरूप में हो या किसी विधि व्यवहारी के मार्फत।

परिशिष्ट

तहसील : अलिबाग		जिला : रायगढ़		राज्य : महाराष्ट्र		
गांव का नाम	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र		
				हे.	आर	सें.आर
चेंद्रे	52	2-ए भाग	—	—	02	60
	54	4 भाग	—	—	13	20

[सं. ओ. 14016/63/90—जी पी.]

सी० एल० बगाल, उप सचिव

New Delhi, the 1st June, 1992

S.O. 1555.—Whereas it appears to the Central Govt. that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, From Boris, Tahasil-Alibag, District-Raigad to Village-Salav, Tahasil-Murud Janjira, District-Raigad in the State of Maharashtra pipe line should be laid through the Agency of Gas Authority of India Ltd. 16 Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, Ring Road, New Delhi-110066.

And whereas, it appears to the Central Govt. that for the purpose of laying such pipe lines, it is necessary to acquire the Right of User in the lands described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of user in the lands) Act.

1962 (50 of 1962) the Central Govt. hereby declares its intention to acquire the Right of User in the lands referred in the schedule;

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the pipe lines through the said lands may prefer any objection within 21 days from date of the Notification to the Competent Authority, Tahasil-Salav Natural Gas pipeline, Prabhu Niwas, 2nd Floor, At. Post Tahasil-Alibag, District-Raigad Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal Practitioner.

SCHEDULE

State : Maharashtra District : Raigad Tahasil : Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Block No.	Area		
				H	Are	C. Are
1	2	3	4	5	6	7
Chendhre	52	2-A	—	—	02	60
	54	4 Part	—	—	13	20

[No. O-14016/63/90-G.P.]

C. L. BASHAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 1 जून, 1992

का.आ. 1556—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला रायगढ़ से मौजे बोरीस तहसील-अलिबाग से मौजे-सालाव तहसील मुहुड जजिरा नैसर्गिक गैस परिवहन के लिये पाईप लाईन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110066 द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाठ अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः जब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आशेष सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. प्रभु निवास, दूसरा मजला, अलिबाग, तहसील अलिबाग को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत स्वरूप में हो या किसी विधि व्यवहारी के मार्फत।

परिशिष्ट

तहसील : अलिबाग		जिला : रायगढ़		राज्य : महाराष्ट्र		
गांव का नाम	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र		
				हे.	आर	सें.आर
बेलकडे	—	—	28 भाग	—	02	70
	—	—	299 भाग	—	00	13
	—	—	297 भाग	—	02	60
	—	—	294 भाग	—	04	50
	—	—	293 भाग	—	01	60
	—	—	220 भाग	—	00	70
	—	—	243 भाग	—	00	60

[सं. ओ. 14016/63/90—जी.पी.]

सी० एल० बगाल, उप सचिव

New Delhi, the 1st June, 1992

S.O. 1556.—Whereas it appears to the Central Govt. that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, From Boris, Tahasil-Alibag, District-Raigad to Village-Salav, Tahasil-Murud Janjira, District-Raigad in the State of Maharashtra, pipe line should be laid through the Agency of Gas Authority of India Ltd. 16 Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, Ring Road, New Delhi-110066.

And whereas, it appears to the Central Govt. that for the purpose of laying such pipe lines, it is necessary to acquire the Right of User in the lands described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipe lines (Acquisition of Right of user in the lands) Act 1962 (50 of 1962) the Central Govt. hereby declares its intention to acquire the Right of User in the lands referred in the schedule;

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the pipe lines through the said lands may prefer any objection within 21 days from date of the Notification to the Competent Authority, Tahasil-Salav Natural Gas pipe line, Prabhu Niwas, 2nd Floor, At. Post. Tahasil-Alibag, District-Raigad Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal Practitioner.

SCHEDULE

State : Maharashtra District : Raigad Tahasil : Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Gat No.	Area		
				H	Are	C
						Are
1	2	3	4	5	6	7
Belkade	—	—	28	—	02	70
			Part	—	—	—
			299	—	00	15
			Part	—	—	—
			297	—	02	60
			Part	—	—	—
			294	—	04	50
			Part	—	—	—
			293	—	01	60
			Part	—	—	—
—	—	—	220	—	00	70
			Part	—	—	—
			243	—	00	60
—	—	—	Part	—	—	—

[No. O-14016/63/90-G.P.]
C. L. BASHAL, Dy. Secy.

धर्म मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

का. आ. 1557—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धक, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, बंगलौर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/331/86 डी II(ए)]

मुभाप चन्द्र शर्मा, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1557.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 20-5-1992.

[No. L-12012/331/86-D.II (A)]
S. C. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

Dated this 12th day of May, 1992

PRESENT

SHRI M. B. VISHWANATH,

B.Sc., B.L.,

PRESIDING OFFICER

Central Reference No 95/87

I PARTY V/S II PARTY

Sri P. B. Rajput Regional Manager,
Sri G. S. Jawalimath, Region No. I/II,
C/o General Secretary, State Bank of India,
State Bank Staff Union, Regional Office, Hubli,
48, Church Street,
Bangalore-560001.

AWARD

In this reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, made by the Hon'ble Central Government of India by its order No. L-12012/331/86-D.II(A) dated the April, 1987, the point for adjudication as per schedule is:—

“Whether the action of the management of State Bank of India in discharging from service S/Shri P. B. Rajput (Messenger, Belgaum Branch) and G. S. Jawalimath, Messenger, Hirekerur Branch) is justified? If not, to what relief the concerned workmen are entitled?”

2. In the claim statement, among other things, it is contended that the departmental enquiry held against the workman Rajput and the workman Jawalimath is illegal.

3. In the counter statement the II party has, inter alia, contended that the departmental enquiry held against the I party workmen is in accordance with Law.

4. It is seen from the records that the plea in the claim statement regarding invalidity of D.E. has been amplified through amendment. Consequently the II party has filed additional counter statement on 4-1-88.

5. My Learned Predecessor, as could be seen from the order sheet dt. 4-1-88, has framed the preliminary issue as:

“Whether the II party proves that it has held D.Es. against the workmen in accordance with the Principles of Natural Justice and Law?”

6. On the preliminary issue, on behalf of the II party three witnesses have been examined. M.W.1 V. Vadhyar, Officer of the S.B.I. was the enquiry officer in respect of the D.E. held against the workman Rajput. M.W.2 Gopalan, Bank Manager was the E.O. in respect of the D.E. held against the workman Jawalimath. M.W.3 Triyambak is the branch Manager through whom the certified statement Ex. M. 10 has been produced. He has produced the certified statement Ex. M. 11 also. Ex. M.10 shows the subsistence allowance paid to the workman Jawalimath. Ex. 11 shows the subsistence allowance paid to the workman Rajput.

7. On behalf of the I party workmen, three witnesses have been examined WW-1 is Gurusiddappa Jawalimath, WW-2 is Prarap Rajput. Both W.W.1 and 2 are the workmen in-

involved in this reference. W.W.3 is Satish B. Wagh, General Secretary of the I party union W.W.3 was the defence representative in the enquiries against both the workmen.

8. After recording evidence, my Learned Predecessor by his order dt. 30-7-89 has given a finding that the D.Es. against both the employees were in accordance with law. He has given opportunity to the parties to adduce evidence, if any, on the rest of the points.

9. It can be seen from records that neither of the parties has adduced further evidence.

10. Arguments of both counsels have been heard on victimisation, perversity of findings and adequacy of sentence.

11. First I will take up the case of workman P.B. Rajput.

12. At the outset, it should be stated that there is absolutely no material to show that both the workmen have been victimised. There is no substance in the plea of victimisation.

13. Ex. M.1 is the charge sheet against P.B. Rajput. P.B. Rajput was working at Belgaum branch of the II party as Messenger. Ex. M.1 contains three charges against said P.B. Rajput. First charge is that the workman Rajput misappropriated Rs. 1,175/-, having presented and encashed Savings Bank withdrawal forms, pertaining to S.B. account No. 39/9290 in the name of Smt. Vimal Shankar Kamerkar Rajput handed over the amount to the depositor, Vimal Kamerkar, after considerable time only when the depositor complained to the branch about the matter.

14. The second charge is that on 29-4-1981 Rajput encashed the cheque for Rs. 1,500 issued by C.G. Aptekar, clerk at Dharwad branch on his account at that branch, purchased by their Belgaum branch as a DD No. PB 1419. After encashment, the delinquent Rajput stealthily removed the cheque, the covering schedule and the originating debit list from the branch and kept them with him, without allowing the cheque to be despatched to the Dharwad Branch of II party for realisation. He kept them with him till 27-7-81.

15. The third charge is that Rajput encashed at Dharwad and Davanagere Branches S.B. withdrawals on this savings bank account maintained at Belgaum branch without sufficient balance. When the D.Ds. were received at Belgaum branch, Rajput stealthily removed them from tappal without allowing them to be put through in the branch books to the debit of his (Rajput's) account and he handed over the instruments to the Branch Manager only on 3-8-81.

16. Ex. M.3 is the report of the Enquiry officer M.W.1. On charge No. 1 he gave benefit of doubt to the delinquent. In other words, he has held that the first charge against Rajput was not proved. On second charge the E.O. gave a finding that Rajput was guilty. On third charge also he gave a finding that the workman was guilty.

17. The report of the disciplinary authority is not marked in this case. Xerox copy is found in the record. The D.A. reversed the finding of the E.O. on charge No. 1. The D.A. accepted the findings of the E.O. on two other charges. The D.A. under paragraph 521 of the Sastry Award read in conjunction of 18.28 Desai Award ordered on charge No. 1 that the employee should be reverted to the first stage of basic "discharge from service". Accordingly the workman was discharged from service.

18. Now the point for consideration is :—

"Whether the findings are perverse?"

19. On charge No. 1, the E.O., in his finding given in metaphorical language says that the Bank officials were negligent. He further says that the I party should have been hauled up for forgery. I have carefully seen the four withdrawal slips made by the workman Rajput in the name of Vimal Shankar Kamerkar. All the four withdrawal slips, on the reverse, admittedly bear the signatures of the workman Rajput. From this it is abundantly clear that Rajput had alone drawn the money. It is difficult to believe that the workman had signed for the purpose of identification. When Kamerkar was an account holder in the bank, identifying her signature does not arise. The Bank officials must have been familiar with the signature of the account holder Kamerkar. It is clear from the material on record that the I party workman

has paid the amount drawn by him illegally to the account holder Kamerkar only when she complained. It is also significant to note that the depositor's signature has been taken subsequently. The admitted signatures of the account holder and the purported signatures of the account holder Kamerkar in Devanagiri script, differ. This is clear to the naked eye. The E.O. has failed to notice these aspects in his findings. The disciplinary authority has rightly gone into the matter in detail and reversed the finding of the L.O. on charge No. 1. It cannot be said that the D.A. has committed any mistake in reversing the finding of the E.O. on charge No. 1. I have stated that to the naked eye, the two signatures, one admitted and one disputed, differ. This shows that the withdrawal slips were signed by the workman Rajput and were encashed by him. The fact that the two signatures of the account holder differ on each of the withdrawals clearly proves the guilt of the workman Rajput. Clearly, I party workman has drawn the amounts wrongly from the account of Kamerkar. The I party has made good the amount only when the account holder complained. It is obvious that till then he had misappropriated the amount.

20. Now regarding charge No. 2, Ex. P.E.6 series and Ex. 1.1.7 (marked in the enquiry) are the relevant documents. It is clear that the cheque is a bearer cheque in the name of workman Rajput for Rs. 1,500/-. The cheque has been issued by another employee Aptekar. It is clear from P.E.6 List of originating debits (demand remittances despatched) and cheques remittance schedule that the amount has been credited to the account of the workman Rajput on 29-4-81. Though the amount was credited to the account of Rajput on 29-4-81, the cheque was not despatched to the Dharwad branch till 27-7-81 (wrongly stated as 27-4-83 at page 8 of Ex. M.3), on which date the cheque was handed over to the Branch Manager, Belgaum branch. Though it may be assumed that in a bank cheques being before despatched pass through many hands, it should be remembered that Rajput was the messenger. He was an interested party since he had encashed the cheque of Aptekar. The conclusion is inescapable that he had stealthily removed the cheque, covering schedule, list of originating debits from the bank and had kept them with him till 27-7-81 deliberately. The E.O.'s finding that the charge No. 2 was proved is correct. It cannot be stated to be perverse.

21. Now the third charge. The withdrawal slips Exs. P.E. 8, 9, 10 and 11 (marked in the D.E.) are the relevant schedule, and list containing stamps of Dharwad and Davanagere branches clearly shows that Rajput has discounted these withdrawal slips at Dharwad and Davanagere branches on the dates stated. The D.D. purchase cash slips with the admitted signature of Rajput establish that the workman Rajput had received the cash against these D.D. purchases on the respective dates. Ex. P.E. 7 is the account extract of the workman Rajput. On the dates of payment of cash against the D.D. purchases, it is clear from Ex. P.E. 7 (marked in the D.E.) Rajput had no sufficient funds in his account. When D.Ds. were received at Belgaum branch, Rajput stealthily removed them from the tappal and handed over the instruments to the Branch Manager only on 3-8-81 long after they were received. The E.O. in his report has referred to the relevant evidence in this regard, the evidence of the witness AG. Kapre, Branch Manager. This Branch Manager has stated that Rajput used to sort out the tappal. Workman Rajput was an interested party having encashed the D.Ds., without sufficient funds in his account, he was interested in concealing the D.Ds. that he had handed over them only on 3-8-81 is abundantly clear from the letter of workman Ex.P.E.19 (marked during the D.E.). The head messenger Raghunath Naik is since deceased. Rajput was also a messenger. The branch manager Khapre has clearly stated that Rajput was assisting the head messenger Raghunath Naik. The only conclusion possible is that workman Rajput had surreptitiously removed the instruments and handed over them only 3-8-81. The third charge also has been established. We cannot find fault with the finding of the M.O. in Ex.M.3.

22. There is no substance in the arguments that the E.O. has not discussed the evidence and has not taken into consideration the defence. Though Kamerkar is not examined, the charges against Rajput are proved. The Learned counsel for the I party has relied on 1991 Lab. I.C. 2470 (K.S.R.T.C. v/s. Nagendrapal). In this authority of our Hon'ble High

Court loss of Rs. 35 of the K.S.R.T.C. was involved. Our Hon'ble High Court was pleased to hold that punishment of dismissal was not proportionate to misconduct and directed reinstatement. In the instant case huge amounts are involved. Other acts of misconduct of grave nature are also involved. So the authority of our Hon'ble High Court is not applicable. The other authorities submitted on behalf of the I party are not applicable.

23. For the aforesaid reasons, I am of opinion, there is no perversity in the findings of the enquiry officer. The workman was a bank employee. Making use of his position, he has committed the acts of misconduct of grave nature. The accusations against the workman are grave. I am of opinion this is not a fit case in which the workman should be given an opportunity to reform himself.

24. I will take up the case of the other workman Jawalimath.

25. In respect of Jawalimath there are two charge sheets Exts. M.4 and 5. In the first charge sheet Ex.M.4 dt. 2-12-82 there are four charges. In the second charge sheet Ex. M-5 dt. 26-3-85 there is one more charge. There are in all five charges against the I party workman Jawalimath. The I party was working at Hirekerur branch of the II party. The I party workman Jawalimath was appointed as a messenger in 1965. He was promoted as cashier w.e.f. 1-2-80.

26. The first charge is that Jawalimath was on unauthorised absence on three occasions, in all for 274 days.

27. The second charge is that the I party workman misutilised his savings bank account at Hirekerur branch and issued withdrawal orders for Rs. 70 and Rs. 120 respectively. When the withdrawal orders were presented at the branch, the balance was only 0.07 ps. The withdrawal orders received from Belgaum bazar branch were returned as short credits unpaid for want of funds.

28. The third charge is that Jawalimath encashed five S.B. withdrawals on his account at Hirekerur branch at various branches, without having adequate fund on the date of commencement or on the date of presentation at the drawing branch.

29. The fourth charge against the I party workman is that he misrepresented (impersonated) himself as a cashier working at Belgaum and Hubli branches, encashed his S. B. withdrawals under different names at Chitradurga, Cauvery Bhavan and Madras main branches.

30. The fifth charge is that the I party workman misrepresented (impersonated) himself as a cashier working at Hubli branch and encashed two S.B. withdrawals at Madras branch.

31. Ex.M.9 is the report of the findings of the enquiry Officer Gopalan (M.W.2) in respect of charges 1 to 4. Ex. M.10 is the report of the finding of the E.O. in respect of the fifth charge.

32. Ex. P. 1 and P. 2 before the L.O. are the attendance registers. Ex.P.3 is the leave register. From the attendance register and leave register, it is clear that Jawalimath was on unauthorised absence for the charged periods. The examination of Branch Manager also proves this. The workman Jawalimath was absent without getting the leave sanctioned. The unauthorised absence has been established beyond reasonable doubt. The finding of the E.O. is correct.

33. The E.O. has referred to the objection memo Ex.P.4, withdrawal slip Ex.P.5, Ex.P.6 showing return of withdrawal slip, Ex.P.7 objection memo, Ex.P.8 withdrawal slip, Ex.P.9 cheque referred and returned register and Ex.P.10 relevant ledger sheet (ledger sheet kept in a cover). On this charge, two witnesses Joshi, Branch manager and another officer Patil were examined. The E.O. has considered the withdrawal slips issued by the workman and the cheque return memos issued by the branch while returning the instruments. He has discussed the evidence of two officers. The instruments were returned for want of funds in the account of Jawalimath. He has correctly come to the conclusion that the I party had encashed S.B. withdrawals on his account at Hirekerur branch as D.Ds. without having adequate funds in his account.

34. Now regarding charge No. 3. The E.O. in his report Ex. M.9 has referred to Exs. P.11 to P.21 which show cash paid to I party workman, letter addressed by the concerned branch, cash paid voucher and other correspondence like cheque remittances schedule and originating debits. He has also considered the evidence of P.W.2 Shaik, officer. It is clear that the I party workman has encashed and received amounts though there was no balance in his account on the dates presented. I give below tabular form which gives the details of the misconduct by the workman Jawalimath.

Name of the Branch	Date encashed	Amount	Balance on the date of encashment	Date of pre-sentment	Balance on the date of pre-sentment
1. Overseas Branch					
Bangalore	14-9-81	60/-	1-63	19-9-81	1-63
2. Gokul Indl. Estate, Hubli	19-3-82	50/-	35-07	23-3-82	35-07
3. —do—	22-3-82	70/-	35-07	25-3-82	0-07
4. Belgiam Bazaar Branch	21-4-82	70/-	0-07	3-5-82	0-07
5. Parasgad	23-4-82	200/-	0-07	3-5-82	0-07

The E.O. has rightly come to the conclusion that charge No. 3 was proved.

35. The E.O. has considered the evidence of two P.Ws. and three D.Ws. The E.O. has referred to Exs.P.22 to 28 which are COS.6 dt. 30-4-82 of Chitradurga branch, S.B. withdrawal slip dt. 30-4-82 by Rachayya, Belgaum branch objection memo dt. 6-5-82, Belgaum branch remittance schedule, D.D. purchase debit slip dated 27-4-82 of Cauvery Bhavan Branch for Rs. 150, office copy of Cauvery Bhavan branch letter R.M. 16-161 dated 10-6-1982, representation dt. 7-6-82 submitted by Shri M.P. Kulkarni, Cash Officer, Cauvery Bhavan branch. It is clear from the evidence and the documents that at Chitradurga branch the I party workman Jawalimath has impersonated as Rachayya, at Cauvery Bhavan branch as Patil Regarding impersonation at Madras branch, the E.O. has come to the conclusion that it is not proved since documents were not produced. Anyway his conclusion that the impersonation at Chitradurga branch and Cauvery Bhavan Branch is established. He has discussed relevant documents and the evidence of M.P. Kulkarni.

36. The report of the finding of the E.O. regarding charge No. 5 is contained in Ex.M.10. The E.O. has referred to the evidence of V. Unnikrishnan, Officer of Madras branch. He has referred to Ex.P.1 and P.2 and has come to the conclusion that the workman Jawalimath on 20-7-82 encashed S.B. withdrawal slip for Rs. 120 misrepresenting himself as Chowli. Cashier working at Hubli Branch. The E.O. has rightly come to the conclusion that charge No. 5 also was proved.

37. I am of opinion that the findings given by the E.O. as per Exs.P.9 and 10 are correct and valid. It cannot be said that the findings are perverse.

38. The disciplinary authority has accepted the findings of the E.O. and has passed an order of stoppage of one increment for a period of 6 months on charge No. 1, stoppage of two increments with cumulative effect on charge No. 2, stoppage of three increments with cumulative effect on charge No. 3. The D.A. has passed an order of discharge on charge No. 4. He has passed an order of discharge on charge No. 5 also.

39. Bearing in mind the nature of misconduct committed by the I party workman Jawalimath (five charge) I am of opinion that the punishment prescribed is proper and adequate. It cannot be said that this is a fit case in which the delinquent workman should be given an opportunity to reform himself.

40. In view of my aforesaid discussion, I pass the following :

AWARD

The reference is rejected.

Award passed rejecting the reference.

(Dictated to Stenographer, taken down by him, got typed, corrected and signed by me).

M. B. VISIWANATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

का. आ. 1558.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार [भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20 मई 1992 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011 (57/88-डी2(ए))]

सुभाष चन्द शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1558.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 20-5-1992.

[No. L-12011/57/88-D.II (A)]

S. C. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 35 of 1991

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Patna.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri K. M. K. Sinha, authorised representative.

For the Workmen—Shri G. K. Verma, General Secretary, State Bank of India Employees Union (Bihar State).

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dated, the 11th May, 1992

AWARD

By Order No. L-12011/57/88-D.II (A), dated the 20th March, 1989, the Central Government in the Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad.

Subsequently the dispute has been transferred to this Tribunal vide Notification No. L-12011/57/88-D.II (A), dated 104-1991.

"Whether the action of the management of State Bank of India, Patna, in not promoting Shri K. P. Singh with retrospective effect (the date when he became eligible for promotion) is justified? If not, to what relief is the workman eligible?"

2. The case of the management of State Bank of India, Patna, as disclosed in the written statement-cum-rejoinder, details apart, is as follows :

According to the rules/instructions, policy and practice of the Bank and conditions of service binding on and applicable to the workmen, the eligibility for considerations for appointment/promotion on regular basis to the post of Head Clerk is that every clerical employee, who has completed five years of confirmed service and who is considered suitable, is eligible for consideration for promotion/appointment to the post of Head Clerk provided he has given his consent in writing to such appointment/promotion and to serve in any office of the Bank in the circle, i.e. the then Bengal Circle in 1971 and Patna circle in 1972. The circular of the Bank No. Per 104/86 B. No. 124/68 underlines the position. In terms of such rules/instructions, policy and practice of the Bank and conditions of service binding on and applicable to the concerned workman, the suitability, the seniority and consent are the basis and most important ingredients for such promotion. As per practice, then prevalent, before August, 1977, refusal by the employee to accept the promotion/appointment as such was considered as debarment for promotion for all times to come. The employee knew fully well the impact and effect of his refusal as such and the fact that the same would debar him from appointment/promotion to the post of Head Clerk for all time to come and, therefore, while refusing appointment/promotion, he was fully conscious of the impact and in fact he has deliberately done so in order to avoid any transfer or for any other ulterior objectives best known to him. Therefore, the concerned workman, once having so refused and having acted upon such refusal, is now estopped from raising this dispute as he has no right to raise the dispute for the simple reason that having already taken advantage he cannot now go back and blow hot and cold at the same time. The concerned workman was neither willing nor was he eligible nor has he any right for appointment/promotion to the post of Head Clerk since the year 1971 as claimed.

3. The case of the concerned workman, as appearing in the written statement submitted on his behalf by the sponsoring union, State Bank of India Employees Union (Bihar State), briefly stated, is as follows :

K. P. Singh, the concerned workman joined the service of the erstwhile Bank of Behar Ltd. as a Clerk on 1-5-1964. The Bank of Behar Ltd. with all its assets and liabilities was amalgamated with State Bank of India in 1969 and all their employees, including the concerned workmen, were absorbed and made the employees of State Bank of India with continuity of service. All conditions of service applicable to the employees of the State Bank of India were/are extended to the employees of erstwhile Bank of Behar from 1-1-70. Since amalgamation the concerned workman has remained posted as a Clerk at the Bank's Judges' Court Road Branch, Patna. The post of Head Clerk falls within the clerical cadre and therefore, elevation to the post of Head Clerk is technically called as 'appointment' though, in fact, it is promotion. All clerical staff who have required seniority of five years' confirmed service are eligible for promotion or appointment as Head Clerk in the State Bank of India. The post of Head Clerk in the clerical wage scale attracts a monthly Special Allowance. The Special Allowance was previously Rs. 61 plus D.A. thereon per month from 1-1-70 to 31-8-78, Rs. 200 per month from

1-9-78 to 30-6-83, Rs. 325 per month from 1-7-83 to 31-10-87 and is now Rs. 380 per month from 1-11-87. The major portion of the Special Allowance payable is counted as pay for the purpose of superannuation benefits. The employees in clerical cadre having adequate seniority are promoted/appointed to the post of Head Clerk in the Bank and the seniority list is prepared for the purpose. No examination is held and no interview is taken to judge the suitability or ability of the clerks who are promoted as Head Clerk on account of the seniority alone. The eligible employees who refuse to accept the promotion/appointment as Head Clerk forfeit future chance for a period of one year from the date of such refusal. As per the rules obtaining at Patna circle of the Bank when the opportunity for appointment/promotion as Head Clerk comes to an employee and if there exists a simultaneous vacancy at the office where he is working or another office at the centre where he is posted, the employee is to be given option to make his choice of his posting. The concerned workman was eligible for promotion/appointment as Head Clerk. The then Agent (now designated as Branch Manager) of the then Bank of Behar Branch, Patna (now known as Judge's Court Road Branch, Patna) by Memorandum No. 89 dated 27-7-1971 asked him to submit his consent for acceptance or appointment as Head Clerk in the Bank. The concerned workman submitted his willingness for the said promotion. Even then he was not promoted as Head Clerk. His representations in this regard were ignored. Once again the Branch Manager concerned by Memorandum dated 29-10-82 informed him that he was suitable for promotion as Head Clerk. He again showed his willingness for the promotion, but the Bank did not promote him. All such letters seeking his consent for accepting the post of Head Clerk were simply eye-wash. As per the extant rule he was entitled to be promoted and posted as Head Clerk at Judges' Court Road Branch itself where he was/is working or at any other branch in the town of Patna, as per his choice. The Bank meanwhile promoted many juniors to him as Head Clerk at Judges' Court Road Branch and/or branches or offices in Patna urban agglomeration area or also in the Region/Zone in which the Judges' Court Road Branch falls. Even now the Bank is posting juniors as Head Clerk at Judges' Court Road Branch ignoring his seniority and his better claim to the post. He is being discriminated and subjected to unnecessary loss both in the matter of status and Special Allowance attached to the post of Head Clerk. He is being put to perpetual loss because of the Bank's annoyance against him for his trade union activities as the President of Bihar Provincial Bank Employees Association, the Bihar State Federation of A.I.B.E.A. which is not recognised by the Bank. The management of the Bank's malafide designs manifested against him by issuance of chargesheet against him for gross misconduct for attending a dharna before the gate of another Bank prior to the start of working hours of another Bank as well as the branch where he worked and despite the fact that he remained present throughout in his place of work during the working hours from 10.30 A.M. to 5.30 P.M. Participation in dharna without adversely affecting one's work in the Bank is not a misconduct, either gross or minor, in the Awards/Bipartite Settlements. The representations submitted by him from time to time with regard to denial of promotion have fallen on deaf ears and the management in pursuance of their anti-labour practice has not cared even to give reply. In the circumstances, he is entitled to promotion/appointment to the post of Head Clerk from the date he became eligible for such in July, 1971.

4. In rejoinder to the written statement of the sponsoring union, the management of the Bank has reiterated the stance it has taken in its written statement and asserted that the concerned workman was neither willing nor was he eligible for appointment/promotion to the post of Head Clerk. The management has asserted that it had acted bonafide and

disciplinary proceeding against the concerned workman is neither relevant nor has it any bearing on the issue involved in the present dispute. In the circumstances, the management of the Bank has prayed that the present reference be answered in its favour.

5. In rejoinder to the written statement, of the management, the sponsoring union has asserted that the management has failed to show that they had found the concerned workman unsuitable for the post of Head Clerk. The management has also failed to show that he ever refused the promotion. It is false to say that the concerned workman refused or was unwilling to accept the promotion.

6. The management, in support of its action has examined four witnesses, namely, MW-1 A. R. La, Branch Manager, State Bank of India, Judges' Court Road, Patna, MW-2 Poonam Narayan, Personnel Officer posted at Regional Office, State Bank of India, Patna, MW-3 S. K. Prasad, posted to Zonal Office at Patna and MW-4 Ramesh Jha, an Officer-in-charge the Branch Manager Secretariat at Judges' Court Road Branch at Patna and laid in evidence a sheaf of documents which have been marked Exts. M-1 to M-11.

On the other hand, the sponsoring union has examined four witnesses, namely, WW-1 T. P. Singh, Head Clerk of the Bank at Judges' Court Road Branch, Patna, WW-2 Umesh Prasad, WW-3 P. S. Pal, both employees of the Bank and WW-4 Kamla Prasad Singh, the concerned workman and laid in evidence a number of documents which have been marked Exts. W-1 to W-25.

7. Undeniably, K. P. Singh, the concerned workman joined the service of the erstwhile Bank of Behar Ltd. as Clerk on 1-5-64. The Bank of Behar Ltd. with all its assets and liabilities was amalgamated with State Bank of India in 1969 and the employees of this Bank, including the concerned workman were absorbed in the service of the State Bank of India and became the employees of State Bank of India with continuity of service. All conditions of service applicable to the employees of the State Bank of India were extended to the employees of the Bank of Behar Ltd. which amalgamated with the State Bank of India, with effect from 1-1-70. It follows, therefore, that although K. P. Singh, the concerned workman was employed in the erstwhile Bank of Behar as Clerk, he became the employee of State Bank of India on the amalgamation of the Bank of Behar Ltd. with State Bank of India in 1969 and all the conditions of service applicable to the employees of State Bank of India were extended to him with effect from 1-1-1970.

8. The present industrial dispute has been raised on the issue of promotion/appointment of K. P. Singh in the post of Head Clerk of the State Bank of India.

According to the sponsoring union, all the clerical staff who have required seniority of five years' confirmed service are eligible for promotion/appointment as Head Clerk in the State Bank of India. On the other hand, it is the firm case of the management that every clerical employee who have completed five years' of confirmed service and who are considered suitable are eligible for promotion/appointment in the post of Head Clerk provided he gives his consent in writing to accept such appointment/promotion and to serve in any office of the Bank in circle i.e. Bengal Circle 1971 and Patna circle in 1972. According to the union, in terms of rules obtaining in Patna circle, when the chance come to an employee for appointment/promotion as Head Clerk and if there was a simultaneous vacancy at the office where he is working or at another office at the centre where he is posted, the employee is to be given the option to make his choice of his office of posting. Circular Per. 36/79 dated 22-3-79 (Ext. W-3) envisages that Clerks, Clerk-Typists and Clerks-cum-Cashiers having five years' confirmed service as on 31-3-78 and who are considered suitable, may be appointed as Head Clerk. The Circular also envisages that the employees recommended for appointment as Head Clerk should be prepared to serve at any office of the Bank in the circle and written undertaking in this regard should be obtained from each of them. The earlier circular No. B. No. 124/68 dated 2-7-68 envisages that the written undertaking should be obtained to serve at any office of the Bank in or out of the State in which they were posted (Ext. M-1). It appears that by Circular Per No. 36/79 the employees were to submit

written undertaking to serve at any office of the Bank in the circle. But by another Circular Per No. 87/77 dated 4-8-77 the employees were given an option to make his choice of office of posting when there was a simultaneous vacancy at the office where he was working or at any office at the centre where he was posted Ext. (W-2). Thus, it appears from the documentary evidence as discussed above that the Clerks, Clerk-Typists and Clerk-cum-Cashiers having five years' confirmed service as on 31-3-79 and found suitable were eligible for promotion/appointment as Head Clerk provided they gave written undertaking to serve at any office of the Bank in the circle with an option to make their choice of office of posting when there was a simultaneous vacancy at the office where he was working or at another office at the circle where he was posted.

9. The Bank has asserted in its written statement that as per practice prevalent before August, 1977 refusal by an employee to accept promotion/appointment as Head Clerk was considered as refusal for all times to come and he was debarred from appointment/promotion in the post of Head Clerk for all times to come. Circular No. Per 68/79 dated 21-5-79 (Ext. W-4) envisages that the employees who are eligible to be recommended for appointment as Head Clerk, but are not willing to give consent for acceptance of the post of Head Clerk, a written statement should be obtained from them about such refusal and kept at the Branch. Circular No. Per 87/77 dated 4-8-77 (Ext. W-2) deals with the matter relating to refusal of promotion. The relevant portion of the circular is gleaned hereinbelow :

"F. Refusal of promotion as Head Clerk/Official-in-charge/Cashier-in-Charge of Cashiers.

According to the extant instructions, refusal by an employee to accept appointment at Head Clerk/Official-in-Charge/Cashier-in-Charge of Cash etc. is treated as his refusal for such appointment in future. It is, however, not clearly laid down as to what should be the period for which an employee should be debarred from such appointment/officiating chances in any higher capacity (including that of Sub-Accountant and Head Cashier) as a penalty for his first refusal. The matter was discussed at length and it was decided that the forfeiture of future chances to such employees for appointment/to officiate in higher capacities will continue for a period of one year from the date of his refusal. It was also agreed that in case an employee refused to accept appointment as Head Clerk, his refusal of Head Clerk's appointment will not be treated as his refusal for appointment as Official-in-Charge of Sub Office and vice-versa."

10. By Memorandum No. 89 dated 27-7-71 the then Agent of the Bank of Behar, Patna desired to know from the concerned workman whether he was willing to accept the appointment as Head Clerk and prepared to serve at any branch in or out of the State. The concerned workman was required to submit his acceptance or otherwise by 30-7-71 (Ext. W-7). Since at the time Circular No. B-124/86 dated 2-7-68 was in force the concerned workman was required to give his consent at any branch in or out of the State (Ext. M-1). The concerned workman signified his willingness by stating that he was prepared to be posted at any branch as per rules of the Bank by letter dated 27-7-71 (Ext. W-13). By another letter dated 30-7-71 the concerned workman intimated the Agent that the contents of the letter of the Agent were quite different from the practice of the Bank for inviting consent of the employees. He complained that offer of the management is just an eye-wash (Ext. W-14). It appears that he wrote a series of letters on the matter to the management on different dates, such as, 11-8-73 (Ext. W-15), 8-2-76 (Ext. W-16) and 19-5-78 (Ext. M-8). The concerned workman informed the branch Manager by letter dated 19-5-78 that every time he was offered the appointment of Head Clerk with order of posting at one or the other branch far off from Patna ignoring his claim for posting at Judges' Court Road. The evidence on record reveals that he was posted to Warisaliganj Branch as Head Clerk. But he did not join his posting there. At the time of hearing he has asserted that he was not released from Judges' Court Road Branch at Patna. But this important fact has not been pleaded in the pleading nor was it suggested to the witness for the management. It appears that consequent upon his failure to join

as Head Clerk at Warisaliganj Branch within the stipulated time, the offer of appointment/promotion as Head Clerk to Shri Singh was withdrawn (Ext. M-10).

By another undated memorandum issued sometime in the early part of 1979, the concerned workman and others who completed five years' confirmed service as on 31-3-79 and were otherwise eligible for appointment as Head Clerk who were willing to serve any office of the Bank in the circle were requested to fill up column against their names to facilitate preparation and submission of the statement of the local Head Office at an early date (Ext. M-9). The name of the concerned workman appears at serial No. 10. No entry has been made against him in the right hand column. But in the left hand column there is an endorsement of R. R. Dubey, who was the officer-in-charge in the Branch Secretariat in 1979. Shri Dubey purported to have made the following endorsements in his own handwriting :

"He refused to sign this, rather he behaved in an indecent manner. As such, I am not submitting his name as he declined to give his consent to serve anywhere in the circle."

This endorsement was made on 25-4-79 (Ext. M-9/1). The management has relied on this endorsement while the union has assailed this endorsement tooth and nail.

11. In terms of Circular No. Per. 36/79 dated 22-3-79 (Ext. W-3) the employees recommended for appointment as Head Clerk were required to give a written undertaking of his willingness to serve at any office of the Bank in the circle. It appears that the Branch Manager prepared a format of his own to get the willingness or otherwise of the employees with regard to the matter of posting after appointment as Head Clerk. The concerned workman has firmly stated that the memorandum was not shown to him. In the circumstances, Shri Dubey was the best witness to vouch for the fact about the indecent behaviour of the concerned workman and of his unwillingness to serve anywhere in the circle. But he has not been examined by the management. Shri Dubey, from the evidence on record it appears, has retired from service. Management's own witness MW-4 Ramesh Jha has stated that Shri Dubey was pro-management and that he used to come to office during the strike by boat from the Ganges side. After retirement Shri Dubey has been working in the State Bank of India Staff Association which is a rival union to the union which has sponsored the present dispute. In the circumstances, I consider that the examination of Shri Dubey was essential. But the management has not examined him for the reason best known to it. Besides, had the concerned workman mis-behaved with Shri Dubey the management was within its rights to proceed against him for misconduct in domestic proceeding. There is no evidence that the management did so. This again gives rise to the conclusion that the endorsement of Shri Dubey is not free from suspicion. Taking the entire facts and circumstances into consideration, I am not prepared to accept Shri Dubey's endorsement on Ext. M-9/1 on the memorandum Ext. M-9 as refusal on the part of the concerned workman to accept the offer of promotion/appointment as Head Clerk in the circle.

12. I have already pointed out from Circular No. Per. 87/77 dated 4-8-77 that consequent upon refusal by an employee to accept appointment as Head Clerk/Official Incharge/Cashier Incharge of cash the forfeiture of future chance for appointment/posting in higher capacity would continue for a period of one year from the date of his refusal. Even if it is considered that the concerned workman refused promotion/appointment as Head Clerk in July, 1971, even then he was entitled to promotion in 1979 when the embargo on his appointment/promotion as Head Clerk was lifted long ago. He was under no cloud in 1979 as there was no domestic proceeding pending against him. It is also established by evidence on record that some employees junior to the concerned workmen have already been promoted/appointed as Head Clerk. Considering all the facts and circumstances, I am of the firm opinion that the case of the concerned workman for appointment/promotion as Head Clerk should be considered by the management in terms of the undated memorandum (Ext. M-9).

13. Accordingly, the following award is rendered—

the action of the management of State Bank of India,

Patna, in not promoting Shri K. P. Singh with retrospective effect is not justified. The management is directed to consider his case for promotion/appointment as Head Clerk in terms of undated memorandum (Ext. M-9).

In the circumstances of the case, I award no cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

का. आ. 1559.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सै. भारत कोकिंग कोल लि. की आकाश-किनारी को, के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19 मई 1992 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012/259/86-डी 3(ए)]

वी. के. वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1559.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Akashkinaree Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 19-5-1992.

[No. L-20012(259)/86-D.III (A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

Reference No. 33 of 1987

PARTIES :

Employers in relation to the management of Akashkinaree Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri J. P. Singh, Advocate.

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advocate

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the May, 1992

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(259)/86-D.III (A), dated, the December, 1986.

SCHEDULE

“Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh that the management of Akashkinaree Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited should allow resumption of duty by Shri Sheo Shankar Prasad who claimed to have previously worked as a General Mazdoor in North Tetulia Section of the said Colliery is justified? If so, to what relief is this workman entitled?”

2. Shri Sheo Shankar Prasad the concerned workman claims to have been appointed as General Mazdoor in North Tetulia Colliery section with effect from 5-4-71 by the then Manager of the Colliery but all of a sudden he was stated to have been illegally stopped from his work with effect from 25-4-73 without any reason. He has prayed for his resumption of duty with full back wages for the reasons stated in his W.S.

3. Admittedly North Tetulia Colliery was a non-coking coal mines the management of which was taken over by the Central Government on 31-1-73 but it was nationalised with effect from 1-5-73. The concerned workman has denied to be an inductee and claimed to have been appointed by the then Manager of the North Tetulia Colliery. It was stated that he was put in service for more than a year and so his stoppage without compliance of the provision of Section 25-F of the I. D. Act, 1947 was illegal and void. His stoppage from the work amounts to termination. The termination of the service as alleged was illegal on the ground that no show cause notice was given to the concerned workman to explain the allegation of being inductee. It was stated that the concerned workman has all along been filling representation to the authorities concerned but it was of no effect and hence he raised industrial dispute giving rise to the present reference.

4. According to the management the reference being over-stale is liable to be rejected.

5. The management of Akashkinaree Colliery was taken over by the Custodian General with effect from 31-1-83 it was nationalised with effect from 1-5-73. The management stated that there was a screening committee in which the concerned workman was screened out being inductee for he had fraudulently managed to enter the services of the Colliery after take over. According to the management he was never employed in Akashkinaree Colliery prior to take over on 31-1-73. The concerned workman being inductee was stopped from his work. It was stated that in case of illegal stoppage there was a provision for appeal before the Dy./Additional Custodian General and the concerned workman never filed any such appeal. Since he was not an employee it was not necessary at all to follow the provision contained in Section 25-F of the I. D. Act, 1947.

6. The point for consideration would be as to whether the concerned workman was an employee of North Tetulia Colliery prior to take over of the Colliery with effect from 31-1-73 and if so whether he is entitled for the relief claimed by him.

7. The management says that the concerned workman was an inductee who fraudulently managed to enter the services of the Colliery after it was taken over and was screened out prior to nationalisation which took place on 1-5-73. The concerned workman has got proved certain documents to prove that he was an employee of the Colliery prior to 31-1-73, and even thereafter till he was stopped on 25-4-73. Ext. W-1 is the photo copy of the appointment letter dated 5-4-71 issued by the Manager North Tetulia Colliery. During the course of argument the original appointment letter was also produced just for the perusal of the Court which was subsequently returned to the concerned workman, I have examined the document and prima facie I do not see any reason to disbelieve it. Apart from that some other documents have also been filed to prove this fact. The concerned workman while in employment had filed different applications before the Manager sometimes for grant of casual leave and also for grant of due wages. Ext. W-2 is an application for casual leave. Ext. W-3 is an application for back wages. Ext. W-4 is a letter addressed to the concerned workman by the Manager North Tetulia Colliery requiring him to produce medical certificate with reference to his illness. Ext. W-5 is a sort of warning by the Manager. Ext. W-5.1 is an order dated 7-2-72 whereby the concerned

workman was transferred to Cap Lamp room. Ext. W-6 is an application by the concerned workman with a request to permit him to join the duty after his illness. Ext. W-6/1 is an application for advance of Rs. 40 and it is dated 19-7-72. All these documents which are photo copies prima facie go to show that the concerned workman was under the employment of North Tetulia Colliery prior to its take over by the Central Government. Definitely originals have not been produced but for these reasons it cannot be said that they are all manufactured papers.

8. In this connection I may also refer to the evidence of WW-1 Sri Yashvir Chakravorty a retired employee of North Tetulia Colliery. He was knowing the concerned workman and according to him he was working from before the nationalisation. The witness Shri Chakravorty was Overman Incharge prior to nationalisation and in the said capacity he had occasion to know the concerned workman. He emphatically stated that the concerned workman was appointed in April, 1971 as General Mazdoor. He also stated that prior to nationalisation the concerned workman continuously discharged his duties as General Mazdoor. He has proved the appointment letter which has already been marked as Ext. W-1. He has also proved other documents which have already been dealt with. The witness has been cross-examined and apparently nothing has been elicited to disbelieve his credence. It has been suggested to the witness that Ext. W-1 was forged document. I find that nothing has been shown to brand the document as forged one. WW-2 is the concerned workman. He has stated his case as to how he was stopped from his work although he had been working in the Colliery as General Mazdoor since before it was taken over. He has also proved a number of documents which have been marked Ext. W-7 to W-16. However, he has denied the suggestion thrown to him that he managed his entry from the back door after take over of the Colliery.

9. After having discussed the evidence both oral and documentary I have no reason to entertain any doubt that the concerned workman was not an employee of the Colliery prior to its take over. WW-1 has stated that after take over there was a screening of the workmen and the persons whose names were entered in Form B Register and who were having C.M.P.F. No. were taken into service. From the record I find that the concerned workman had called for the report of the screening committee and Form B Register from the management but the same could not be made available for the reasons that the documents were disposed off being old. Ext. W-2 is a photo copy of the C.M.P.F. A/cs, No, of the workmen. The name of the concerned workman does not figure anywhere in the document. However the witness has stated that no C.M.P.F. No. was allotted to any employee on the other hand the learned counsel produced before me the relevant provision to show that the workmen are necessarily required to get C.M.P.F. No. after certain days of their employment. It was urged that since the concerned workman was not a member of the C.M.P.F. he was not an employee rather an inductee. Ext. M-1 is the photo copy of the Contribution card for the period from April, 70 to March, 71. It may be noted that the concerned workman was appointed in April, 1971 and so the document has got no relevancy. Ext. M-3 is the photo copy of the order dated 25-4-73 and the Manager of the Colliery stopped the concerned workman from his work because he was found inductee by the screening committee. Thus it is true that the concerned workman was not a member of the C.M.P.F. but we are not sure whether his name figured in the Form B Register or not. I think that any benefit to be driven in the situation must go to the concerned workman. At this very stage I may refer to the evidence of WW-2 who stated that his name was registered in the Form B Register. However, the learned counsel for the workmen urged that the concerned workman was under the employment hardly for 2 years and just possibly during this period he might not have contributed to the CMPPF. But that alone cannot be taken a ground to disbelieve all of the documents favourable to the concerned workman. I think the contention as raised by the learned counsel should not be completely brushed aside. For the reasons stated above I am to hold that the concerned workman was an employee of the Colliery before and after it was taken over by the Central Government.

10. It has been urged on behalf of the management that the concerned workman was stopped in the year 1973 and

the reference was made in 1987 say after 14 years. The reference being overstate is bad in law and not maintainable. Contrary to that the concerned workman has proved certain documents (Ext. W-8 to W-15 series) just to show that after stoppage he was not sitting idle rather he had been corresponding with the concerned authorities for his employment. Ext. W-15/3 may be referred to. This is an application by the concerned workman dated 1-3-79 with a request to the General Manager for his employment. Ext. W-15/4 is the photo copy of the letter dated 20-10-75. The concerned workman had written to the Director of Personnel with a request to allow him to resume his duty. Similarly Ext. W-15/5 is the letter dated 20-12-75 written to the Director of Personnel. Ext. W-15/6 is again a request letter written to the Director of Personnel and it is dated 1-12-75. All these documents simply show that the concerned workman was himself anxious to join his duties after his stoppage and he had written several letters to the authorities concerned. After that the case of the concerned workman was taken up by the Union and necessary correspondence was made with the concerned authorities. Ext. W-12/1 and Ext. W-13 are the letters by the union to the General Manager (Personnel) with a request to provide employment to the concerned workman. Lastly the dispute was raised when Shri Ajab Lal Sharma Organising Secretary wrote a letter dated 29-11-75 to the ALC (C) for conciliation (Ext. W-8). Ext. W-9 is the rejoinder to the comments of the management which was addressed to the ALC (C). In para-4 of the document it has been stated that in all five workmen were stopped including the concerned workmen but all except the concerned workman were taken in. I think this aspect of the matter has not been denied by the management. Ext. W-17 is the screening report which will show that five persons named in the report including the concerned workman were screened out. I find no reason as to why the case of the concerned workman was not considered when all others placed in the similarly situation were taken into the employment. From this document we find that the concerned workman after his stoppage was not sitting idle. Necessary correspondence were made by himself and the union and ultimately industrial dispute was raised in November, 1975. In this way one can say that there was delay of 3 years in raising the dispute. This delay cannot be given a bad name of overstate dispute.

11. A certified copy of the judgement of the Hon'ble Patna High Court vide C.W.J.C. No. 2187 of 1989 (R) has been filed. That was a case in which the dispute was raised after 7 years without any reasonable excuse and the appropriate Government had refused to refer the dispute to the Tribunal on the ground that the claim became overstate. Here in the instant case as discussed above, the dispute was raised only within 3 years time but the reference was made in 1987. Even before and after raising the dispute the concerned workman had been taken every step to get employment. There is yet another authority cited by and on behalf of the management and i.e. the certified copy of the judgement passed in CWC No. 747 of 1988 (R). The Hon'ble Court held that the substituted section 14 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 came into force with effect from 1-5-73 and as for the workmen were not in employment in the Coal Mines in question on the appointed day i.e. 1-5-73, the respondent No. 2 could not have directed for their reinstatement.

12. In the instant case I have already held that the concerned workman was under the employment in flesh and blood prior to take over of the Colliery and so the facts and circumstances of this case cannot be made applicable with the facts and circumstances of the authorities cited above.

13. I have considered all these aspects of the matter and I am to hold that the concerned workman was a General Mazdoor in North Tetulia Colliery from before its management was taken over by the Central Government. Even thereafter he worked for few months before the Colliery was nationalised but it is true that the concerned workman remained out of duty for a pretty long time and in the situation I do not think it fair and proper to grant him any back wages for the whole of 17 years. In my opinion reinstatement of the concerned workman in service as General Mazdoor in Cat. I without any back wages will meet the ends of justice. Under the circumstances the management

is directed to reinstate the concerned workman as General Manager in Cat. I within one month from the date of publication of the Award and there will be no order for back wages.

B. RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

का. आ. 1560.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. भारत कोकिंग कोल लि. पुतकी कोलियरी, भागबंद क्षेत्र 8 के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-5-1992 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/176/85-डी 3(ए)]
जी. के. वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1560.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Putkee Colliery in Bhagaband Area-VIII of M/s. B.C.C. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 18-5-92.

[No. L-20012(176)|85-D.III(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) at DHANBAD PRESENT :

Shri B. Ram.—Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

REFERENCE NO. 19 OF 1986

PARTIES :

Employers in relation to the management of Putkee Colliery in Bhagaband Area-VIII of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen.—Shri D. K. Verma, Advocate.

On behalf of the employers.—Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 7th May, 1992

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Sec-

tion 10(1)(d) of the I. D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(176)|85-D.III(A), dated, the 6th January, 1986.

SCHEDULE

“Whether the demand of Colliery Karamchari Sangh that S/Sh. Ramdhani Hazam, Jagdish Mahato, Kishan Hazam, Suresh Prasad, Mahendra Sonar and Narain Mahato, working as Water Suppliers at Putkee Colliery in Bhagaband Area-VII of M/s. Bharat Coking Coal Limited, should be treated as Management's workman and said Category-I wages under the Central Coal Wage Board recommendations is justified? If so, to what relief the concerned workmen are entitled and from what date?”.

2. The concerned workman 6 in Number claim to be treated as workmen of the management of BCCL on the ground that they have been working as Water Carrier and supplying water to the employees of Putkee colliery in Bhagaband Area No. VII of M/s. BCCL for the last 12 years. These workmen were paid through vouchers by the management as piece rated workmen.

3. It was stated that many of the collieries of BCCL the water suppliers doing the similar jobs have been treated as regular employees of BCCL and they are also being paid wages as per Coal Wage Board recommendation. The concerned workmen made several approaches to the management for their regularisation and for payment of their proper wages, but it was of no use. The union namely the Colliery Karamchari Sangh raised the industrial dispute before the ALC(C) but the same was withdrawn on 31-12-81 on the assurance given by the management that the dispute will be resolved mutually. But the concerned workmen could not be regularised inspite of the assurance and ultimately the dispute had to be raised again before the ALC(C), Dhanbad. Before the ALC(C) the management took the plea that there was no relationship of master and servant between the management and the concerned workmen and thus the conciliation proceeding ended in failure.

4. The management by filling W.S. has denied the relationship of employer and employee between the management and the concerned workmen. It was stated that the management had made elaborate arrangement for supplying of drinking water to the workmen and office staff at their place of work. Suitable arrangement have also been made at the quarters and at common points to facilitate fetching waters to the respective quarters. But, however, in some places it has not been made possible to supply water to the labour and staff quarters.

5. It was stated that the management has no obligation to supply waters on the residential quarters or to pay any amount to the staff and workers in lieu of not providing water at the quarter but as the management has provided water arrangement at most of the places, it agreed to pay certain amount to certain staff and workmen for making arrangement for water supply at their quarters. It is further stated that the staff made some arrangement with different

water suppliers for supplying waters at their residential quarters and requested the management to pay @Rs. 1 per bhar of 2 tins of water supplied to them. It was stated that the concerned workmen are water suppliers and they also supply to the general public at the residential quarters and they are paid accordingly.

6. The management has not recruited the concerned persons and thus they are not under the control and supervision of the management. In such view of the matter it has been prayed that the award be passed accordingly.

7. The main point for consideration is whether there was any relationship of employer and employee between the management and the concerned workmen. No paper worth the name has been filed on behalf of the concerned workmen that they were ever employed by the management. No appointment letter was issued to them. Their names were never registered in the Form B Register. They were never also issued with identity card. The only paper relied upon are some vouchers. They claimed to have been paid through the vouchers by the management. The vouchers have been filed on behalf of the management just to show that the concerned workmen had been supplying drinking waters to the workers and staff quarters and the payment was made by the management for the sake of convenience. It was also pointed out that it was only part time work. Ext. M-1 is the vouchers relating to Kishun Hazam one of the concerned person. It is for the period from 1-6-85 to 15-6-85. During this fortnight period he had supplied 560 tins of water to the different staff. As per Ext. M-2, accordingly one bhar contains 2 tins of water. This means that Shri Kishun Hazam carried 280 bhars of water in 15 days. If divided by 15 it will come to about 18 bhars of water per day. I do not think that supply of 18 bhars of water will be the full day work. Similarly Jagdish Mahato one of the concerned workmen supplied 741 tins of drinking water in 15 days. This means he supplied 370 bhars in 15 days i.e. about 25 bhars per day. This also cannot be said whole time work. The evidence has been led on behalf of the workman that the concerned workmen had to cover a distance of about 2 K.M. to carry the drinking water but this fact has been denied by the management through suggestion. It does not stand to my reason as to how the quarters will be constructed and there will be no provision for water and that too the water will be at a distance of about 2 K.M. Thus I am to hold that the concerned workmen were part time workers definitely engaged by the staff and workmen of Area No. VII. Decidedly the management cannot engage anybody as part time worker because the part time employment is in consistent with the relationship of employer and employee and therefore the concerned workmen cannot be the employees within the meaning of Industrial Dispute Act. Consequently if anybody is not an employee within the meaning of the Act then the reference cannot be made to the Tribunal for adjudication and passing any award. I think mere payment by the management cannot create any right with the concerned workmen for their entitlement as Cat. I Mazdoor.

8. Again the concerned workmen cannot be said to be employed by or in connection with the mine. They have been supplying water to the staff quarters and such act has nothing to do with the mine or the mining operation. The position of the concerned workmen cannot be quated with other employees like clerks and peons of the mining industry because they all work in the union towards the fulfilment of any object. Contrary to that the concerned workmen are water carrier and they have little to do with the work of the staff and employees who are engaged in mining work.

9. Two witnesses have been examined on behalf of the workmen. WW-1 Shri Jagdish Mahato is one of the concerned workmen. He has stated to have been supplying water for the last 10 years and now he is sitting idle for 11 year. He was examined in 1988. The witness cannot say the year from which he had been supplying water. According to him the quarters were newly constructed. He also stated that he had been carrying drinking water from the distance of 2 K.M. However, according to MW-1 WW-1 there is seprate provision for supply of water to the officers and class III employees. Be that as it may we find from Ext. W-1 that drinking water was needed by the staff and it was supplied by the concerned workmen. But the question is if these workmen were ever engaged by the management. If the management had any control or supervision over these persons. The simple answer will be negative. No paper, no appointment letter, no identity card and nothing of the sort had been filed to given a link between the employer and the employee. WW-2 Kumar Arjun Singh was the Provincial Secretary of Dhanbad Colliery Karmachari Sangh and he had raised industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad. According to him the management had assured him during the conciliation proceeding that the concerned workmen will be regularised but no such paper has been brought on the record to substantiate this fact. However, he has proved the photo copy of the minutes of the discussion held between the RCMS Union and the management of Bhagabad Area which is Ext. W-1. This paper has been filed just to show the management has considered the case of one Shri Sheo Shankar Ram Waterman of Area No. VII who had been paid on voucher by the management for the last several years. I do not think this will be of any help to the concerned workmen. There is nothing before us as to what was the consideration which promoted the managment to regularise Shri Sheo Shankar Ram the Waterman From this paper it is not clear that he was not in possession of any paper like appointment letter, identity card or any oher paper just to show the relationship between the management and the workman. In the instance case we find thae there is no paper just to establish the relationship of employer and employee between the management and the concerned persons. For the reasons stated I am to hold the view that the concerned have got no case and they are not entitled for their regularised as Cat. I Mazdoor.

In the result, I hold that the demand of Colliery Karmachari Sangh that ShShri Mardhani Hazem, Jagdish Mahato, Kishan Hazam, Suresh Prasad, Mahendra Sonar and Narain Mahato, working as

Water Suppliers at Putkee Colliery in Bhagaband Area No. VII of M/s. Bharat Coking Coal Limited should be treated as Management's workmen and paid category-I wages under the Central Coal Wage Board recommendation is not justified. Consequently the concerned workmen are not entitled to any relief.

This is my Award.

B. RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, २१ मई, १९९२

का. आ. १५६१.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) की धारा १७ के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. की कुस्तोर कोलियरी क्षेत्र के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. २) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को १५-५-९२ को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-२००१२/१५६/८५-डी-३ (ए)]

वी. के. वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1561.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Management of Kustore Colly. in Area No. VIII of M/s. B. C. C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 15-5-92.

[No. L-20012(156)|85-D.III(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD
PRESENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 42 of 1986

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kustore Colliery in Area No. VIII of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri B. K. Ghosh, Member, Executive Committee, Janta Mazdoor Sangh.

On behalf of the employers : Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 30th April, 1992

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(156)|85-D.III(A), dated, the 17th January, 1986.

THE SCHEDULE

"Whether the demand of Janta Mazdoor Sangh that the management of Kustore Colliery in Area No. VIII of M/s. Bharat Coking Coal Limited should regularise their workman, Shri Bijay Kumar Singh as Pump Khalasi in Category-IV with retrospective effect, is justified? If so, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. In this case both the parties appeared and filed their respective W. S. documents. Thereafter the case proceeded along its course. Subsequently at the stage of oral evidence Shri B. K. Ghosh, Member, Executive Committee, Janta Mazdoor Sangh appeared and submitted before me that the concerned workman does not appear to be interested in the case. Since the workman and his union does not appear to be interested with the reference, I am constrained to pass 'No dispute' Award in the reference.

B. RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, २१ मई, १९९२

का. आ. १५६२.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) की धारा १७ के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी. सी. सी. एल. लि. की तिसरा कोलियरी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. १) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को १४ मई, १९९२ को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-२००१२/१४१/८८-डी३(ए)डी४-४(ए)]

वी. के. वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1562.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of North Tisra Colly. of M/s. B.C.C. Ltd. and their workmen which was received by the Central Government on 14-5-1992.

[No. L-20012(141)|88-D.3(A)|D-4(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d)
of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 30 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of
North Tisra Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen : Shri D. K. Verma, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, the 29th April, 1992

AWARD

By Order No. L-20012/14/33-D. 3(A)/D. 4(A), dated, the 10th March, 1989, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.

"Whether the action of the management of North Tisra Colliery under Lodna Area No. X of M/s. BCCL in dismissing Shri Mahesh Tiwari, Magazine Clerk vide their letter No. BCCL/NTC/PER/87/1904 dated 5-8-87 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The case of the management of North Tisra Colliery as disclosed in the written statement-cum-reply, details apart, is as follows :

The concerned workman, Mahesh Tiwari, was working as Magazine Clerk of the Magazine of North Tisra Colliery. On 17-11-86 he was deputed as Magazine Clerk of the Magazine in the 2nd shift commencing from 4 P.M. and ending at 12 mid-night. On that date during the end shift 7500 coal delay detonators valued at Rs. 23,200 were stolen away from the magazine by some anti-social elements. The concerned workman left his duty without prior permission and without being relieved by another Magazine Clerk duly authorised as competent person under Regulation 36 of Coal Mines Regulations, 1957. Thus, the concerned workman acted as an abettor in commission of the theft, alternately he committed negligence of serious type in view of the fact that the detonators are high explosives capable of detonating with supersonic speed and can be used by anti-social elements in terrorist and mafia activities. The com-

licity of the concerned workmen with some mafia activities cannot be ruled out. A chargesheet dated 18-11-1986 was issued to him for commission of misconduct of neglect of work and also for commission of abetment of theft of 7500 detonators during his duty hours on 17-11-86 at the magazine in the capacity of Magazine Clerk. As there is no certified Standing Orders in the colliery, he was charged under the Model Standing Orders. The concerned workman submitted his reply on 22-11-86 denying the allegations of complicity in the commission of theft and expressing his helplessness in preventing the theft. He attempted to justify his absence from duty for few hours on some medical ground. Another workman, named Nepal Singh, a Night Guard on duty during relevant time on 17-11-86 was also issued with similar chargesheet for his complicity in the theft in question as well as negligence of his duty. He submitted his reply to the chargesheet. But the replies of these two workmen were not found satisfactory and a joint enquiry was held by Sri P. K. Singh, the then Senior Personnel Officer of Jayrampur Colliery. Jayrampur Colliery and North Tisra Colliery fall within the jurisdiction of the same General Manager of Lodna Area. The General Manager of Lodna Area approved of the appointment of Shri P. K. Singh as Enquiry Officer. The Enquiry Officer held the enquiry after giving notice to the concerned workman. He conducted the enquiry in conformance to the principles of natural justice. He submitted his report to the Agent along with enquiry proceedings and other papers. He considered the materials on record and gave his findings holding that the concerned workmen were guilty of misconduct of negligence of duty and abetment of theft. The enquiry report, the enquiry proceedings and other relevant papers were examined by the Agent; he concurred with the findings of the Enquiry Officer. He recommended for dismissal of the chargesheeted workmen and put up all relevant papers before the Chief Mining Engineer/General Manager seeking his approval for dismissal of the chargesheeted workmen. The General Manager/C.M.E. approved the dismissal of the chargesheeted workmen from service. Accordingly, both the chargesheeted concerned workmen including the concerned workmen were dismissed from service by order dated 5-8-87 of the Agent with immediate effect. In the circumstances, the management has prayed that its action in dismissing the concerned workman from service is legal, bonafide and in accordance with the Standing Orders.

3 The case of the concerned workman, as disclosed in the written statement submitted by him is as follows :

He was a Magazine Clerk of North Tisra Colliery. He was chargesheeted by the Agent Superintendent of North Tisra Colliery by memorandum dated 18-11-1986. He replied to the chargesheet by his letter dated 21/22-11-86. The allegation in the chargesheet was that on 17-11-86, while he was on duty from 7 P.M. to 3 A.M. at Magazine situated in Pure Goluckdih Section of North Tisra Colliery as Magazine Clerk, theft of 7,500 Coal Delay Detonators valued approximately, Rs. 23,200 took place due to his negligence of duty. He denied the allegation in the chargesheet stating that the charge of negligence

was vague and misleading. The chargesheet did not disclose what were the acts of commission or omission attributed to constitute negligence of duty on his part. He was highly prejudiced in his defence on account of vagueness of charge of negligence of duty. After submission of his reply, the management instituted an enquiry without properly appreciating his reply. He asked for supply of copy of relevant paper but the same was not provided to him. He wanted to examine certain material witness, but the same was not allowed to him. He has alleged that the Enquiry Officer has violated the principles of natural justice in holding the domestic enquiry and gave a perverse finding. Anyway, he was dismissed from service by the Agent of North Tisra Colliery by order dated 5-8-1987. The Enquiry Officer found him guilty also of misconduct of abetment of theft; he had given his finding that the misconduct proved also covered abetment of fraud and dishonesty. The Agent also took into consideration the said finding of abetment of theft, dishonesty and fraud. There was no charge of theft, dishonesty and fraud against him. Hence, finding of the Enquiry Officer is not only perverse but totally unjustified. The management has failed to consider his long years of unblemished service while inflicting punishment on him. The officers of the management told him that the management would not lose anything if they had to reinstate him in service by order of a competent court as he had 17 days left to reach the age of superannuation. In the circumstances, the concerned workman has prayed that the action of the management in dismissing him from service be held to be unjustified.

4. In rejoinder to the written statement of the concerned workman, the management has asserted the statements of facts as disclosed in its written statement and stated that the concerned workman was the Magazine Clerk on duty to maintain account of explosive cartridges and detonators and issue the materials on proper requisitions. He was to remain at the magazine and to keep the materials of the magazine in his custody during the entire period of 2nd shift of 17-11-86. During the 2nd shift 7,500 coal delay detonators of the magazine were stolen away. These facts have been stated in the charge-sheet and the natural inference is that the concerned workman might have abetted the theft by becoming a party or was negligent of duty which could only happen if he was not on duty leaving the explosives and detonator without the charge of any other explosive clerk or was sleeping on duty. It was for him to explain the circumstances under which he committed the negligence of duty or became a party to theft of highly explosive materials. The chargesheet was not vague and the concerned workman was not prejudiced in his defence. The enquiry was held in conformance to the principles of natural justice.

5. At the instance of the management, the fairness and propriety of the domestic enquiry was considered as preliminary issue.

The management examined the Enquiry Officer Shri P. K. Singh as MW-1 and laid in evidence the entire domestic enquiry proceedings, report of the Enquiry Officer and order of dismissal of the concerned

workmen from service which have been marked Exts. M-1 to M-14.

The concerned workman did not examine himself nor did he adduce any documentary evidence.

Upon consideration of the evidence on record and hearing both the parties, it was held that the domestic enquiry was held fairly and properly. Thereafter, the matter was heard on merits.

6. Undeniably, Shri Mahesh Tiwari, the concerned workman was the Magazine Clerk and Shri Nepal Singh was the Night Guard of the North Tisra Colliery. There is no dispute that on 17-11-86 the concerned workman, Mahesh Tiwari, was deputed for duty as Magazine Clerk of the magazine situated in Pure Goluckdih Section of North Tisra Colliery from 7 P.M. to 3 A.M. of 18-11-86. It appears from the evidence on record that Nepal Singh, Night Guard of the colliery was deployed for duty on 17-11-86 in the 2nd shift from 4 P.M. to 12 midnight at the magazine situated at Pure Goluckdih Section of North Tisra Colliery. It is the irrefragable position that a theft in respect of 7,500 coal delay detonators valued Rs. 23,200 was committed and in the circumstances the concerned workman and Nepal Singh were visited with similar chargesheet. The chargesheet issued against the concerned workman is reproduced hereinbelow (Ext. M-1) :

"It has been reported that on Monday the 17th November, 1986 while you were on duty from 7.00 P.M. to 3.00 A.M. (of 18-11-86) at Magazine situated in Pure Goluckdih Section of North Tisra Colliery, theft of 7,500 (Seven thousand five hundred) Coal Delay Detonators valued approximately Rs. 23,200 (Twenty three thousand two hundred) only took place due to your negligence on duty. Due to your negligence of duty heavy loss was caused to the company.

Your aforesaid act amounts to misconduct under Model Standing Orders applicable to workmen of North Tisra Colliery or any other standing orders or otherwise. The specific provision under standing order 17 attracted are read as under :

17—(1)(f) : Neglect of work.

17—(1)(u) : Abetment or attempt of abetment of any of the acts of misconduct.

You are required to explain in writing within 72 (Seventy two) hours of the receipt of this chargesheet as to why disciplinary action should not be taken against you.

You are suspended from your duty forthwith till further orders."

Both the concerned workman and Nepal Singh submitted replies to the chargesheet denying the charges. The reply of the concerned workman to the chargesheet has been marked as Ext. M-2. The concerned workman has complained in his reply that the charge of neglect of work and abetment or attempt of abetment of any acts of misconduct under clause 17(i)(f) and 17(i)(u) of the Standing Orders were vague as no material particulars of acts of negligence or abet-

ment were disclosed in the chargesheet. He complained in his reply that the names of the witnesses and the documents on the basis of which the chargesheet was issued were not mentioned in the chargesheet.

7. Shri D. K. Verma, Advocate, for the concerned workmen submitted that the chargesheet issued against the concerned workman suffers from the infirmity of vagueness as the manner in which the concerned workman allegedly committed negligence of work or abetted or attempted to abet any acts of misconduct has not been disclosed therein. He has further submitted that the concerned workman, in the circumstances, was prejudiced in his defence.

Shri B. Joshi, learned Advocate for the management, has contended that since the theft was committed during the duty hours of the concerned workman, the natural presumption is that the concerned workman might have abetted the theft or was neglect of duty.

8. The charge shall contain such particulars as to time and place of the alleged offence and the thing in respect of which it was committed as are reasonably sufficient to give the person proceeded against of the matter with which he is charged. In the present case the chargesheet discloses to time and place of the alleged offence and the thing in respect of which it was committed. But where the nature of the case is such with the particulars mentioned above do not give the persons proceeded against sufficient notice of the matter with which he is charge, the charge shall also contain such particulars of the manner in which alleged offence was committed as will be sufficient for the purpose. In the present case the chargesheet does not disclose the manner in which the concerned workman committed the misconduct of neglect of work. But the chargesheet discloses that he committed abetment or attempted to abet misconduct of theft. But no omission to state the offence or particulars thereof shall be regarded at any stage of the case material unless the person proceeded against was, in fact, misled by such omission and it has occasioned a failure of justice.

9. The proceeding of the domestic enquiry reveals that the Enquiry Officer read over and explained the chargesheet to the concerned workman and Nepal Singh, Night Guard. Shri S. C. Goenka was the Presenting Officer for the management. His evidence discloses that due to negligence of the concerned workman and Nepal Singh theft had taken place and that both of them connived at the offence of theft. He explained in his testimony that the concerned workman was negligent in his duty by leaving his place of duty without any intimation to the Agent or to any competent person. It appears that during the absence of the concerned workman the theft took place. As Presenting Officer he relied on the written complaint of Nand Kishore Singh, the report submitted by Ashok Kumar Choudhury and Paramhana Singh, F.I.R. report lodged to the police, and report of CISF. The concerned workman cross-examined Goenka at length. He also cross-examined the other witnesses for the management. He made his own statement in support of his contention that he did not commit the misconduct of neglect of work. This being he position, I came to the conclusion that although the chargesheet does not disclose in which manner he committed the

misconduct of neglect of work, he was not misled by such omission and there was no failure of justice. This being the legal position, I over-rule the contention of Shri Verma that the chargesheet suffers from the infirmity of vagueness.

As per Nomenclature, Job description and Categorisation of Coal Employees issued by Joint Bipartite Committee for the Coal Industry Magazine Clerks are placed in clerical Grade-III. As a Magazine Clerk it was the duty of the concerned workman to maintain account of explosive cartridges and detonators and issue materials on proper requisition. Admittedly, the concerned workman was deputed for duty in the magazine of North Tisra colliery situated in Pure Goluckdih Section of the said colliery from 7 P.M. of 17-11-86 to 3 P.M. of 18-11-86. The evidence of the concerned workman discloses that on 17-11-86 he reported for duty at 7 P.M. and Nepal Singh was on duty on that date. He enquired of Nepal Singh as to whether everything was alright and got an affirmative answer and as he was feeling vomiting tendency and he went to road side for taking some medicine and about 9.30 P.M. one Mahesh Singh and Ashok Choudhary, CISF Jawans while coming to his quarter met him on the road and told that dacoity had been committed at the magazine. Then all them came to the magazine and found the lock broken and after checking the record found that 7500 detonators were missing and he reported the matter to the Agent. By way of explanation he has stated that magazine clerks did not sit at the magazine throughout the shift as there was no proper arrangement for security. In the preliminary enquiry he took up the position that he tried to inform the Agent about his sickness but since the Agent was too busy he could not inform. In the domestic enquiry he has taken no such plea. Paramhans Singh, another magazine clerk stated in his testimony in domestic proceeding that he never remains in the magazine for full 8 hours and that he would keep the key with him at his residence which was quite near the magazine and the reason for not remaining in the magazine was that there was no arrangement for safety as anybody could come and do forcibly what they wanted to do. Ashok Choudhary, another Magazine Clerk stated that after distribution of detonators and making necessary entries and locking the room he used to leave the place of duty and tried to explain the situation by saying that this practice was obtaining since long. Thus, although it was the duty of the concerned workman as a Magazine Clerk to remain at his duty post throughout his duty hours, all the magazine clerks including the concerned workman used to leave the duty post after distribution of magazine, making entries in the record and locking up the magazine room. Unfortunately the theft of detonators was committed at the time when the concerned workman left the duty post without intimation to anybody due to his indisposition and he was caught napping. Nepal Singh, Night Guard was found by the CISF personnel gagged and his hands and feet tied up. The Enquiry Officer has come to the conclusion that the whole affairs was staged managed revealing a closed collusion between Nepal Singh and the concerned workman. Upon consideration of the evidence, I firmly hold that the Enquiry Officer over rest himself in drawing such conclusion as there was no vestige of evidence on record to indicate that the whole affair was stage

managed revealing a close collusion between Nepal Singh and the concerned workman. Upon consideration of the evidence, I firmly hold that the Enquiry Officer over rest himself in drawing such conclusion as there was no vestige of evidence on record to indicate that the whole affair was stage managed revealing a close collusion between Nepal Singh and the concerned workman. The Enquiry Officer was so much carried away by over jealousy that he concluded that this was not only an act of negligence but a deliberate act on their part to organise theft of detonators. There is not a shred of evidence to come to this conclusion. The Inquiry Officer is required to be fair and reasonable, he should not impose his own personal impression on the matter at issue. But in this particular case the Enquiry Officer has done so and that being the position his report suffers from lack of objectivity. Besides, it is also his finding that the concerned workman and Nepal Singh are also guilty of abetment of fraud and dishonesty in connection with the property of the employer. The misconduct of abetment of fraud and dishonesty in connection with the property of the employer is outside the pale of the chargesheet. This is yet another instance of total lack of objectivity and lack of application of the mind on the part of the Enquiry Officer.

10. Model Standing Orders for Industrial Establishments in Coal Mines is applicable to the workmen of the colliery. Clause 17 of the Model Standing Orders envisages disciplinary action for misconduct which includes habitual neglect of work as misconduct and not one isolated instance of neglect of work. There is no evidence on record that the concerned workman was guilty of habitual neglect of work. Technically he committed neglect of work on a single occasion, but there are extenuating circumstances to explain this neglect of work as the evidence reveals that the other magazine clerks also used to leave their duty post after distribution of detonators, making entries in the record and locking up the magazine room due to reasons of safety.

11. With regard to charge of abetment or attempt at abetment of theft there is no evidence on record to prove this charge.

12. It appears that Nepal Singh was also dismissed from service. He raised an industrial dispute and the management compromised the matter with him by reinstating him in service by paying him 50 per cent of wages from the period of his dismissal from service till the date of settlement with continuity of service for the purpose of gratuity.

The concerned workman was to retire from service shortly after the date of his dismissal from service. Considering all the facts and circumstances, I hold that the management was not justified in inflicting punishment of dismissal of the concerned workman from service. I think that the ends of justice will be met if the concerned workman was visited with punishment of reduction of 50 per cent of his wages from the date of his dismissal from service till his superannuation with continuity of service for the purpose of gratuity.

13. Accordingly, the following award is rendered the action of the management of North Tisra Colliery under Lodna Area No. X of M/s. BCCCL in dismissing Shri Mahesh Tiwari, Magazine Clerk from

service is not justified. The management is directed to pay the concerned workman 50 per cent of his wages from the date of his dismissal from service till he reached the age of superannuation with continuity of service for the purpose of gratuity.

In the circumstances of the case, I award no cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 22 मई, 1992

का. शा. 1563-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मै. भारत कोकिंग कोल लि. की कुया कोलियरी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (मं. 1) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012/100/82-डी-3(ए)/
आई.आर. (कोल-1)]

वी. के. वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd May, 1992

S.O. 1563.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Kuiya Colliery of M/s. B.C.C. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 14-5-92.

[No. L-2012(100)/82-D.3(A)/IR(Coal-I)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 105 of 1990

PARTIES :

Employers in relation to the management of
Kuiyo Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri S. K. Mitra,
Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri K. K. Bandyopadhyay, Advocate.

For the Workmen.—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, the 28th April, 1992

AWARD

By Order No. L-20012(100)/82-D.3(A)/I.R. (Coal-I) dated, the 26th April, 1990, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

“Whether the demand of the workmen of Kuiya Colliery Bastacolla Area of M/s. B.C.C. Ltd., P.O. Jharja, Dist. Dhanbad that the workmen mentioned in the Annexure should be regularised and treated as departmental workmen is justified? If so, to what relief are the concerned workmen entitled?”

LIST OF WORKERS

1. Panchanan Bouri
2. Peyarilal Yadav
3. Sitaram
4. Sokhilal Yadav
5. Malinda Bouri
6. Shobha Ram Yadav
7. Mogaram Bouri
8. Oeojanam Yadav
9. Anand Bouri
10. Suresh Rabidas
11. Amulya Bouri
12. Bisu Mahato
13. Panu Bouri
14. Somaru Yadav
15. Sankar Bouri
16. Sadan Yadav
17. Ramlal B. P.
18. Alma Manjhi
19. Sonalal Manjhi
20. Bhuchi Manjhi
21. Ajan Manjhi
22. Prabhu Manjhi
23. Kisun Manjhi
24. Lakhiya Manjhi
25. Chandu Manjhi
26. Sarada Manjhi
27. Ratia Manjhi
28. Lukhi Manjhi
29. Jhumri Manjhi
30. Alpi Manjhi
31. Fulmoni Manjhi
32. Bishundhari Bhuia
33. Hararam Khelower
34. Ramchandra Bhuia
35. Pitaambar Khelower
36. Chandu Manjhi
37. Ubra Sawra
38. Cheimoti Lal
39. Madan Prasad
40. Biswanath Parmanik
41. Sital Bhuia
42. Rameswar Manjhi
43. Naresh Bhuia
44. Sanichar Manjhi
45. Mohan Bhuia
46. Tirku Manjhi
47. Bandhu Bhuia
48. Jaleswar Manjhi

49. Lakhu Bhuia
50. Sarkar Manjhi
51. Lal Manjhi
52. Shyamlal Manjhi
53. Ganu Manjhi
54. Sarbeswar Bouri
55. Sonaram Manjhi
56. Sankar Bouri
57. Gopal Manjhi
58. Charku Bouri
59. Ram Manjhi
60. Pramod Kewat
61. Jatilal Manjhi
62. Sadhu Kewat
63. Malti Manjhi
64. Gokhul Rewari
65. Budhni Manjhi
66. Jagdish Bhuia
67. Sundari Manjhi
68. Khubhu Sawra
69. Mahabir Sarnakar
70. Bhadur Yadav
71. Pardeshi Rajwar
72. Manoharan
73. Prahled Yadav
74. Chandram Sawra
75. Bholu Prasad
76. Pardeshi
77. Haricharan Paswan
78. Nirmal Kr. Chakraborty.

2. The case of the sponsoring union, Bihar Colliery Kamgar Union, as disclosed in the written statement submitted by it on behalf of the concerned workmen, details apart, is as follows :

Panchanan Bouri and other concerned workmen have been working as permanent Truck Loaders within the precinct and premises of the Kuiya Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. since long with unblemished record of service. They have been performing the job of coal loader under the direct control and supervision of the management of Kuiya Colliery. All the implements necessary for execution of the job are being supplied by the management to the concerned workmen. Each of the concerned workmen has put in more than 240 days attendance in each calendar year as coal loader. The job of loading coal is a prohibited category of job. M/s. B.C.C. Ltd. has got permanent employees who have been doing the same nature of job of loading of coal at the same place along with the concerned workmen. Despite these facts the management has been disbursing the wages of the concerned workmen through intermediary and that too below the rates as prescribed by the Wage Board Recommendations and N.C.W.A.T. II, III & IV. The union served a strike notice on the management on 29-12-81 demanding regularisation of the concerned workmen and payment of wages at par with other permanent loaders. The conciliation proceedings ended in a failure, but the then Government, known for its anti-labour attitude and policy, did not either refer the dispute for adjudication nor did it reject the dispute for adjudication and kept it pending since 1982. The union and the workmen concerned represented to the Ministry and to different authorities for earlier reference of the dispute but without any effect. Seeing no other alternative the union filed representation before Hon'ble High

Court at Patna, Ranchi Bench, which was registered as C.W.J.C. No. 1330/83(R). The Hon'ble Court was pleased to direct the Government to pass proper order in the matter in accordance with law. Thereupon, the Central Government, appreciating the legal position, referred the dispute for adjudication. The demand of the workmen of Kuiya Colliery for regularisation of the concerned workmen in service and for treating them as departmental workman is legal and justified. The action of the management in not regularising the concerned workmen and not treating them as departmental workmen is illegal, arbitrary, unjustified and against the principles of natural justice. The management has not been paying them wages as per Wage Board Recommendations and NCWA, II, II and IV. The action of the management is vindictive, discriminatory and smacks of anti labour policy. The management has not procured any registration from the competent authority for engaging the concerned workmen as contractor's workmen nor had the alleged contractor procured any licence for engaging the concerned workmen in the job of coal loading. Disbursement of wages through different intermediaries is nothing a legal camouflage. In the circumstances, the union has demanded that the concerned workmen be regularised in service as departmental workmen with retrospective effect and be paid wages as per NCWAs. The union has submitted that some inaccuracies have been crept in the annexure to the reference containing the names of some of the concerned workmen; it has submitted the correct names with a prayer for acceptance of the same.

3. The case of the management of Kuiya Colliery of M/s. BCCL as appearing from the written statement-cum-rejoinder, briefly stated, is as follows :

The workmen covered by the present reference whose cause is being sponsored by the union are not the workmen of M/s. BCC Ltd. for the management of Kuiya Colliery of M/s. BCC Ltd. Hence, the instant dispute cannot be called an industrial dispute within the meaning of Section 2(K) of the Industrial Disputes Act and the persons covered by the order of reference are not workmen within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. The Central Government has not considered the basic fact as to whether the persons covered by the reference were the workmen of the management of Kuiya Colliery while referring the present dispute for adjudication. There exists no relationship of employer and employee between the management and the concerned persons. M/s. BCC Ltd. is a Govt. Company within the meaning of Section 617 of the Companies Act, 1956. Kuiya Colliery is one of the collieries of M/s. BCC Ltd. Fertiliser Corporation of India Ltd. is also registered under the Companies Act, 1956. M/s. BCC Ltd. and the FCI entered into an agreement on 19-1-1978. FCI Ltd. requested M/s. BCC Ltd. for supply of coal for its consumption in power house and M/s. BCC Ltd. agreed to make the supply of coal to FCI Ltd. from its three collieries, namely, B. Jaccolla, Bera and Kuiya on the basis of the terms and conditions as contained in the agreement. The agreement was valid upto 4th April, 1982. Accord-

ing to the agreement M/s. BCCL had the obligation to sell coal, but it was the obligation of the FCI to lift the coal from the sources and to arrange for transportation. FCI Ltd. appointed two contractors, namely, Jindal Roadways and M/s. Ramlal Agarwal for transporting the coal to be lifted from Kuiya Colliery and also from other collieries. The contract between the FCI Ltd. and the transport contractors clearly stipulate the terms and conditions of payment and other conditions of service of workers engaged by the contractors. Some of the relevant clauses of the contract between FCI and its transport contractors are gleaned herein below :

"Clause 20—Liability under laws concerning Factory :

The contractor shall at all times indemnify the Fertilizer Corporation of India Ltd., Sindri Unit, Sindri against claims that they be raised under the Workmen's Compensation Act or the Factory's Act and such other relevant Acts as may be applicable for working inside or outside the factory during the tenure of this contract.

Clause 21—Compliance of statutory obligations :

The contractor shall observe all statutory laws and rules as may be applicable, such as Factory Act, Workmen's Compensation Acts, etc. for the time being in force. Any accident that may occur during the tenure of the contract shall be his responsibility and he shall pay such compensation as may be required under the Act. He should also report in writing all accident so occurring within the factory premises (Minor or major) to the FCI Management forthwith. The management reserves the right to pay the injured persons compensation in the first instance which shall be deducted subsequently from the contractor's bills.

Clause 22 : The contractor shall abide by all other regulations in force and subject to FSI and Provident Fund deduction as given below :

By virtue of the Employees Provident Fund Amendment Act 1963 the employees employed by or through contractor have become entitled to P. F. Benefits as available to an eligible worker under statutory scheme as per Govt. of India notification No. S.O. the 27th November, 1963 from the date on which the said act shall come into force. Under the said Act employees engaged by the contractor in the above job are to be given the benefits of P. F. The contractor will also be subject to the conditions detailed in Annexure—II to Dy. Chief Engr. (Material Handling Plant) FCI Sindri Unit|Addl. Supdt. (Power House), FCI, Sindri C.E. (Chem), SMP latest by 6th of each month. In case of non-compliance, FCI, Sindri will retain 16.2% of the contractors payment towards employees and employers' contribution. Unless exemption certificate from PF Commissioner or his authorised agent is given inspection fee @ 0.9% or the rate as recommended will be recovered.

Clause—28—Submission and payment of bills :

Bills in duplicate duly supported by certificate of weighment for qualities transported issued by the Dy.

C.E. (MH Plant) Addl. Supdt. (PH), CM (Chem) SMP or their authorised nominee shall be submitted to our F.M. FCI, Sindri and payment will be made against bills on 15 days basis subject to IT and other statutory deductions. The bills should accompany labour payment certificate/exemption certificate duly endorsed by bill forwarding authority.

Clause—29—The successful tenders will have to intimate the date place and time of payment to their workers each month in respect of each work to Chief Personnel Officer, well in advance to observe the provisions of Minimum Wages Act and other labour acts.

30. The contractor will be held liable to FCI for any act of commission and omission likely to deter the provisions of laid down in the above mentioned clauses, thereby causing damage any loss or inconvenience to the F.C.I. Ltd."

The above terms clearly indicate that the workers engaged by the contractors in the transportation of coal were the basic responsibility of the contractors in all respects. Their principal employer would be F.C.I. and not M/s B.C.C. Ltd. Therefore, under the provisions of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, if any action is warranted including payment of wages and absorption in service, it is either the responsibility of the contractor of the F.C.I. Ltd. Persons covered by the present reference were never engaged by the management of Kuiya Colliery and it was wholly an internal arrangement between the F.C.I. Ltd. and the Transporters to engage coal loaders.

4. In rejoinder to the written statement of the management, the union has asserted that the present dispute is an industrial dispute within the meaning of Sec. 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947 and the concerned workmen covered by the present reference are workmen within the meaning of Sec. 2(s) of the said Act. The appropriate Govt., while making the reference under Sec. 10 of the Industrial Disputes Act, had considered the basic fact and on consideration of the basic fact the present reference has been referred for adjudication. The union has also asserted that there exists employer-employee relationship between the management and the concerned workmen. It has been reiterated that the concerned workmen have been performing the work of loading coal within the precinct and premises of Kuiya Colliery and they have been performing the duties of loading coal into trucks. The main function of Kuiya Colliery and other collieries of M/s. B.C.C. Ltd. is to raise coal and sell to different buyers, such as Steel Plant, Power Plant etc. M/s. B.C.C. Ltd. is despatching the coal raised from the collieries to respective buyers through railway wagons or through trucks. The concerned workmen are not aware of any agreement between the F.C.I. Ltd. and B.C.C. Ltd. nor the same is relevant in so far as the concerned workmen are concerned. The union has asserted that it is absolutely false to allege that F.C.I. Ltd. had appointed two contractors, namely, Jindal Roadways and Ramlal Agarwal for transporting coal from Kuiya colliery and also from other collieries. The concerned workmen have got no concern with the so called

contractor. It has been alleged that the so-called agreement and paper arrangement are nothing but legal camouflage in order to deprive the poor workmen of their legitimate wages and regularisation in service. The so-called contractor did not appoint the concerned workmen for the purpose of loading of coal nor did the so-called contractors supervise the job of the concerned workmen. Clauses of the so-called agreement quoted by the management in the written statement have got no relevancy for the purpose of adjudication of the present dispute and so-called agreement is emphatically denied. It is false to allege that the principal employer is F.C.I. Ltd. and not M/s. B.C.C. Ltd. The sponsoring union has raised the dispute against the Agent of the colliery who is the owner of the colliery. As per Mines Act and as per the provision of the Standing Order also the Agent is responsible. The written statement of the management has been verified and signed by Shri Ram Narain Singh, Personnel Manager of Bastacolla Colliery, who has got no authority, legal or otherwise, to verify or to sign the written statement on behalf of the agent of Kuiya Colliery and on behalf of M/s. B.C.C. Ltd. as well.

5. In rejoinder to the written statement of the sponsoring union, the management has reiterated the fact that in terms of an agreement M/s. B.C.C. Ltd. agreed to make supply of coal to F.C.I. Ltd. from its three collieries, namely Bastacolla, Bera and Kuiya. The agreement was valid upto 4-4-82. According to the said agreement the management of M/s B.C.C. Ltd. had obligation to sell coal, but it was the obligation of the F.C.I. Ltd. to lift the coal from the sources and to arrange for transportation. The F.C.I. Ltd. in turn appointed two Contractors, namely, M/s. Jindal Roadways and Ramlal Agarwal for transportation of coal to be lifted from Kuiya Colliery and other collieries. The contract between M/s. F.C.I. and transport contractors clearly stipulates the terms and conditions of payment as also other conditions of service M/s. F.C.I. Ltd. Sindri stopped taking coal on the basis of the said agreement from Kuiya colliery from 4-4-82 and as a result thereof there was no job for workmen engaged by the said two contractors who were engaged by F.C.I. Ltd. to lift the coal on the basis of agreement. The management has denied that the concerned workmen had put in more than 240 days attendance as coal loaders of the management. Since the attendance of the workmen were maintained by the two contractors as aforesaid and payments were made to the concerned workmen by the said two contractors, the management of Kuiya colliery has no knowledge whatsoever about the attendance of the concerned workmen. Coal was loaded far away from the premises of the mine and therefore it cannot be said that the job of loading was prohibited category of job. The management has denied that all the necessary implements for execution of the job were being supplied by the management. The management has further denied that the permanent employees of the colliery are also doing the same nature of job at the same place alongwith the concerned workmen or that the work of the concerned workmen was being supervised by the management. As a matter of fact, the management had no control and/or supervision over the workmen. The management has also denied that payment

to the concerned workmen were made through different intermediaries as alleged. In the circumstances, the prayer of the union to answer the reference in favour of the workmen by directing the management to regularise the workmen as departmental workmen with retrospective effect and arrears of wages is not maintainable.

6. The union, in support of its demand, has examined two of the concerned workmen, namely, WW-1 Nirmal Kumar Chakraborty and WW-2 Gokul Rawani and laid in evidence a number of documents which have been marked Exts. W-1 to W-7.

The management, in order to refute the demand of the union, has examined three witnesses, namely, MW-1 Rabindra Kumar Singh, presently working as Manager, Kuiya Colliery of M/s. B.C.C. Ltd., MW-2 Satyanarain Agarwal, Surface Supervisor of Kuiya Colliery and MW-3 S. C. Rawani, P.O.'s Clerk of Kuiya Colliery. Besides, the management has laid in evidence a sheaf of documents which have been marked as Exts. M-1 to M-4 and certain other documents which have been marked 'Y' to 'Y-6' for identification.

7. The case of the sponsoring union, in essence, is that the concerned workmen have been working as truck loaders of coal in Kuiya Colliery of M/s. BCCL within the precinct and premises of the said colliery under the supervision and control of the management and with the work implements supplied by the management and in the process all of them have put in attendance for more than 240 days in every calendar year. It is the further case of the union that the regular workmen of the management have been performing the same nature of job and the regular workmen have been getting wages as per N.C.W.As, while the concerned workmen have been getting payment of wages much below the rates fixed by Wage Board Recommendations or N.C.W.As and that their wages are being disbursed through intermediaries.

The case of the management is complete refutation of the claim of the sponsoring union for the concerned workmen. The case of the management, in short, is that M/s. B.C.C. Ltd. was having an agreement with the F.C.I. Ltd. for supply of coal and the said agreement was valid upto 4-4-82. According to the said agreement, M/s. B.C.C. Ltd. had the obligation only to sell the coal, but it was the obligation of F.C.I. Ltd. to lift the coal from sources and to arrange for transportation and in the process F.C.I. Ltd. appointed two contractors, namely, M/s. Jindal Roadways and M/s. Ramlal Agarwal for transporting coal and these contractors engaged the concerned workmen. According to the management of Kuiya Colliery, it has got nothing to do with the concerned workmen and there exists no relationship of employer and employees between the management of Kuiya colliery and the concerned workmen.

8. WW-1 Nirmal Kumar Chakraborty, one of the concerned workmen, has stated on oath before me that since 1978-79 they have been working in Kuiya Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. as Truck loaders within the precinct and premises of Kuiya colliery, and that in the course of performance of duties they have been leading coal raised from Kuiya colliery and dumped

at depot No. 22 by the workmen of the management with the help of dumper, on trucks. Nirmal Kumar Chakraborty has further stated that they have been doing the job of coal loader which is permanent nature of job under the supervision and control of the representative of the management of the colliery and with the work implements supplied by the management and all of them have put in attendance for 240 days or more in every calendar year. He has asserted that they have been performing the job of truck loaders alongwith regular workmen of the management and while regular workmen of the management have been getting Group-III wages as per NCWA they have been getting payment at the rate of Rs. 20 per head per day for loading 4½ tonnes of coal per head per day. WW-2 Gokul Rawani, another concerned workman, has lend firm support to the testimony of Nirmal Kumar Chakraborty by stating that the concerned workmen including him have been working as truck loaders of coal in Kuiya colliery for the last ten years or more and they have been working in Depot Nos. 21 and 22 of the colliery. He has also supported Nirmal Kumar Chakraborty by stating that they have been performing their job under the direct control and supervision of the representative of the management of Kuiya colliery with work implements supplied by the management and in the process they have put in attendance for 240 days or more in every calendar year. He has also stated that they have been performing the same nature of job alongwith the regular workmen of the colliery and the same representatives of the management exercise supervision and control over the job of regular workmen and their jobs and that while the regular employees of the management have been getting Group-III wages they have been getting Rs. 20 as wages per head per day for loading 4½ tonnes coal per head per day.

In cross-examination, both of them have been grilled on the point as to whether they possess any letter of appointment from the management or not. I consider that the issue of the concerned workmen having any letter of appointment or not is not of much moment because it has not been claimed by the union that the concerned workmen are having letters of appointment. Besides, had the concerned workmen been favoured with letters of appointment, the question of the present dispute would not probably have arisen. Anyway, evidence of these two witnesses with regard to performance of duties by the concerned workmen with the precinct and premises of Kuiya colliery for long under the direct supervision and control of the representative of the management and with work implements supplied by the management and in the process put in attendance for 240 days or more in each calendar year by each of the concerned workmen has not been assailed in cross-examination.

Nirmal Kumar Chakraborty has proved three Attendance-cum-Wage Registers marked Exts. W-2, W-2/1 and W-2/2. These attendance-cum-wage registers relate to the years 1981, 1982 and 1986. Nirmal Kumar has stated in his testimony that they could procure these registers from the management which bear the signature of Naresh Sharma, Loading Babu of Kuiya colliery marked Exts. W-2/1a series, signature of Satyanarain Agarwal, another Loading

Babu of the colliery Ext. W-2/a/1 and the signatures of Dhiren Halder, Magazine Clerk of the colliery Exts. W-2/1/a and W-2/2/a series. The management has examined Satyanarain Agarwal as MW-2, who has been working in Kuiya Colliery as Loading Supervisor although designated as Surface Supervisor to explain his signature. He has identified his signature on the register and offered the explanation that he put his signature on the register at the behest of the Munshi of the contractor as there was some dispute before over payment of wages. It has remained incomprehensible how he could put his signature on the register when there was no specific direction in that behalf by the management. Even so, it has remained un-explained as to how and why signature of this witness could set at rest the dispute between the contractor and his alleged workmen over payment of wages. In my view, it is a laboured attempt on the part of this witness to explain his signature on this register. The management has not explained the circumstances under which Naresh Sharma, Loading Babu of Kuiya colliery put his signatures on these registers. The management by adducing oral evidence has sought to explain the signatures of Dhiren Halder on the registers by stating that it was no part of the duty of Magazine Clerk to put his signature on the attendance-cum-wages registers. Even so, Dhiren Halder would have been the best witness to explain the position, but he has not been examined with the result that we are drifted away to grope in the dark. MW-3 S. C. Rewani, Clerking to the P.O. of the colliery, has stated that the Attendance Register Ext. W-2 is not the Attendance Register or Wage Register of M/s. BCCL. According to this witness, he got his employment in the colliery before nationalisation, but he has got no letter of appointment. His evidence discloses that Meghraj Agarwal appointed him in the colliery in the post of Munshi while Parmeshwar Agarwal was the owner of the colliery. He has not explained under what authority he was appointed by Meghraj Agarwal in the colliery, nor has disclosed the connection Meghraj Agarwal was having with the colliery. His evidence discloses that he is P.O.'s Clerk and Pay Clerk rolled into one and has to perform manifold duties although there are 69 other clerks in the colliery. He seems to be an omnibus witness and I am not at all impressed by his evidence. It is pertinent to mention here that the attendance-cum-wage registers bear the names of all the concerned workmen.

9. The management has filed some wagesheets and payment-sheets for bonus (Exts. M-3 series and M-4) to prove that the names of the concerned workmen do not appear in these documents. These documents relate to regular workmen of the colliery. It has not been claimed by the sponsoring union that the management has treated the concerned workmen as regular workmen of the colliery. On the other hand, the union has complained that although the management has been taking work from the concerned workmen as truck loaders alike the regular workmen, it has been denying the status of regular workmen to the concerned workmen and in the process has been paying wages to the concerned workmen much below the normal rates as per Wage Board Recommendations and N.C.W.As. Hence, production of these wage-sheets and payment-sheets

for bonus does not at all improve the case of the management.

10. It is the firm case of the management that M/s. B.C.C. Ltd. was having an agreement dated 19-4-1978 with the F.C.I. Ltd. in terms of which it was the obligation of M/s. B.C.C. Ltd. to sell coal but it was the obligation of F.C.I. Ltd. to lift the coal from sources and to arrange for transportation and that F.C.I. Ltd. appointed two contractors, namely, M/s. Jindal Roadways and M/s. Ramlal Agarwal for lifting coal and for transportation of coal. The management has produced the agreement which has been marked 'Y' for identification. It does not bear the signature of the parties to the agreement. None of the witnesses for the management has attested to the fact of execution of agreement in his presence. In such circumstances, the document was marked 'Y' for identification. Even so, one poignant fact remains and that is that it does not disclose any provision for lifting of coal by F.C.I. Ltd. Then again, the management produced some letters of allocation marked 'Y-3', 'Y-4', 'Y-5' and 'Y-6' which simply disclose authorisation for transportation issued by the F.C.I. Ltd. The management has stated in its written statement about the contract between F.C.I. Ltd. and its contractors. The relevant clauses of the contract have been copiously gleaned in the written statement. But the real substance that matters is missing : the agreement between F.C.I. Ltd. and its two contractors have not been produced at all.

The management has produced certain letters of M/s. Jindal Roadways requesting the management of Kuiya Colliery to arrange for supply of coal to the trucks for transporting the same to F.C.I. Ltd. The truck numbers have been mentioned herein (Ext. M-1 series). The management has produced one allocation letter (Ext. M-2) issued by M/s. F.C.I. Ltd. intimating the General Manager of M/s. B.C.C. Ltd. for allocation of coal for Power House through transporting contractors which includes the name of M/s. Ramlal Agarwal and M/s. Jindal Roadways (Ext. M-2). These documents do not lead to the conclusion that the concerned workmen are the workmen of the contractors nor do these documents indicate that the concerned workmen have been performing the job of lifting the coal as the employees of the contractors.

On the other hand, the sponsoring union has produced photostat copies of some Form-IVA Registers maintained under the provision of Payment of Wages Act and Rules. These Form IVA registers kept under Rule 17(1) of the Payment of Wages (Mines) Rule, contain the names of some of the concerned workmen. MW-1 Rabindra Kumar Sinha has been working as Manager of Kuiya Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. since 9-7-1990. He has admitted that the management has been maintaining Form IVA as per Payment of Wages Act in respect of wagon loaders and that the Loading Babus maintain Form IVA registers at the loading point under the said Act. These Form IVA Registers (Exts. W-3 series) establish the fact that some of the workmen were engaged on the job of loading coal. Under Rule 17(1) of the Payment of Wages (Mines) Rules the employer is res-

possible to maintain these registers in respect of piece rated workmen. If the management of Kuiya Colliery and for the matter of that M/s. BCCCL have got no connection with the concerned workmen that the names of some of the concerned workmen should not have appeared in these registers.

MW-1 Rabindra Kumar Sinha, Manager of Kuiya Colliery, is the principal witness for the management in this case. In his examination-in-chief, he has dwelt at length with regard to the modalities of supply of coal to F.C.I. Ltd., although the management has claimed in the written statement that an agreement with the F.C.I. Ltd. was valid upto 4-4-1982. The evidence of this witness indicates that the management of the colliery even now sells coal to F.C.I. Ltd. (Ext. W-7). He had admitted in cross-examination that alike other collieries of M/s. B.C.C. Ltd. it is the main function of Kuiya Colliery to raise coal and to supply to the customers and that the management of the colliery despatches the coal by trucks and also by railway wagons, but mostly by trucks. According to him, the workmen who load coal manually into railway wagons are the workmen of the colliery, and that the management despatches coal to different parties including F.C.I. Ltd. by trucks and the workmen of the colliery also load coal on trucks belonging to different parties and that Loading Babus supervise the work of the workmen of the colliery. He has also admitted that the management will not allow any contractor or any other person to load coal into trucks or railway wagons as per his sweet will and it is the business of the workmen of the colliery deployed at the loading point to see whether coal has been loaded as per allotment and loading Inspectors and Supervisors are engaged to see that coal is loaded into trucks or railway wagons according to gradation and the management will not allow any customer to employ his workmen for loading coal into trucks. He has also admitted that it is the duty of the management to exercise supervision over loading of coal into trucks or railway wagons and that in a running mine raising of coal and loading of coal are permanent nature of job. He could not say that if the concerned workmen have been loading coal into trucks from the loading point in the vicinity of 21 and 22 Pits of Kuiya Colliery. Thus, the evidence of this witness reveals some basic facts : that loading of coal is permanent nature of job and that loading of coal into trucks by the workmen is supervised by the management.

11. Thus, the evidence on record fully establishes the position that the concerned workmen have been engaged on the job of loading of coal into trucks for considerable number of years and that their job is being supervised and controlled by the management and the management has been supplying the concerned workmen with work implements. The evidence on record further establishes that loading of coal is permanent nature of job and as such this is an integral part of the works of the establishment of the management and that the concerned workmen have been performing their job in the place of work belonging to the management. Evidently, loading of coal is further purpose of establishment of the management and the concerned workmen are broadly under the control of the establishment of the management. In order to de-

termine the question of relationship of employer and employee the true test, as pointed out by Hon'ble Supreme Court, is that where a worker or group of workers labour to render service which form integral part of the services of another and utilised as such, then that other is, in fact, the employer, even though the employment is brought about by or through some other person acting under the supervision and control of the former. 1978 Lab. I.C. 1264 (Hussain-bai VR. The Alach Factory Tezhilali Union and others) followed in 1991 Lab. L.C. 1062 (Calcutta) (Divisional Railway Manager, Eastern Railway VR. Satyajit Majumdar and others). This being the position, I come to the conclusion that the management of Kuiya Colliery is the real employer of the concerned workmen and consequently it follows that there exists relationship of employer and employees between the management of Kuiya colliery and the concerned workmen.

12. By Notification dated 1-2-1975, the Central Government, after consultation with the Central Board prohibited employment of contract labour in the works specified in the schedule in all coal mines. The schedule is as follows :

- “1. Raising or raising-cum-selling of coal;
2. Coal loading and unloading;
3. Over burden removal and earth cutting;
4. Soft coke manufacturing;
5. Driving of stone drifts and miscellaneous stone cutting under ground.”

It appears from the Notification that coal loading and un-loading by employment of contract labour has been prohibited by the Central Government. M/R. BCC Ltd. is a public sector Company and the Kuiya Colliery is a part and parcel of that company. It does not speak well of a Government company to violate the prohibition imposed by the Central Government for employment of contract labour on the job of loading and un-loading of coal. This I state with respect to the contention of the management that the concerned workmen are the workmen of contractors.

13. Wagon loaders are entitled to Group-III Wagon. But according to the evidence of WW-1 M Kumar Chakraborty and WW-2 Gokul Rawani, the concerned workman have been getting wages of Rs. 20 per head per day for loading 4-1½ tonnes of coal per head per day. In my view, since the concerned workmen are held to be the employees of Kuiya Colliery, they are entitled to Group-III wages.

I cannot ignore the position that the entire coal industry has been passing through a critical phase and in the circumstances it will be very hard for the management if the demand of the union for regularisation of the services of the concerned workmen and payment of proper wages to them from the date of their employment is allowed. In my view, the management should regularise the concerned workmen in service and pay them Group-III wages with effect from the date of the present reference i.e. 26-4-1990 minus the wages already paid to them.

14. It appears that some inaccuracies have crept in mentioning the names of some of the concerned work-

men in the annexure to the reference. The union has corrected the names in the written statement. WW-1 Nirmal Kumar Chakraborty has also testified that some inaccuracies have crept in mentioning the names of some of the concerned workmen in the annexure to the reference. He has mentioned the correct names in his evidence. This being so, a separate annexure be prepared and marked as Annexure 'A' containing the correct names of the workmen involved. The management is directed to regularise these workmen as per Annexure 'A' and to pay them back wages as mentioned above.

15. Accordingly, the following award is rendered the demand of the workmen of Kuiya Colliery Bastacolla Area of M/s BCC Ltd., P.O. Jharia, Distt. Dhanbad, that the workmen mentioned in Annexure 'A' should be regularised in service and treated as departmental workmen is justified. The management is directed to regularise these workmen in service and pay them Group-III wages as per NCWA IV with effect from 26-4-90 less wages already drawn by them.

In the circumstances of the case, I award no cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer

ANNEXURE 'A'

1. Panchanan Bouri
2. Sitaram Mahato
3. Malinda Bouri
4. Anand Bouri
5. Peyarilal Yadav
6. Sokhilal Yadav
7. Sobha Ram Yadav
8. Deoanand Yadav
9. Mogaram Bouri
10. Suresh Rabidas
11. Amulva Bouri
12. Bisu Mahato
13. Panu Bouri
14. Somaru Yadav
15. Sankar Bouri
16. Sadan Yadav
17. Ramlal B. P.
18. Alma Manjhi
19. Sonalal Manjhi
20. Bhuchi Manjhi
21. Ajan Manjhi
22. Prabhu Manjhi
23. Kishun Manjhi
24. Lakhiva Manjhi
25. Chandu Manjhi
26. Sarada Manjhi
27. Ratia Manjhi
28. Lukhi Manjhi
29. Jhumri Manjhi
30. Aloj Manjhi
31. Fulmoni Manjhi
32. Bishundhari Bhuiya
33. Hararam Khelowar
34. Ramchandra
35. Pitambar Khelowar
36. Chandu Manjhi
37. Ubra Sawra
38. Cheitmoti Lal
39. Madan Prasad Rewani
40. Biswanath Parmanik
41. Sital Bhuiya
42. Rameswar Manjhi
43. Naresh Bhuiya

44. Sanichar Manjhi
45. Mohan Bhuiya
46. Tirku Manjhi
47. Bandhu Bhuiya
48. Jaleswar Manjhi
49. Lakhu Bhuiya
50. Sarkar Manjhi
51. Lal Manjhi
52. Shyamlal Manjhi
53. Ganu Manjhi
54. Sarbeswar Bouri
55. Sonaram Manjhi
56. Sankar Bouri
57. Gopal Manjhi
58. Charku Bouri
59. Ram Manjhi
60. Pramod Kewat
61. Jatilal Manjhi
62. Sadhu Kewat
63. Malti Manjhi
64. Gokhul Rowani
65. Budhni Manjhi
66. Jagdish Bhuiya
67. Sundari Manjhi
68. Khubhu Sagar
69. Mahabir Sarnakar
70. Bahadur Yadav
71. Pardeshi Rajwar
72. Manoharan Chakraborty
73. Prahlad Yadav
74. Chandram Sawra
75. Bhola Prasad Mahato
76. Pardeshi Prasad
77. Haricharan Paswan
78. Nirmal Kumar Chakraborty.

नई दिल्ली, 22 मई, 1992

का. आ. 1564 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20 मई, 1992 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-42011/11/87 जी -II (बी)]

बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd May, 1992

S.O. 1564.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Orissa, Bhubaneswar as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Warehousing Corporation, and their workmen, which was received by the Central Government on 20-5-92.

[No. L-42011/11/87-D. II(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA,
BHUBANESWAR

PRESENT :

Sri R. K. Dash, LL.B.,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal,
Orissa, Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 41 OF 1988
(CENTRAL)

Dated, Bhubaneswar, the 8th May, 1992.

BETWEEN :

The Management of Central Warehousing
Corporation, Jaipur Road, Cuttack.

....First Party-management.

AND

Their workmen represented through F.C.I.
Workers' Union, 58, Diamond Harbour
Road, Calcutta 23.

....Second Party-workmen.

APPEARANCES :

Sri M. K. Kandaswamy, Sr. Asstt. Manager,
Central Warehousing Corporation, Bhubanes-
war.—For the first party-management.

None.—For the workmen.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred upon them by clausd (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 and by their order No. L-42011/11/87-D.II(B)ID dated 11-8-88 have referred the following dispute for adjudication by this Tribunal :—

“Whether the demand of the workmen represented by FCI Workers' Union, Calcutta that they should be treated to be the employees of the C.W.C. Jaipur Road with effect from 9-8-86 is lawful and justified? If so, what relief the workmen are entitled to?”

2. Briefly stated the case of the workmen numbering 45 as mentioned in the list attached to the reference is that initially the management of Central Warehousing Corporation, Jaipur Road was carrying out handling of foodgrains at the depots as well as railway siding of Jaipur Road through workers engaged by contractors. For carrying out the aforesaid work on contract basis neither the contractors had licence nor the management obtained registration

certificate as provided under the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970. In such a situation the workrs are likely to be treated as the employees of the management. While the contract system of work was being carried on, one of the contractors suddenly left the work for which the workers demanded to regularise their services equal to that of the other departmental workers. As the total work had been disrupted, the Depot Manager, Jaipur Road having decided to do away with the contract labour system employed these workmen who had been working since September, 1986 and made payment of their wages directly. Subsequently, all of a sudden the Depot Manager took another decision to revoke the contract system and pressurised these workmen to work under a contractor who had equally no licence. This gave rise to a dispute which was admitted to conciliation before the Asstt. Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar. As the dispute could not be resolved he submitted a failure report to the Government of India on receipt whereof the present reference was made to adjudicate the dispute.

In sum and substance, the case of the workmen is that they should be treated as the employees of the Central Warehousing Corporation, Jaipur Road with effect from 9-8-86.

3. It is needless to recapitulate the case of the management as because at the time of hearing the workmen, on whom onus lies to prove their case, did not choose to lead evidence. When it is pleaded by them that they had been directly employed by the management since September, 1986 it was obligatory on their part to substantiate the same by leading acceptable evidence. That having not been done I have no other option but to answer the reference in negative.

When the case was fixed for passing award the workmen through their union sent a petition through post asking this Tribunal to stay its hand in disposing of the proceeding because of the reason that the self-same matter concerning the employees of 65 depots is now pending before the National Industrial Tribunal, Bombay for adjudication. The Industrial Disputes Act does not envisage that the Industrial Tribunal is competent to stay a proceeding pending before it on any ground whatsoever. In this view of the matter, the prayer of the workmen to stop further proceeding does not merit any consideration.

4. In view of my discussions made above, I hold that the demands of the workmen represented through F.C.I. Workers' Union, Calcutta that they should be treated as the employees of the Management with effect from 9-8-86 is not legal and justified.

The reference is thus answered accordingly. Dictated and corrected by me,

R. K. DASH, Presiding Officer.

